विचार
नवभारत टाइम्स
नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। सोमवार, 20 जनवरी 2025

खुले मन से हो बात

केंद्र सरकार की पहल के बाद 26 नवंबर से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने आखिर चिकित्सा सहायता लेना स्वीकार कर लिया है। यह फैसला सभी पक्षों के लिए राहत बनकर आया है। हालांकि अभी यह राहत तात्कालिक ही है क्योंकि यह साफ नहीं हो पाया है कि बातचीत के इस प्रस्ताव से किसान संगठनों की मांगों पर बना गतिरोध दूर होगा या नहीं और होगा तो कैसे।

डल्लेवाल का अनशन

आंशिक सहमति | यह इस बात से भी स्पष्ट है कि किसान नेता डल्लेवाल ने चिकित्सा सहायता लेना मंजूर करते हुए भी अनशन जारी रखने का ऐलान किया है। अभी भी उनका यह रुख कायम है कि मांग पूरी होने तक उनका अनशन चलता रहेगा। ध्यान रहे, उम्र के आठवें दशक में चल रहे डल्लेवाल कैंसर पेशंट भी हैं। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि जल्द से जल्द अनशन समाप्त कर वह डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक समय पर दवाएं और भोजन लेना शुरू करें।

मांगों पर गतिरोध | किसान संगठनों की मांगों को लेकर गतिरोध लंबे समय से बना हुआ है। जहां किसान मुख्य तौर पर सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी मांग रहे हैं वहीं सरकार बार-बार कह चुकी है कि यह व्यावहारिक नहीं है। दोनों पक्षों के पास अपने तर्क हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि किसी बुजुर्ग नेता का अनशन पर बैठना भावनात्मक दबाव भले बनाए, किसानों की मांग को ज्यादा तर्कसंगत और न्यायोचित नहीं बनाता।

सुप्रीम कोर्ट का संयम | सरकार इस मांग को स्वीकार करने में अपनी असमर्थता जताते हुए जो इन्फ्रास्ट्रक्चर का अभाव, वित्तीय संसाधनों की कमी और खाद्य पदार्थों के मूल्य में असाधारण बढ़ोतरी की आशंका जैसे कारण गिनाती है, उन्हें सीधे तौर पर खारिज नहीं किया जा सकता। शायद यही वजह रही कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में न तो कोई आदेश जारी किया और न ही इन मांगों के मेरिट पर कोई सीधी टिप्पणी की।

बीच की राह | वैसे देखा जाए तो किसान संगठन शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग पर जोर दे रहे हैं जिसका उन्हें अधिकार है। ऐसे में इकलौता रास्ता यही बचता है कि दोनों पक्ष खुले मन से बातचीत के जरिए बीच की कोई राह निकालें। उम्मीद है कि ताजा पहल हालात को उस तरफ ले जाएगी।

चक्र-व्यू

कला को कैसे देखें

राहुल पाण्डेय

पिछले दिनों मैं अपने एक मित्र के साथ वीएस गायतोंडे की एक पेंटिंग देख रहा था। 1988 में बनाई इस पेंटिंग को गायतोंडे साहब ने कोई नाम नहीं दिया था। इसमें दो रंगों के अलग-थलग पड़े अनमने से कॉम्बिनेशन थे, जिनमें कभी कोई आकार उभरता है तो कभी मन में तेज चलता अंधड़। हम इसके टेक्सचर पर बात कर रहे थे कि कैसे गायतोंडे साहब ने इसे बनाया होगा। कला की दुनिया में वीएस गायतोंडे अपने महीन और रहस्यमय टेक्सचर के लिए जाने जाते हैं। वह कैसे इन्हें आकार देते थे, यह लगभग रहस्य ही है। कोई कहता है कि कलर करके उसे ब्लेड से काटते थे तो कोई कहता है कि कुछ चिपकाकर कलर करके उसे धागे से मांजते थे। इंडियन मॉडर्न आर्ट की दुनिया में गायतोंडे के बनाए टेक्सचर, मॉडल माने जाते हैं, जो एक साथ मन, आध्यात्मिकता, इंझंझावात और शांति पेश करते हैं। कई लोग कहते हैं कि वह जापानी कला विचारों से प्रभावित थे, और उनकी पेंटिंगों में जो बिंदु दिखता है, वह वहीं से आया है। मेरे मित्र भी जापान पर ही टिके थे। मेरा कहना था कि हो सकता है जापान से उन्होंने चिंतन-मनन की विशेष शैली सीखी हो, लेकिन यह बिंदु तो हमारा अपना है। भारत बिंदुओं का देश है। हमारी संस्कृति में यहीं से शुरुआत मानी गई है और यहीं पर अंत।

हम दोनों गायतोंडे साहब की इस पेंटिंग के टेक्सचर से लेकर बिंदु सभ्यता की बात कर ही रहे थे कि पीछे से एक और सज्जन आ गए। पूछने लगे, ये क्या है? मैंने कहा, पेंटिंग है। छूटते ही बोले, ये कैसी पेंटिंग है? इसमें तो बस वही टिकुली यानी बिंदी दिख रही है। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मेरे साथी के यह पूछने पर कि समझना क्या चाहते हो, उनका कहना था कि कुछ पेड़-पौधे दिखते, कुछ सूरज-बादल होता। और नहीं तो कुछ पहाड़-झरने होते तो बात समझ में आती। ये क्या यहां-वहां जो मर्जी रंग लगा दिए, मन हुआ तो एक, नहीं तो दो-तीन टिकुली लगा दिए और हो गई पेंटिंग। उनकी बात सुनकर मैं और मेरे साथी अभी तक हैरान हैं। हमें दो बातें एकदम नहीं समझ आ रहीं। कैसे कोई ऐसे कह सकता है? और जो ऐसे कह सकता है, उसे कैसे समझाएं?

एकदा

ग़फ़्फ़ार की मां

खान अब्दुल गफ्फार को अपने भाई अब्दुल जब्बार खान के साथ इंग्लैंड में पढ़ने का अवसर मिला, लेकिन वह जा नहीं सके। मां ने गफ्फार को यह कहकर रोक लिया कि एक बेटा तो विदेश चला गया है, अब दूसरे को नजर से दूर नहीं जाने दूंगी। यह मेरे सामने फलेगा-फूलेगा। मां उनसे बेपनाह मोहब्बत करती थीं और कभी अपने से अलग न होने देतीं। लेकिन धीरे-धीरे उनका बेटा गफ्फार से बाचा खान बन गया। जमाने ने उसे सरहदी गांधी कहकर पुकारा। जब खान साहब जेल के किस्से बताते, तो मां रोतीं। हालांकि उन्होंने कभी बेटे को यह सोचकर नहीं रोका कि वह इंसानी कौम के लिए कुछ बड़ा काम कर रहा है। एक बार वह जेल में थे तो मां का खत मिला। लिखा था, 'तुम्हें देखे बहुत वक्त बीत गया है। दिल चाहता है चलूं और तुम्हें देखूं। बेटा, इजाजत दो ताकि मुलाकात के लिए आऊं और तुम्हें जी भर देख लूं।' गफ्फार ने मां को जवाब में लिखा, 'आप मत आइये, मैं खुद जेल से छूटकर सीधे आपके पास आऊंगा।' गफ्फार ने लिखा है, 'उस दिन जेल में धूप में तख्त पर बैठा था। एक दोस्त दौड़ता हुआ आया, उसके हाथ में एक अखबार था। खबर थी कि मेरी मां का इंतकाल हो गया है। आखिरी समय में मां से नहीं मिल सका। अखबार आंखों पर रख फूट-फूटकर रोता रहा कि इस जंग-ए-आजादी ने मुझसे कितनी बड़ी कुर्बानी ली।'

Subrato Char

संकलन : हफीज किदवई

डॉनल्ड ने चुनाव प्रचार में वादे तो खूब किए थे, मगर उन्हें पूरा करना आसान नहीं होगा

क्या भारत के बिना ट्रंप का काम चलेगा

ललित मोहन बंसल, लॉस एंजिलिस से

अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में डॉनल्ड ट्रंप का शपथ लेना कई मायनों में खास होगा। सभी की नजरें होंगी वाइट हाउस में उनके पहले दिन पर।

खुशनुमा माहौल | राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप जानलेवा हमले में बाल-बाल बचे थे, लेकिन उन्होंने हौसला बुलंद रखा। स्विंग स्टेट्स में डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस को बड़े अंतर से हराया और दोनों सदनों में बहुमत हासिल किया। उन्होंने अमेरिका को फिर से महान बनाने और दुनिया में चल रहे युद्धों को खत्म करने का वादा किया है, जिससे माहौल खुशनुमा है। रिपब्लिकन इवेंजेलिकल समुदाय खास तौर पर खुश है, क्योंकि पनामा नहर जैसी महत्वपूर्ण धरोहर को हासिल करने की उम्मीद जगी है। हालांकि ट्रंप के ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाने वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया आ रही है।

मस्क की भूमिका | ट्रंप ने अपनी टीम में चीन के प्रति नरम रुख रखने वाले इलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी को रखा है। साथ ही, कूटनीति में तेज-तर्रार और चीन पर कड़ी टिप्पणियां करने वाले मार्को रुबियो को विदेश मंत्री बनाया है। मस्क पिछले साल भारत की यात्रा कैसल कर चीन पहुंच गए थे। वहां उनकी खूब आवभगत हुई। इसके बाद भी यह कहना गलत होगा कि दो देशों के बीच मस्क बिचौलिये की भूमिका निभा सकते हैं। जानकार बताते हैं कि ट्रंप अपने दोस्तों को एक सीमा तक ही छूट देते हैं।

क्वॉड को समर्थन | हिंद-प्रशांत महासागर में सुरक्षा और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ट्रंप क्वॉड देशों (भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका) की नौसेना के संयुक्त अभ्यास को समर्थन देंगे। वह चाहते हैं कि दक्षिण चीन सागर में चीन के दबाव का सामना कर रहे वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनेई और मलेशिया जैसे देशों का मजबूत साथ दिया जाए। हालांकि, आसियान के कुछ देश चीन के प्रभाव में हैं।

सहयोगियों पर रुख | रूस के खिलाफ मजबूती के लिए ट्रंप ने नैटो के सहयोगी देशों को फिर याद दिलाया कि अपनी सुरक्षा पर GDP का कम से कम 5% खर्च करें। ट्रंप अफ्रीका के 12 मुस्लिम देशों पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि लैटिन अमेरिकी देशों के साथ आर्थिक और कूटनीतिक संबंध मजबूत कर सकते हैं।

चीन की चुनौती | चीन ने समय के साथ सैन्य ताकत, आर्थिक नीति और कूटनीति के जरिए अपना दबदबा बढ़ाया है। आज वह सैन्य शक्ति में अमेरिका को टक्कर देने की स्थिति में है। उसने अपनी मुद्रा युआन का मूल्य दशकों तक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कम रखा, जिससे उसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में फायदा हुआ। बेल्ट एंड रोड इनीशिटिव के जरिए उसने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के 100 से अधिक विकासशील देशों में पहुंच बनाई, कर्ज बांटे। इससे ग्लोबल साउथ के देशों में चीन का दबदबा बना है, तो यूरोपीय देशों के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध कायम हुए। यूक्रेन युद्ध के दौरान उसने रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस खरीद कर उसकी अर्थव्यवस्था में मदद की।

दबदबा घट रहा | डॉनल्ड ट्रंप भले ही व्लादिमीर पूतिन के साथ दोस्ती का दावा करें लेकिन रूसी कब्जे में जा चुके यूक्रेनी इलाकों पर अपना दावा छोड़ने के लिए यूक्रेन को मनाना आसान नहीं होगा। ट्रंप ने शपथ ग्रहण के अगले ही दिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को बातचीत के लिए बुलाया है। आज वह वक्त नहीं है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति अंतरराष्ट्रीय नियम-कायदों को ताक पर रखते हुए अपनी बात मनवा सकें। रूस, चीन और उत्तर कोरिया के बीच बढ़ते कूटनीतिक रिश्तों से अब बहुध्रुवीय दुनिया आकार ले रही है।

भारत से उम्मीद | भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते मजबूत हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच भी अच्छी समझ है। दक्षिण-पूर्व एशिया में भू-राजनीतिक नजरिये से भारत की अहम भौगोलिक स्थिति के बारे में अमेरिका जानता है। उसे पता है कि भारत अपने दम पर आर्थिक ताकत बना है। चीन के बढ़ते दबाव को देखते हुए ट्रंप के पास एक ही चारा है, भारत के साथ व्यापार बढ़ाना और अमेरिकी कंपनियों का निवेश कराना।

साथ में विकास | प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विश्व बंधुत्व की अवधारणा को जी-20 और ग्लोबल साउथ-77 देशों के आयोजन में बड़ी सफलता मिली है। यह दिखाता है कि भारत और अमेरिका मिलकर संयुक्त राष्ट्र (UNO) और अन्य वैश्विक मंचों पर कैसे लाभ उठा सकते हैं।

पता है, कुछ न करना भी बहुत बड़ा काम है...

कोई हफ्ते में 70 घंटे काम करने के लिए कह रहा है और कोई 90 घंटे। सभी को चिंता है चीन की। चीन जो आगे निकल चुका है और हमारा क्या होगा। लेकिन, अगर उनकी मुलाकात किसी चीनी के बजाय मार्क ट्रवेन से हुई होती तो? तब ट्रवेन कहते, 'मैं आलसी पैदा हुआ था और जवान होने के बाद भी उतना ही आलसी रहा, जितना बचपन में था।' अगर काम जरूरी है, तो खाली बैठे रहना उससे भी ज्यादा जरूरी। यह हमेशा सच नहीं होता कि खाली बैठने से दिमाग में शैतान का घर हो जाए। हो सकता है कि वहां शैतान के बजाय खुशियां रहने आ जाएं।

उच्च संस्कृति में एक शब्द है निकसेन (Niksen)। इसका अर्थ है 'कुछ न करना'। बिना किसी खास उद्देश्य के आराम से बैठना, खिड़की के बाहर देखना या खुद को सिर्फ मौजूदा पलों में डूबने देना। निकसेन का मुख्य विचार यह है कि आप खुद को तनावमुक्त करें और दिमाग को थोड़ा खाली समय दें। यह कोई ध्यान या मेडिटेशन जैसी तकनीक नहीं, जहां आपको किसी खास चीज पर फोकस करना पड़ता है। आखिर दिमाग पर इतना भी जोर क्यों दिया जाए? उसे बस छोड़ दीजिए। यह खुद भी चाहता है कि कोई उससे कुछ न कहे। निकसेन को आधुनिक जीवन की भागदौड़ में मानसिक शांति और रचनात्मकता को बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका माना जाता है।

वैसे भी, हम हमेशा व्यस्त रहने के लिए नहीं बने।

AI Image

जीवन आनंद

शैलेंद्र पांडेय

हमेशा काम करना हमारा मिजाज नहीं, उसके लिए तो मशीनें हैं। हमारा स्वभाव है बोर होना। जब बोर होंगे, तभी आगे कुछ करने के लिए उत्सुकता बढ़ेगी। खाली रहना जरूरी है सपने देखने के लिए। सपने देखेंगे तभी तो उनको पूरा करने के लिए फिर कोई काम करेंगे। साइकोएनालिसिस के जनक सिगमंड फ्रायड का मानना था कि दिन में देखे गए सपनों से अपनी ताकत और अपनी कमजोरी को समझने में मदद मिलती है। इनके जरिये जाना जा सकता है कि हमारा डर, लक्ष्य और उम्मीदें क्या हैं।

खाली बैठने का यह मतलब नहीं कि हम आलसी हो गए और यह मतलब तो बिल्कुल नहीं कि घर में एक-दूसरे का चेहरा निहारा जाए। यह समय मानसिक विकास और आत्म-विश्लेषण का भी हो सकता है। जब हम कुछ नहीं करते, तब खुद के बारे में सोच रहे होते हैं। उसी समय सबसे ज्यादा करीब होते हैं हम अपने। कभी-कभी हमें खुद को समझने के लिए यही ठहराव चाहिए होता है। जब हम रुकते हैं, तो हमारा दिमाग चलता है। उसे आजादी मिलती है नए विचारों की ओर बढ़ने की। क्या हर दिन घंटों बांस के दिए टास्क में उलझा रहा शख्स कोई रचनात्मक काम कर सकता है?

आज के समय में हमेशा सक्रिय रहने की एक अजीब-सी मजबूरी है। कुछ नहीं तो लोग सोशल मीडिया पर ही विजी दिखने की कोशिश में हैं। यह मेसेज दिया जा रहा कि खाली बैठे रहना निठल्लापन है। लेकिन, इस दबाव में आने की जरूरत नहीं। अपने लिए थोड़ा समय बचा लेना गुनाह नहीं है।

शेयर करें अपने अनुभव

जीवन की दिनचर्या के अनुभवों में आप कैसे आनंद महसूस करते हैं, हमें बताएं nbtreader@timesofindia.com पर, और सब्जेक्ट में लिखें-'जीवन आनंद'

THE SPEAKING TREE
और पढ़ने के लिए देखें
www.speakingtree.nbt.in

ज्ञान से विज्ञान को जान सकते, विज्ञान से ज्ञान को नहीं

सुरक्षित गोस्वामी

ज्ञान मतलब सब कुछ जानने की क्षमता यानी जिसके बाद कुछ भी जानना शेष न रह जाए। ज्ञान केवल चेतना ही नहीं, प्रकृति के भी रहस्य उजागर कर देता है, क्योंकि ज्ञानी सृष्टि की बुद्धिमत्ता (cosmosis intelligence) के साथ अपना संपर्क साध लेते हैं। प्रकृति के रहस्यों को उजागर करना विज्ञान है, और प्रकृति सहित पुरुष के रहस्यों को जानना ज्ञान। विज्ञान में आप बाहर, प्रकृति में खोज करते हैं और ज्ञान में अपने ही भीतर चेतना की खोज। विज्ञान साकार की खोज है तो ज्ञान निराकार की।

वैज्ञानिक आत्मा को नहीं जान सकते, लेकिन आत्मा को जानने वाले हमेशा से सृष्टि को जानते आए हैं। प्रकृति में ऐसी कोई भी खोज नहीं जिसको बाद में बेहतर न किया गया हो। ऐसा कोई भी मोबाइल फोन नहीं, जिसको और बेहतर न बनाया गया हो। विज्ञान को जितना भी जान लीजिए, आने वाली नई खोजें आपकी जानकारियों को पुरानी बनाती चली जाएंगी। इसलिए वैज्ञानिक अपने को हमेशा अपडेट रखते हैं ताकि कहीं पिछड़ न जाएं। लेकिन ज्ञानी हमेशा नित नूतन रहते हैं, क्योंकि हजारों साल पहले जो ज्ञान था, वह आज भी अपडेटेड है।

प्रकृति का ज्ञान समय के साथ बदलता है, लेकिन चेतना का ज्ञान सदा स्थिर रहता है। ज्ञान के माध्यम से हम अज्ञान और विज्ञान दोनों को समझ सकते हैं, क्योंकि यह दोनों ही हमारी सोच और समझ पर निर्भर करते हैं।

ज्ञान से विज्ञान को देखेंगे तो सभी रहस्य खुल जाएंगे, लेकिन विज्ञान के नजरिए से केवल उसी की जानकारी मिलती है, जो आज खोजा गया है। अनंत को विज्ञान की कसौटी से नहीं समझा जा सकता। हां, ज्ञान से अनंत संभावनाओं की ओर जाने में मदद मिलती है।

विज्ञान 'क्या' और 'कैसे' की व्याख्या करता है, लेकिन 'क्यों' पर जाकर अटक जाता है, जैसे ब्रह्मांड क्यों बना और उसका विस्तार क्यों हो रहा है। 'क्यों' का उत्तर पाने के लिए हमें ब्रह्मांड के आधार ब्रह्म को जानना होगा। जहां विज्ञान जाकर खत्म होता है, वहां से ब्रह्म ज्ञान आरंभ होता है। भारतीय परंपरा में ब्रह्म ज्ञान हमेशा विज्ञान सहित दिया जाता है। गीता में कृष्ण कहते हैं, 'अति गोपनीय ज्ञान को विज्ञान सहित कहता हूं।' यदि विज्ञान के छात्र को विज्ञान के साथ-साथ ज्ञान भी सिखाया जाए, तो उसका नजरिया विस्तृत हो सकता है, और वह पूर्णता का अनुभव कर सकता है।

अधिकतर विज्ञान को जानने वाले उपाधि रोग में ही फंस जाते हैं कि 'मैं वैज्ञानिक हूं', लेकिन चेतना को जानने से अनंत का ज्ञान आपके भीतर उतरने लगता है।

युवा नेतृत्व पर यह पहल क्यों है ज़रूरी

डॉ. मनसुख मांडविया

महाभारत काल से हमारे देश की परंपरा रही है कि राष्ट्र का नेतृत्व जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर सौंपा जाए। इसीलिए राजा भरत ने अपने नौ पुत्र होते हुए भी युवराज के तौर पर उनमें से किसी को भी नियुक्त न करते हुए भूमन्यु को सामर्थ्य के आधार पर नियुक्त किया था। भारत की प्राचीन रीत रही है कि गुणों के आधार पर नेतृत्व प्रदान किया जाता है। इसी परंपरा को फिर से जीवित करने और परिवारवाद को जड़ से खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने संकल्प रखा है कि आने वाले समय में ऐसे एक लाख युवाओं को सक्रिय राजनीति में लाया जाए, जिनके परिवारों की कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है।

यंग लीडर्स | प्रधानमंत्री मोदी के इस संकल्प को सिद्ध करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना होगा, जिसकी शुरुआत एक छोटे कदम से हुई। इस साल भी हमने स्वामी विवेकानंद जयंती 12 जनवरी को 'राष्ट्रीय युवा दिवस' के रूप में मनाया। लेकिन इस बार राष्ट्रीय युवा दिवस को देश के लिए नए लीडर्स तराशने का मौका बनाते हुए इस कार्यक्रम को 'विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025' के रूप में आयोजित किया गया।

संघर्ष और जीत | स्वामी विवेकानंद मानते थे कि भारत को युवा ही आगे ले जा सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, 'जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी।' प्रधानमंत्री मोदी की युवाओं में अटूट श्रद्धा है। वह मानते हैं कि अगर युवाओं को सही मार्गदर्शन और अवसर प्रदान किया जाए, तो युवा इतिहास रच सकते हैं।

युवाओं पर जिम्मा | हमने विचार किया कि क्यों न इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए इसका आयोजन अलग तरीके से किया जाए। सोच विचार से तय हुआ कि 'विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग 2025' कार्यक्रम का स्वरूप कैसा रहेगा। कुल मिलाकर कार्यक्रम की तैयारी के पहले दिन से लेकर कार्यक्रम पूरा होने तक, सभी कार्य युवा स्वयंसेवक ही करें। विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग 2025 कार्यक्रम का पूरा जिम्मा हमारे युवा वॉलंटियर्स पर था। शायद यह पहला ऐसा सरकारी कार्यक्रम होगा, जिसमें हमने युवाओं को आगे रखा और सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों ने पीछे रहकर उनका मार्गदर्शन किया।

सक्षम हो युवा | युवाओं के लिए अपनी नेतृत्व एवं प्रबंधन शक्ति को तराशने का यह अवसर था। प्रधानमंत्री मोदी युवाओं को शासन व्यवस्था में लाने की सोच रखते हैं। उसी संदर्भ में सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि युवाओं की नेतृत्व शक्ति को कैसे विकसित किया जाए। ऐसे कार्यक्रम के जरिए ही हम अपनी युवा पीढ़ी को नेतृत्व करने में सक्षम बना रहे हैं और यह कार्यक्रम हमारे युवाओं के हाथों में नेतृत्व सौंपने का प्रथम पायदान रहा।

कॉमन रूम

तीस लाख युवा | कार्यक्रम में युवा प्रतिभागियों की योग्यता का सम्मान करने के लिए विकसित भारत क्विज कॉम्पिटिशन का आयोजन किया गया। इसमें देश के 30 लाख से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। जिसके बाद निबंध स्पर्धा और प्रजेंटेशन के माध्यम से उनका चयन किया गया। चयन करने की यह पद्धति देश के युवाओं ने ही तय की। चयनित प्रतिभागी अपनी काबिलियत के दम पर चुने गए जिसमें सिफारिश की कोई गुंजाइश नहीं थी।

विषयों का चयन | युवाओं ने जिन दस विषयों पर प्रधानमंत्री के सामने अपने विचार रखे, उनका चयन भी खुद युवाओं ने ही किया। इसमें 'टेक फॉर विकसित भारत, मेकिंग इंडिया द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस, मेकिंग इंडिया द स्टार्टअप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, एम्पावरिंग यूथ फॉर विकसित भारत, मेकिंग इंडिया स्पेस्टिंग एंड फिट नेशन, एम्पावरिंग विमिन एंड इंप्लिंग सोशल इंडिकेटर्स' जैसे विषय शामिल थे। विषयों का यह चयन युवा की सोच और हमारी अमृत पीढ़ी देश को कौन सी दिशा में ले जाना चाहती है, यह दर्शाता है। देश के सभी राजनीतिक दलों को भी युवाओं की इस सोच को समझकर सम्मान देना पड़ेगा।

अभूतपूर्व मौका | इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री तकरीबन सात घंटे मौजूद रहे। उनके सामने युवाओं ने प्रजेंटेशन दी। प्रधानमंत्री ने बहुत गौर से युवाओं के विचारों को सुना और जाना कि देश के युवा 'विकसित भारत' के बारे में क्या परिकल्पना रखते हैं। देश के अलग-अलग हिस्से से आए युवाओं के लिए यह ऐसा एक अभूतपूर्व अवसर था, जिसमें उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के सामने अपना विजन रखा। साथ ही इस आयोजन में इन युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे शीर्ष लोगों से संवाद का अवसर भी मिला।

नेतृत्व का संकल्प | विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग कार्यक्रम एक निर्णायक प्लैटफॉर्म बनकर उभरा है जो हमारे युवाओं को राजनीति में लाने का और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का माध्यम बनेगा। साथ ही यह हमारे युवाओं में नेतृत्व के गुण विकसित करने के साथ-साथ युवा पीढ़ी को भविष्य के भारत का नेतृत्व करने के लिए भी तैयार करेगा।

(लेखक केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं)

रीडर्स मेल www.edit.nbt.in

विकास को गति मिलेगी

18 जनवरी का संपादकीय 'आयोग से जुड़े सवाल' पढ़ा। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए ऐतिहासिक कदम उठाते हुए आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दी है। सरकार के इस निर्णय से लाखों सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में वृद्धि होगी। आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें न केवल कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ाएंगी, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार लाएंगी। इस फैसले से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और बाजार में मांग बढ़ेगी, जिससे अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम देश के समग्र विकास को गति देगा। हालांकि चुनौतियां भी आ सकती हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए कुशल नीतियों की जरूरत होगी।

आर. के. जैन, ईमेल से

गुनगुनाने की वजह

'जीवन आनंद' कॉलम में 14 जनवरी को प्रकाशित लेख 'आपके दरवाजे एक नई कहानी लेकर आई हवा' प्रकृति के अदृश्य और शांतिपूर्ण आकर्षण को उजागर करता है। मंद-मंद बहने वाली हवा को जब हम महसूस करते हैं, तो अंदर शांति का अहसास होता है। कई बार बारिश थमने के बाद जब हल्की सी हवा चलती है तो वह ठंडक तो देती ही है, लगता है वह हमारी रूह को स्पर्श कर रही है।

जीवन आनंद

मृदुला सिन्हा, ईमेल से

nbtedit@timesofindia.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

RJD में लालू के बराबर तेजस्वी को मिला अधिकार - एक खबर - यानी पिता के जूतों में पूत के पांव।

जितेंद्र गुप्ता

[illegible]

हिन्दुस्तान 1936

कोरोना से थकान

कोरोना महामारी के दुष्प्रभावों का अध्ययन लगातार चल रहा है और नए अध्ययन में यह पाया गया है कि कोरोना से ग्रस्त हुए अनेक लोगों में अत्यधिक थकावट लगातार बनी हुई है। *जर्नल ऑफ जेनरल इंटरनल मेडिसिन* (जेजीआईएम) में प्रकाशित अध्ययन में 11,785 व्यक्तियों को शामिल किया गया था। कम से कम 20 में से एक पूर्व-रोगी को अत्यधिक थकान लगातार सता रही है। शरीर में थकावट के साथ ही मानसिक रूप से भी थकावट और भ्रम का एहसास हो रहा है। इसे चिकित्सा शास्त्र की भाषा में क्रोनिक फेटिग सिंड्रोम या सीएफएस भी कहा जा रहा है। शोधकर्ताओं का कहना है कि यह शिकायत उन लोगों में ज्यादा देखी जा रही है, जो लंबे समय तक कोरोना वायरस से ग्रस्त रहे हैं। भारत में ही लाखों ऐसे रोगी थे, जो एक महीने से भी ज्यादा समय तक पॉजिटिव रहे, जिन्हें लगातार आईसीयू में ऑक्सीजन के भरोसे रहना पड़ा। वैसे, यह आकलन चिकित्सकों ने पहले भी किया था कि जिन लोगों को कोरोना ने लंबे समय तक सताया है, उनको आगे भी बहुत सावधान रहना होगा।

लंबे समय तक पीड़ित रहे लोगों में तब भी अनेक जटिलताएं देखी गई थीं। एक बीमारी ने अनेक बीमारियों को बढ़ाया था। इसके आंकड़े बहुत स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं हैं कि कोरोना का असर वास्तव में कितना विकराल था। कई देशों में आंकड़े छिपाए गए हैं और अनेक देशों में बड़ी संख्या में मामले दर्ज तक नहीं हुए हैं। बहरहाल, चिकित्सकों का मानना है, वैसे थकान कोविड-19 का एक सामान्य लक्षण है, पर कोविड-19 से उबरने के बाद लंबे समय तक लगातार थकान रहना 'लॉन्ग कोविड' का हिस्सा है। लॉन्ग कोविड की वजह से कुछ खास तरह के लक्षण देखे गए हैं, जिनमें चक्कर आना और गंध या स्वाद की समस्याएं सबसे आम हैं। सिरदर्द, खांसी और सांस लेने और नींद संबंधी समस्याएं भी अनुभव होती हैं। वैसे तो, लॉन्ग कोविड की कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं है, लेकिन यदि आपके लक्षण कोविड-19 संक्रमण के बाद हफ्तों या महीनों तक बने रहते हैं, तो आपके लॉन्ग कोविड से पीड़ित होने की आशंका है। बेटमैन हॉर्न सेंटर के शोध निदेशक सुजैन डी वर्नोन के नेतृत्व में शोधकर्ताओं ने पाया है कि कोविड-19 से पीड़ित 85 प्रतिशत लोगों ने संक्रमण के छह महीने बाद थकान के साथ-साथ मस्तिष्क में खोया-खोया सा महसूस होने जैसे लक्षणों की सूचना दी है। कोरोना की वजह से अनेक लोगों में नींद की समस्या भी बढ़ी है। जल्दी नींद नहीं आना या बीच-बीच में नींद का टूट जाना जैसी समस्याएं लोगों को परेशान कर रही हैं।

जो लोग लंबे समय तक कोरोना से पीड़ित रहे थे, उनमें लगातार थकान जैसी समस्या देखी जा रही है। इस पर व्यापक अध्ययन की जरूरत है।

अमेरिका में हुए इस अध्ययन की प्रशंसा होनी चाहिए। कोरोना और उसके प्रभाव पर बड़े अध्ययन की जरूरत है, ताकि किसी ठोस नतीजे पर पहुंचा जा सके। वहां चिकित्सक कोरोना के व्यापक दुष्प्रभावों को लेकर चिंतित भी हैं। साथ ही, इस दिशा में पुख्ता नतीजों तक पहुंचना और भी जरूरी हो गया है। गौर करने की बात है कि इस अध्ययन में बीमार या बीमार रह रहे लोगों को शामिल नहीं किया गया है, वरना दुष्प्रभावों की स्थिति और भयानक पाई जाती। एक तथ्य यह भी है कि अध्ययन में केवल ओमिक्रॉन संस्करण के मरीज ही शामिल थे, यदि डेल्टा के मरीजों को भी शामिल किया जाता, तो समस्याओं का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। कुल मिलाकर, यह अध्ययन अधूरा ही कहा जाएगा और पूरे अध्ययन की प्रतीक्षा रहेगी।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 20 जनवरी, 1950

पाकिस्तान की आनाकानी

हिन्दुस्तान और पाकिस्तान आज चाहे दो पृथक और स्वतन्त्र देश हो गये हैं, परंतु प्राकृतिक और परम्परागत रूप से एक ही भूभाग हैं तथा अभी कुछ समय पूर्व तक ये एक ही शासन-व्यवस्था के मातहत थे। अतः दोनों की अर्थनीति और रक्षा-दृष्टि ऐसी है कि मिल-जुलकर रहने में ही दोनों का कल्याण तथा असहयोग एवं संघर्ष में दोनों का विनाश निश्चित है। जिस रूप में वे एक से दो हुए, उसकी कड़वाहट और समस्याएं, उपर्युक्त तथ्य के बावजूद, दोनों को एक-दूसरे के विरुद्ध सशंक और अतिशंकितक बना रही हैं। इसका परिणाम जो होना चाहिए वही हो रहा है कि दोनों देश अपनी सामर्थ्य के अनुपात से अधिक रक्षा-व्यय कर रहे हैं। निकट पड़ोसी होते हुए भी प्रेम और सद्भाव के बजाय मानो एक-दूसरे को बदनाम करने और नीचा दिखाने के लिए तुले हुए हैं। यहां तक कि एक की सद्भावना को भी दूसरा अच्छे रूप में नहीं लेता। इसका इससे ज्वलन्त और क्या प्रमाण हो सकता है कि भारत ने पाकिस्तान के सामने अपनी समस्याओं के निपटारे के लिए युद्ध का आश्रय हर्गिज न लेने का जो सुन्दर प्रस्ताव रखा था, उसे भी पाकिस्तान ने स्वीकार नहीं किया!

समस्याओं या झगड़ों के निपटारे के लिए युद्ध का आश्रय न लेने के प्रस्ताव की भी एक कहानी है। संयुक्त राष्ट्र संघ में सम्मिलित होने वाले राष्ट्र विश्व शांति के इच्छुक माने जाते हैं और अपेक्षा यह की गई है कि आपस में लड़ने के बजाय विचार-विनिमय, बीच-बचाव या पंच-फैसलों अथवा निष्पक्ष न्यायालय के निर्णय द्वारा वे पारस्परिक मतभेदों या झगड़ों का निराकरण करेंगे। भारत चूंकि शांति के देवता महात्मा गांधी का देश है और मौजूदा भारतीय सरकार विश्व-शांति की उपासक, अतः पिछली तथा वर्तमान कड़वाहट के बावजूद प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान के सामने यह प्रस्ताव प्रस्तुत करने का सत्साहस किया कि हम दोनों (हिन्दुस्तान और पाकिस्तान) इस निश्चय की घोषणा करदें कि किसी भी हालत में अपने झगड़ों के लिए हम युद्ध का आश्रय नहीं लेंगे...। गत वर्ष के अगस्त मास में पूर्वी पंजाब के सार्वजनिक भाषणों में नेहरूजी ने यह खुली घोषणा की थी, उसके बाद काश्मीर में तथा अन्यत्र भी उन्होंने इसे दुहराया। इसे दुर्भावों अथवा कड़वाहट का ही परिणाम कहना चाहिए कि पाकिस्तान ने इसकी कद्र नहीं की।

नए बजट से उम्मीदें वही पुरानी

यहां स्कैन करें

आलोक जोशी | वरिष्ठ पत्रकार

महंगाई से परेशान मध्यवर्ग को यदि आयकर में राहत मिलती है, तो इससे बाजार में खपत बढ़ेगी, जिससे अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ेगी और सरकार की कमाई भी बढ़ेगी।

भारत में सबसे ज्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड हासिल करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब अपना आठवां बजट पेश करने जा रही हैं। उनसे पहले सबसे ज्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम था, जिन्होंने छह बजट पेश किए थे। बजट का नाम आते ही अर्थ और वित्त जगत ही नहीं, बल्कि खबरों पर नजर रखने वाले हरेक भारतीय के मन में सवाल उठने लगते हैं या उम्मीदें जागने लगती हैं। ज्यादातर के मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि बजट से हमें क्या मिलेगा?

कुछ साल पहले तक बजट के बाद की सबसे बड़ी हेडलाइन होती थी- क्या महंगा हुआ और क्या सस्ता! तब कस्टम, एक्साइज और दूसरे अप्रत्यक्ष कर भी यहीं कम या ज्यादा किए जाते थे। जीएसटी आने के बाद से यह काम करीब-करीब खत्म हो चुका है। अब महंगे-सस्ते का मामला सिर्फ सीमा शुल्क में फेरबदल तक सीमित रह गया है। उद्योगों और बड़े व्यापारियों की नजर अब उन नीतियों पर होती है, जिनका फायदा या नुकसान उन्हें तुरंत, निकट भविष्य में या फिर लंबे दौर में होने की गुंजाइश दिखती है। लेकिन आम आदमी के लिए अब सबसे जरूरी चीज 'इनकम टैक्स' का हिसाब रह गई है।

खबरें चलने लगी हैं कि इस बार वित्त मंत्री आयकर के मामले में बड़ा दिल दिखाने वाली हैं। चर्चा तो यहां तक चल रही है कि कर-मुक्त आय की सीमा, यानी इनकम टैक्स का पहला स्लैब बढ़ाकर 15 लाख रुपये सालाना किया जा सकता है। अभी पुरानी टैक्स व्यवस्था में ढाई लाख रुपये और नई व्यवस्था में तीन लाख रुपये तक की कमाई टैक्स फ्री होती है। हालांकि, 'स्टैंडर्ड डिडक्शन' और दूसरी रियायतें मिलाकर सात लाख से पौने आठ लाख रुपये तक की कमाई टैक्स फ्री हो जाती है। जानकारों को लगता है कि ऐसी संभावना तो नहीं है कि सरकार तीन लाख की इस लिमिट को सीधे बढ़ाकर पंद्रह लाख रुपये कर दे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन और बाकी सबके लिए भी इनकम टैक्स से छूट वाले निवेश की सीमाएं बढ़ाकर दूसरे रास्ते से उन्हें राहत दी जाए।

आम आदमी और मजदूर संघों ने तो यह सीमा बढ़ाने की मांग की ही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने भी दस लाख रुपये तक की कमाई को टैक्स फ्री करने की मांग की है। साथ ही, सीआईआई जैसे बड़े उद्योग संगठन की बजट मांगों में भी आयकर के मोर्चे पर कई तरह की राहत का सुझाव दिया गया है। उसे भी लगता है कि महंगाई की वजह से खासकर मध्यवर्ग के कम आय वर्ग के लिए खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। दूसरी तरफ, उसने यह तर्क भी दिया है कि जहां कंपनियों के इनकम टैक्स, यानी कॉरपोरेट टैक्स की सबसे ऊंची दर 25.17 प्रतिशत है, वहीं सरचार्ज और सेस जोड़ने के बाद व्यक्तिगत इनकम टैक्स की सबसे ऊंची दर 42.74 फीसदी हो जाती है। सीआईआई को लगता है कि यह फर्क बहुत ज्यादा है, इसको कम किया जाना चाहिए।

यहां यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि सीआईआई अचानक धर्मार्थ संगठन हो गया है या वह समाजसेवा के लिए ऐसी सलाह दे रहा है। उसने साफ किया है कि ऐसे कदम उठाने से क्या होगा, जिससे न सिर्फ सीआईआई, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। उसका कहना है कि महंगाई से परेशान मध्यवर्ग को अगर टैक्स में यह राहत मिलती है, तो इससे बाजार में खपत बढ़ेगी, जिससे अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ेगी और सरकार की कमाई भी बढ़ेगी। यही अर्थव्यवस्था का चक्र है, जिसको तेज करने की जरूरत है।

गरीबों को मदद या रेवड़ी दिए जाने के इस दौर में सीआईआई ने एक सुझाव यह भी दिया है कि गरीबों को नकद रकम के बजाय वाउचर दिए जाने चाहिए, जिनको वे किसी खास चीज पर ही खर्च कर सकें और वह भी तय समय-सीमा के भीतर। सुझाव यह भी है कि ऐसे वाउचर जन-धन खाता खोल चुके ऐसे ही लोगों को दिए जाएं, जिन्हें किसी भी अन्य सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा हो। इससे दो बातें होंगी। एक तो कुछ खास उत्पादों या सेवाओं पर खर्च बढ़ेगा, यानी उन उद्योगों या कारोबार के ग्राहक तैयार होंगे, दूसरे यह सुनिश्चित होगा कि सरकार जो धन दे रही है, लाभार्थी उसे खर्च भी कर रहे हैं। इसको किसी उद्योग संगठन का सीधा स्वार्थ भी माना जा सकता है।

एक सुझाव ऐसा भी आया है, जिसका मध्यवर्ग यकीनन स्वागत करेगा। सीआईआई का कहना है कि बैंक में जमा रकम पर जो ब्याज मिलता है, उस पर इनकम टैक्स की दर सामान्य से कम होनी चाहिए। इसके पीछे भी तर्क है। वित्त वर्ष 2019-20 में भारतीय परिवारों की बचत का 56.4 प्रतिशत हिस्सा बैंकों में जमा होता था, साल 2023-24 में यह हिस्सेदारी घटकर 45.2 फीसदी रह गई है। इसकी बड़ी वजह शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड वगैरह के मुकाबले कम रिटर्न के साथ ही उस पर लगने वाला टैक्स भी है। खासकर बुजुर्गों और बैंक में ही बचत रखने वाले लोगों के लिए यह एक अच्छा कदम हो सकता है।

सीआईआई का एक अन्य सुझाव महंगाई पर हमला करने और अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। बजट की लिस्ट में यह उसकी पहली ही मांग है। उसका कहना है कि अब सरकार को पेट्रोल-डीजल पर 'एक्साइज ड्यूटी' घटानी चाहिए। मई 2022 के बाद से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम करीब 40 प्रतिशत गिर चुका है, लेकिन इस शुल्क में फेरबदल नहीं हुआ है। अभी पेट्रोल के दाम में 21 प्रतिशत और डीजल में 18 प्रतिशत हिस्सा सिर्फ 'सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी' का ही है। जाहिर है, महंगाई में भी इसकी हिस्सेदारी बहुत बड़ी है। यह ड्यूटी कम की गई, तो इसका सीधा असर महंगाई पर दिखेगा और लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए कुछ रकम और बचेगी।

हजारों खबाहिशें वित्त मंत्री के पास पहुंच चुकी हैं, लेकिन इनमें से कितनी पूरी हो पाती हैं, यह खासकर इस बात पर निर्भर रहेगा कि सरकारी खजाने का हाल कैसा है। अभी तक की खबरें तो अच्छा संकेत दे रही हैं, लेकिन विकास के मोर्चे पर कुछ चिंताएं भी पैदा होती दिख रही हैं। इस स्थिति में कुछ ऐसे ही उपाय कारगर हो सकते हैं, जिनसे न सिर्फ आम आदमी को राहत मिले, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार पकड़ने में मदद मिल सके।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

निर्माण कार्यों के प्रदूषण से आखिर कैसे निपटा जाए

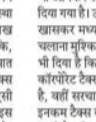

यहां स्कैन करें

श्री कुमार कुमारस्वामी | शहर नियोजन विशेषज्ञ

भारत के कई शहर प्रदूषित हवा से जूझ रहे हैं। जब हवा की गुणवत्ता खराब हो जाती है, तो ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स प्लान (ग्रैप) लागू कर दिया जाता है। इस समय में निजी व सरकारी निर्माण-कार्यों पर रोक भी लगा दी जाती है, क्योंकि माना जाता है कि शहरी भारत में सूक्ष्म कणों, यानी पार्टिकुलेट मैटर (पीएम- 2.5 और 10) से होने वाले प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत ये निर्माण-कार्य हैं।

प्रदूषण कम करने के उपाय निस्संदेह स्वागतयोग्य हैं, लेकिन निर्माण-कार्यों पर रोक लगा देने से अर्थव्यवस्था के साथ-साथ आजीविका और जनजीवन पर भी बुरा असर पड़ता है। सकल घरेलू उत्पाद में निर्माण-कार्य का योगदान कृषि के बाद दूसरा है। फिर, यह उम्मीद भी है कि भारत इस साल दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा निर्माण-बाजार बन सकता है, लिहाजा इसे लेकर एक संतुलित नजरिया बनाना होगा। हमें आजीविका या गुणवत्तापूर्ण जीवन से समझौता किए बिना आर्थिक विकास सुनिश्चित करने पर ध्यान देना चाहिए। मेरा मानना है कि निर्माण-कार्यों से होने वाले प्रदूषण को थामने के लिए हमें कुछ सुधारों को अपनाना चाहिए।

सबसे पहले, हमें निर्माण-स्थलों को प्रभावी रूप से घेर देना चाहिए। दरअसल, जो ग्रीन सेफटी जाल आमतौर पर इस्तेमाल होता है, वह बहुत महीन कणों को नहीं पकड़ पाता, इसलिए जब काम चल रहा हो, तो धूल को प्रभावी तरीके से रोकने के लिए अपारदर्शी तिरपाल शीट से निर्माण-स्थल को ढकना चाहिए। दूसरा उपाय, बंद निर्माण-क्षेत्रों में ऐसा मशीनी वेंटिलेशन सिस्टम होना चाहिए, जिसके फिल्टर उच्च गुणवत्ता वाले हों। इस तरह की मशीनें निर्माण-स्थलों पर काम करने वाले श्रमिकों के लिए वायु गुणवत्ता बनाए रखते हुए धूल के कणों को प्रभावी ढंग से पकड़ लेती हैं। तीसरा, काटने, आकार देने और वेल्डिंग करने जैसे धूल-पैदा करने वाले काम उन्हीं कमरों में होने चाहिए, जो विशेष तौर पर इसके लिए बनाए गए हों और जहां मशीनी वेंटिलेशन सिस्टम लगा हो। चौथा, वैक्यूम सिस्टम लगे उपकरणों के इस्तेमाल से निर्माण-स्थलों पर धूल के प्रबंधन में प्रभावी रूप से मदद मिलती है। धूल पैदा होते ही वे उपकरण उनको अपने में समेट लेते हैं और हवा में मौजूद सूक्ष्म कण काफी हद तक कम हो जाते हैं। पांचवां, क्रंकीट बनाने वाली मशीनों से निकलने वाले सीमेंट के धूल-कण चूंकि स्वास्थ्य पर काफी बुरा असर डालते हैं, इसलिए इसके निपटारे के लिए पर्याप्त उपाय किए जाने चाहिए। इन मशीनों का पूरी तरह से बंद घेरे में इस्तेमाल होना चाहिए और वहां मशीनी वेंटिलेशन की व्यवस्था होनी चाहिए।

निर्माण-कार्यों पर पूरी तरह से रोक लगा देने से अर्थव्यवस्था के साथ-साथ आजीविका और जनजीवन पर भी बुरा असर पड़ता है।

पांचवां उपाय, उत्खनन-कार्यों के दौरान तिरपाल शीट से ढीली मिट्टी को ढकने से उसके कण हवा में उड़कर दूर तक नहीं जा पाते। इसके अलावा, खुली जगहों पर रखी निर्माण-सामग्रियों के लिए और उनकी ढुलाई के वक्त मैग्नेशियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड जैसे यौगिक पदार्थों का इस्तेमाल धूल को दबाने में प्रभावी हो सकता है। छठा, निर्माण-स्थलों पर गाड़ियों की आवाजाही से भी काफी धूल उड़ती है। इससे बचने के लिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी गाड़ियों को पक्की या स्थिर राहों से ही गुजारा जाए। सातवां, उन्नत सेंसर लगाकर वायु गुणवत्ता की वास्तविक समय में निगरानी की जानी चाहिए, जिससे हमें प्रदूषण के स्तर को जानने और उसके अनुसार तत्काल कदम उठाने में मदद मिल सकती है। आठवां, इंसानों में स्वच्छ पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी विकसित करने संबंधी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए निर्माण-स्थलों पर इंजीनियरों, परियोजना प्रबंधकों और श्रमिकों को स्वच्छता उपाय अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। दुर्भाग्य से, कई सिविल और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रदूषण-नियंत्रण मुख्य विषय नहीं है, जिसके कारण निर्माण-स्थलों पर जागरूकता फैलाना आवश्यक है।

विडंबना है कि हम पहले से ही इन उपायों को जानते हैं, पर पर्याप्त निवेश व प्रतिबद्धता के अभाव से इनसे दूरी बनाकर रखते हैं। हालांकि, इन उपायों के अलावा धूल-मुक्त निर्माण-उत्पादों व सेवाओं को विकसित करने के लिए नवाचार व उद्यमशीलता को भी बढ़ावा देना चाहिए, जिससे न सिर्फ पर्यावरण-हितैषी निर्माण-कार्य संभव हो सकें, बल्कि वे तुलनात्मक रूप से सस्ते भी होंगे।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

सभी सत्य सनातन

आजकल सनातन शब्द को लेकर जो महाभारत मचा है, वह बिल्कुल अनावश्यक, एकदम गैर-सनातनी है। सनातन भारतीय मनीषियों की खोज है और प्राचीन शास्त्रों में गोते लगाएं, तो भिन्न अर्थों में इसका प्रयोग पाया जाता है। सनातन किसी एक धर्म का नाम नहीं, बल्कि यह अस्तित्व का मूलभूत वैज्ञानिक नियम है। जैसे आकाश अंतहीन फैला हुआ है, वैसे ही सनातन है और उसकी छाया में सभी नियमों का पालन होता है। गौर से खोजें, तो पता चलता है कि नैतिक नियम, मन के नियम, प्राकृतिक नियम, सभी के लिए सनातन कहा गया है।

जैसे बुद्ध ने कहा, 'इस संसार में वैर से वैर कभी शांत नहीं होता। अवैर से ही वैर शांत होता है; यही सनातन धर्म है।' और वैर कैसे शांत होगा? इसका उत्तर भी बुद्ध देते हैं : 'उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, मुझे जीत लिया, मेरा लूट लिया, ऐसी गांठें जो मन में नहीं बनाए रखते, उनका वैर शांत हो जाता है।'

कितना सरल, कितना सहज है। आप हिंदू हों या जैन या बौद्ध या मुस्लिम, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप अगर वैर भाव पालते हैं, लोगों से द्वेष करते हैं, तो आप सनातनी नहीं हो सकते। ओशो यही कहते हैं, 'वैर नर्क है। कहीं अन्य जगह कोई नर्क नहीं, शत्रुता में जीना नर्क है। तुम जितनी शत्रुता अपनी चारों तरफ बनाते हो, तुम्हारा नर्क उतना ही बड़ा हो जाता है। तुम जितनी मित्रता अपने चारों ओर बनाते हो, उतना बड़ा स्वर्ग खड़ा हो जाता है। नर्क कोई भौगोलिक जगह नहीं है और न ही स्वर्ग। इसलिए नक्शे में मत पड़ना। ये मनोदशाएं हैं। जब तुम सारे जगत को मित्र की तरह देखते हो, तुम्हारे लिए जगत मित्र हो गया, तुम्हारे शत्रु समाप्त हो गए।'

भगवान महावीर ने भी इसी तर्ज पर कहा है, *मित्तिमे सव्व भूए सु, वैरं मज्झ न केवई* मेरी मित्रता सारे विश्व से है और मेरा वैर किसी से नहीं। महावीर के कानों में भी खीलें ठोकने वाले मिल गए, पत्थर मारने वाले मिल गए, पर महावीर यही कहते रहे, मेरी किसी से शत्रुता नहीं। यही सनातन धर्म है। शत्रुता से शत्रुता समाप्त नहीं होती, क्रोध से क्रोध समाप्त नहीं होता, यह समझ सनातन धर्म है।

आप पुरानी भारतीय पुस्तकों को खंगालें, तो इसी तरह के वचन मिलेंगे, 'सच बोलें, प्रिय बोलें, पर अप्रिय सत्य कभी न बोलें। और असत्य कितना ही प्रिय क्यों न लगे, उसे न बोलें।' यह सनातन धर्म है। 'गलत काम कभी न करें, चाहे प्राण क्यों न त्यागना पड़े और सही काम से किसी भी स्थिति में कभी न मुकरें।' यही सनातन धर्म है।

जैसे आकाश अंतहीन फैला हुआ है, वैसे ही सनातन है। गौर से खोजें, तो पता चलता है कि नैतिक नियम, मन के नियम, प्राकृतिक नियम, सभी के लिए सनातन कहा गया है।

ये सभी नियम मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं, मन के आचरण के नियम हैं। पुराने समय मनोविज्ञान नाम से कोई शास्त्र नहीं था, वह आध्यात्मिक विचार के अंतर्गत ही आता था। मगर सनातन पर गलतफहमियों का परदा पड़ा है। काश! सनातन उन आवरणों से मुक्त हो जाए।

अमृत साधना

अमित शाह | केंद्रीय गृह मंत्री

डिग्री हासिल करना जरूर अच्छी बात है, मगर विद्यार्थियों को डिग्री के बजाय ज्ञान हासिल करने के लिए ज्यादा पुरुषार्थ करना चाहिए। उन्हें प्रतिस्पर्द्धा की संस्कृति के बजाय सहयोग की संस्कृति लेकर आगे बढ़ना चाहिए।

नई तकनीक से पठन-पाठन का रूप बदला

जब टेलीविजन की शुरुआत हुई, तो लेखन-सामग्री पर खतरा बताया गया था। यहां तक कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने के बाद तो पत्र-पत्रिकाओं के दिन लदने की भविष्यवाणियां की जाने लगी थीं। मगर कुछ लोगों का यह विलाप बाद में अनर्गल प्रलाप साबित हुआ। खैर, अब तो सोशल मीडिया का युग है, जिसमें हर कोई लेखक है, फिर भी यह बहस चल रही है कि इसका हमारे पठन-पाठन पर बुरा असर पड़ा है। जबकि, मैं आज भी मानता हूं कि पढ़ने वाले पढ़ना ही पसंद करते हैं। उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि लेखन कागज पर उकेरा गया है या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर। तकनीक के जानकार कुछ अलग मिजाज से जरूर पठन का मजा ले रहे हैं, लेकिन कागज पर पढ़ने के शौकीनों के लिए हर तरह की राह खुली हुई है।

दरअसल, पिछले कुछ वर्षों में लेखन और अभिव्यक्ति की शैली में काफी बदलाव आया है। एक तो लेखन के मामले में लोग पहले की तुलना में कहीं अधिक उदार हुए हैं और फिर, अब हर कोई लिखना पसंद करता है। इससे आप भले ही यह आरोप लगाएं कि लेखन का स्तर गिर गया है या अब रचनात्मकता पुराने दिनों जैसी नहीं दिखती, लेकिन यह दिलचस्प है कि तमाम लेखकों का कोई-न-कोई पाठक वर्ग है। अपने सुख के लिए लिखने वाले लोगों को भी पढ़ने वाले आपको मिल जाएंगे। कई पाठक तो छोटे-छोटे लेखन को खूब पसंद करते हैं, जो *एक्स* जैसी माइक्रोब्लॉगिंग साइट पर लिखे जाते हैं। वास्तव में, सोशल मीडिया ने लेखन का रूप बदल दिया है। कंप्यूटर की-बोर्ड ही अब लेखकों के लिए कलम है। इसलिए, पठनीयता का अभाव नहीं हुआ है, बल्कि उसका रूप बदल गया है, खासकर तकनीक से जुड़ाव होने से।

प्रकाशन सुविधाओं के विस्तार ने भी लेखक-पाठक जुड़ाव को नया आयाम दिया है। पहले किताबों को छपवाना बड़ा कठिन काम होता था, लेकिन आज 100-150 कॉपियों के साथ नए संस्करण छपे जा रहे हैं। कंप्यूटर से इस तरह छपाई हो रही है कि चंद कॉपियां भी यदि कोई छपवाना चाहे, तो वह छपवा सकता है। यह सुविधा खासतौर से नए लेखकों को खूब लुभा रही है। वे एक प्रकाशन-संस्थान से नकारात्मक जवाब मिलने के बाद झट दूसरे के पास पहुंच जाते हैं और अपनी किताब छपवा लेते हैं। कुल मिलाकर, यही कहना सही होगा कि पठनीयता का अभाव नहीं हुआ है। लोग आज भी पढ़ना ही चाहते हैं। मगर हां, हम यह कह सकते हैं कि इसका रूप पूरी तरह से बदल गया है, जो सुखद ही है, क्योंकि समय के साथ बदलने वाले ही टिक पाते हैं।

महिमा सिंह, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम
पठनीयता का अभाव

अब कम होने लगी लोगों में पढ़ने की रुचि

यह सोशल मीडिया का दौर है। सूचना क्रांति के इस युग में पठनीयता का अभाव हो गया है। आज से दस-बीस बरस पहले तक लोग जितने अखबार और पत्र-पत्रिकाएं पढ़ा करते थे, आज शायद ही उतने पढ़ते हैं। पुस्तकालयों में जाकर आज शायद ही कोई व्यक्ति पुस्तक, पत्रिका या अखबार जारी करवाकर पढ़ता होगा, क्योंकि आज विभिन्न पठन-पाठन सामग्री इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर आसानी से उपलब्ध हो जाती है। आज के जमाने में ई-बुक्स, ई-पत्रिकाएं, ई-अखबार आसानी से कहीं भी, कभी भी उपलब्ध हो जाते हैं, बशर्ते वहां इंटरनेट की उपलब्धता हो।

आज नई पीढ़ी में पठनीयता का तेजी से ह्रास हो हुआ ही है, मुद्रण भी एक बड़ी चुनौती साबित हुई है। आज मुद्रण के लिए अर्थ, यानी धन या वित्त की खासा जरूरत पड़ती है। दिक्कत यह भी है कि आज की युवा पीढ़ी हाथ से लिखने से बचती है। वह किसी पुस्तक को प्रत्यक्ष अपने हाथों में लेकर पढ़ने की आदी नहीं रही। समय के कथित अभाव के कारण पाठक, विशेषकर नौजवान लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट या फोन में रमे रहेंगे, लेकिन पढ़ने से बचेंगे। जबकि, पाठनीयता शब्द से तात्पर्य उन सभी कारकों से है, जो किसी पाठ को पढ़ने और समझने में सफलता को प्रभावित करते हैं। आज पाठकों में पढ़ने के प्रति इसलिए भी ललक कम हुई है, क्योंकि अब मनोरंजन के कई साधन विकसित हो चुके हैं। 'मल्टीप्लेक्स कल्चर' ने पठनीयता पर व्यापक असर डाला है। इन्हीं सब वजहों से साहित्यिक किताबों, पत्र-पत्रिकाओं, अखबारों आदि के मुद्रण में अभूतपूर्व कमी आई है। इसे विडंबना ही कहेंगे कि एक तरफ डॉक्टर हमें चेतावनी देते हैं कि स्क्रीन का हमारे मन-मस्तिष्क पर बुरा असर पड़ता है, तो दूसरी तरफ हमारा स्क्रीन-टाइम लगातार बढ़ रहा है। हालांकि, बड़े-बुजुर्ग आज भी कागजों पर पढ़ना पसंद करते हैं। उनके लिए स्क्रीन पर पढ़ना उबाऊ होता है।

बहरहाल, आज के समय में विरले ही किसी घर में पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं के लिए जगह बची है, क्योंकि इसके प्रति नई पीढ़ी में अरुचि का भाव है। अगर हम चाहते हैं कि पठनीयता का यह अभाव दूर हो, तो हमें पढ़ने के प्रति रुचि पैदा करनी होगी। खास तौर पर पुस्तकालयों में जाकर, घर में, सफर के वक्त हमें किताबें हाथ में लेकर पढ़नी चाहिए और स्क्रिन-कल्चर से दूरी बनानी चाहिए। हमें पाठक और लेखक के बीच की दूरी भी पाटनी होगी। अगर हम ऐसा नहीं कर सके, तो उम्दा लेखन से दूर होते जाएंगे। तकनीक की दुनिया कागजी दुनिया पर हावी हो जाएगी।

सुनील कुमार महला, टिप्पणीकार

हमें अपनी इच्छाओं के बजाय उपलब्ध संसाधनों पर अधिक विचार-विमर्श करना चाहिए। -जॉर्ज वाशिंगटन

अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी से ऐन पहले इस्राइल व हमास के बीच, भले दबाव में, युद्धविराम समझौते के क्रियान्वयन की शुरुआत पूरी दुनिया के लिए राहत लेकर आई है। लेकिन स्थायी शांति के लिए जरूरी है कि दोनों पक्ष खुले दिल से समझौते की शर्तों को स्वीकार करें।

शांति की उम्मीद

पंद्रह महीनों तक चले निराशा व विध्वंस के दौर के बाद इस्राइल व हमास के बीच युद्धविराम समझौते की खबरें पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में थीं और अब अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पद की शपथ लेने से ऐन पहले इस्राइल के मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इसके क्रियान्वयन की राह भी खुल गई है। यह समझौता इसलिए भी स्वागतयोग्य है कि इसके बाद दोनों तरफ से बंधकों व कैदियों की रिहाई संभव होने के साथ गाजा के बुरी तरह से ध्वस्त उस क्षेत्र के लिए मानवीय मदद का मार्ग भी खुल सकेगा, जिसे इस वक्त इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। यह सहमति तब बनी है, जब सात अक्तूबर, 2023 को हमास द्वारा इस्राइल में मचाए गए कत्ल-ए-आम के बाद शुरू हुआ संघर्ष बड़ी संख्या में निर्दोष नागरिकों की जान ले चुका है और लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि संबंधित पक्ष युद्धविराम को क्षेत्रीय तनाव कम करने के लिए एक अवसर के रूप में लेंगे। नहीं भूलना चाहिए कि यह पिछले वर्ष मई में बाइडन द्वारा पेश किया गया वही समझौता है, जिसे इस्राइल व हमास दोनों ने ही अस्वीकार कर दिया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के सीधे हस्तक्षेप के बाद, जिसमें उन्होंने अपनी ताजपोशी के बाद हमास को देख लेने और नेतन्याहू को भी घेरने के संकेत दिए थे, दोनों ही पक्षों पर समझौते को स्वीकारने का स्वाभाविक दबाव समझा जा सकता है। चिंतित करने वाला सत्य यह है कि यह स्थायी शांति नहीं, बल्कि युद्ध विराम समझौता है। इसका महत्व तभी है, जब दोनों ही पक्ष खुले दिल से समझौते की शर्तों को स्वीकार करें, लेकिन पहले नेतन्याहू मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी में किया गया विलंब और फिर रविवार की सुबह, जबसे संघर्ष विराम लागू होना था, हमास द्वारा बंधकों के नाम बताने में की गई देरी से आगे की जटिलताओं के संकेत ही मिलते हैं। नेतन्याहू का यह असमंजस, कि कहीं यह समझौता हमास की जीत

का संकेत न दे, निरर्थक ही है, क्योंकि हमास खुद, ईरान व हिजबुल्ला के कमजोर पड़ने से, संघर्ष से निकलने का मार्ग ढूंढ रहा है। दोनों के संबंधों की जटिलता को देखते हुए सभी बंधकों की वापसी, फलस्तीनी कैदियों की रिहाई और छह हफ्तों के युद्ध विराम को स्थायी शांति में बदलना, यह सब कुछ आसान नहीं होने वाला और यह काफी हद तक आज अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे ट्रंप की नीतियों पर भी निर्भर करता है। इसके बावजूद कहना होगा कि यह समझौता शांति व स्थिरता की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो पूरी दुनिया के लिए राहत लेकर आया है।

ताकि विकास की गाड़ी चलती रहे

ट्रंप ब्रांड की अनिश्चितताओं के आर्थिक व राजनीतिक निहितार्थ भी हो सकते हैं। लेकिन भारत अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था के दम पर वैश्विक तूफानों का सामना कर सकता है, बशर्ते वह सामने दिख रही चुनौतियों का समाधान ढूंढने की सतत कोशिशें करता रहे। क्या बजट-2025 में वित्त मंत्री इस पर ध्यान देंगी?

अक्सर लोगों को परिस्थिति की गंभीरता को समझने के लिए आंकड़ों की जरूरत होती है। हाल ही में देश को बताया गया कि वर्ष 2024-25 में जीडीपी विकास दर घटकर 6.4 फीसदी रह सकती है। यह भी पता चला कि मुद्रास्फीति अधिक है, सार्वजनिक निवेश और औद्योगिक विकास बहुत कम है तथा खपत भी धीमी है। खपत को बढ़ावा देने के तरीकों पर खूब बहस हो रही है, जैसे आयकर दरों में कटौती का सुझाव दिया जा रहा है। लेकिन अगर सिर्फ आंकड़ों पर ही गौर करेंगे, तो भ्रम पैदा होगा। सतत प्रयासों से ही समस्याएं दूर होंगी और विकास की राह भी खुलेगी। बगैर किसी क्रम के यहां दिए गए विचार इस संबंध में उपयोगी हो सकते हैं।

शंकर अय्यर
वरिष्ठ पत्रकार

राष्ट्रीय ग्रिड

मांग को नुकसान पहुंचाने वाला एक प्रमुख कारक खाद्य मुद्रास्फीति है, जो एक साल से अधिक समय से नष्ट होने वाली चीजों में सात फीसदी से ज्यादा है। भारत को इन चीजों के लिए एक राष्ट्रीय ग्रिड की आवश्यकता है, जैसा कि वर्गीज कुरियन ने दूध के लिए किया था। राष्ट्रीय ग्रिड के निर्माण से पैदावार में वृद्धि होगी, किसानों की आय में सुधार होगा, रोजगार में वृद्धि होगी और फसल कटाई के बाद होने वाली अन्न की बर्बादी पर अंकुश लगेगा, जो अनुमानित 25 प्रतिशत है। ग्रिड आगे और पीछे के लिंकेज को जोड़ेगा। शुरुआत के लिए, सरकार एक जिला, एक उत्पाद डाटाबेस का उपयोग कर सकती है और अमूल और मदर डेयरी खरीद मॉडल का उपयोग कर सकती है। सहकारी समितियों और निजी खिलाड़ियों द्वारा उत्पादन अनुबंधों में प्रवेश करने के बाद भंडारण की प्रक्रिया भी खरीद के बाद ही शुरू होगी। निश्चित रूप से, अनुबंधों के लिए नीतिगत बदलाव, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बढ़ावा गया ऋण और पंचायत स्तर पर कोल्ड चेन के वित्तपोषण की आवश्यकता होगी।

उद्यम क्रेडिट कार्ड

अौपचारिक ऋण तक पहुंच ने सूक्ष्म उद्यमियों को लगातार परेशान किया है। क्रिसिल की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि इस क्षेत्र में

औपचारिक ऋण की पहुंच मात्र 20 फीसदी है। वित्त मामले के लिए संसद की स्थायी समिति ने भी पाया कि औपचारिक ऋण केवल 39 प्रतिशत छोटे उद्यमों को ही छू पाया है। सूक्ष्म उद्यमियों को ऋण पाने के लिए निजी ऋणदाताओं को अत्यधिक ब्याज दरों का भुगतान करना पड़ता है, जैसा कि हाल ही में रिजर्व बैंक ने संकेत दिया है। हालांकि बैंकों को उद्यम-पंजीकृत उद्यमियों को प्राथमिकता क्षेत्र के मानदंडों के तहत ऋण देने का निर्देश दिया गया है, पर लगता है कि पहुंच को या तो रोक दिया गया है या खारिज कर दिया गया है। सूक्ष्म उद्यमों को उद्यम क्रेडिट कार्ड दिया जा सकता है। इससे उद्यम पंजीकरण के आधार पर ऋण तक उनकी पहुंच हो सकती है। क्रेडिट सीमा को व्यवसाय के आकार और यूपीआई लेनदेन के आधार पर तय किया जा सकता है।

सौर राजमार्गों का मौद्रीकरण

भारत की विकास गाथा मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे पर सरकारी खर्च से प्रेरित है। विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत अपनी जरूरत की अधिकांश ऊर्जा का आयात करता है, जिसमें चुनौतियां भी कम नहीं हैं। हालांकि, बुनियादी ढांचे एक अवसर प्रस्तुत करता है। भारत में करीब 1,50,000 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं; उच्च सौर विकिरण वाले राज्यों में करीब 70,000 किलोमीटर राजमार्ग हैं। नियमों के अनुसार, चार लेन वाले राजमार्गों को लगभग पांच मीटर (पहाड़ी क्षेत्रों में 2.5 मीटर) की चौड़ाई वाले डिवाइडर से बांटकर उस पर सौर पैनल लगाया जा सकता है। यह स्थान बिजली अपलोड करने और रखरखाव के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। सड़क परिवहन मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को क्षमता का नक्शा बनाने, पायलट परियोजनाएं आरंभ करने तथा सार्वजनिक और निजी निवेशकों से बोलियों के लिए तैयार स्थानों को पेश करने का निर्देश दे सकता है। जैसे-जैसे यह विचार आगे बढ़ेगा, यह प्रति किलोवाट-घंटे उपकरणों और ऊर्जा के मूल्य निर्धारण में बढ़े पैमाने पर अर्थव्यवस्थाओं को गति देगा।

अमृत काल कोष

विकसित भारत के लक्ष्य को पाने के लिए फंडिंग में भारी वृद्धि की आवश्यकता है। स्टेट बैंक के चेयरमैन का अनुमान है कि 2036 तक आठ फीसदी ज्यादा की वृद्धि के लिए भारत को 1,094 लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र की परिसंपत्तियों का लाभ उठाना होगा। रणनीतिक विनिवेश के विचार को धन और शक्ति के संकेंद्रण की चिंताओं से चुनौती मिलती है। यह पक्षपातपूर्ण राजनीति से भी ग्रस्त होता है। निजीकरण के ढांचे से हटकर साझा सार्वजनिक स्वामित्व की ओर कदम बढ़ाना एक व्यवहार्य रास्ता है। विचार यह है कि सरकार की सभी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की हिस्सेदारी को अमृत काल कोष में डाल दिया जाए, जो सिंगापुर की जीआईसी जैसी एक संप्रभु इकाई होगी। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की आय में सुधार हुआ है और हाल के वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के शेयरों का बाजार मूल्य लगभग तीन गुना हो गया है, जो घाटे को कम करने, ऋण चुकाने और संप्रभु रेटिंग को उन्नत करने का अवसर प्रदान करता है। राजनीतिक विरोध से बचने के लिए सरकार पहले 51 प्रतिशत से अधिक पीएसयू होल्डिंग्स को स्थानांतरित कर सकती है। इस कोष का उपयोग संसाधन जुटाने और विनिवेश साधन के रूप में किया जा सकता है।

आत्मनिर्भर वरिष्ठ नागरिक

भारत 15 करोड़ से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों का घर है, जिनमें से ज्यादातर को पेंशन का लाभ नहीं मिलता। वर्ष 2050 तक इनकी संख्या 35 करोड़ तक पहुंच जाएगी। वरिष्ठ नागरिक बचतकर्ता, निवेशक और उपभोक्ता हैं। विकास को गति देने के लिए देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर नीतियों में बदलाव की जरूरत है। वरिष्ठ नागरिक सक्रिय जीवन जीना चाहते हैं और समाज के साथ अपनी पहचान और जुड़ाव को मजबूत करने के लिए अक्सर स्वरोजगार करते हैं। कंसल्टेंसी आय पर उनके द्वारा चुकाए जाने वाले 18 प्रतिशत जीएसटी की समीक्षा करना उपयोगी होगा। वरिष्ठ नागरिकों की आय पर जीएसटी क्यों नहीं घटाया जाता? वरिष्ठ नागरिक भी स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। क्या उनके द्वारा आवासीय संपत्ति खरीदने पर छूट दी जा सकती है? भारत अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था का लाभ उठाकर वैश्विक तूफानों का सामना कर सकता है, बशर्ते कि वह लगातार समस्याओं का समाधान कर सके।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

वद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन

मनुष्य को जो कुछ सीखना, करना और निपटाना है, उसके लिए अर्थपूर्ण समय बहुत ही कम मिला है। इसलिए व्यवस्थित ढंग से जब हम अपने काम का विभाजन करते हैं, तो कम समय में काफी कुछ कर सकते हैं।

सुबह जागते ही काम का विभाजन कर लेना चाहिए

निश्चय जब अवसर चला जाता है, तब हाथ मलना ही हमारे पास रह जाता है। आलस्य से भरे भद्दरे स्वभाव में बेकार बैठे रहने की इच्छा प्रबल होती है। मनुष्य जब तक किसी कृत्य को अपना कर्तव्य समझकर दृढ़ उद्देश्य से उसे नहीं करेगा, तो वह कर्तव्य शून्य स्वभाव-अलहड़ी बन जाएगा। आलस्य मनुष्य को वैसे ही नष्ट कर देता है, जैसे लोहे का जंग। संसार में मनुष्य को जो कुछ सीखना, करना और निपटाना है, उसके लिए अपर्याप्त समय बहुत ही कम मिला है, क्योंकि जीवन के दिन गिने-चुने हैं, इनको व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। यदि अपने समय के प्रत्येक पल की चिंता मनुष्य रखे, तो थोड़ी आयु को भी बहुत बढ़ा सकता है, जिसे वह एक मास में कर सकेगा, उसी को बहुतेरे जीवनपर्यंत में भी नहीं करेंगे। यदि उसका ध्यान उचित और उत्तम कृत्यों में निमग्न है, तो समय सुख से व्यतीत करता है, नहीं तो बहुतेरों का जीवन भारभूत-सा हुआ रहता है। दिन-रात जम्हाते बीतता है, इनकी दीर्घ-सूत्रता और रात-दिन के बर्ताव को देखने से यही जान पड़ेगा कि मानो ये खुद को अमर समझे हुए हैं।

बहुतेरे खूब खाकर पेट पर हाथ फेरते पान कूचते हुए तकिया का आश्रय लेकर पलंग पर सो जाते हैं और बारह-चौदह घंटे नींद में खोते हैं। डॉक्टरों का मत है कि शरीरिक स्वास्थ्य के लिए नियमित छह घंटे सोना उपयुक्त है। यदि इतना ही सोने का अभ्यास किया जाए, तो कितना समय बच सकता है। अधिक सोने से केवल समय की हानि ही नहीं, शरीर के जितने अवयव हैं, शिथिल और अयोग्य हो जाते हैं और 12 घंटे सोने के बाद उतनी ही व्यक्तुलता और अशक्तता कार्य करने में होती है। शरीर और मन दोनों को इससे हानि पहुंचती है। फिर खाने के पश्चात तुरंत सो जाने से आलस्य, हाड़फूटन, अपच, ग्लानता, शिरोव्यथा होती है। यदि मनुष्य अपने अमूल्य समय को न खोना चाहे तो उसे क्षुद्र कामों में शामिल नहीं होना चाहिए। प्रातःकाल उठकर मनुष्य को विचार कर निर्णय लेना उचित है कि उसे उस दिन क्या-क्या और कितना करना है, तब उसके करने में तुरंत प्रवृत्त हो जाना उचित है। उन क्षणों को जो व्यर्थ बीते जा रहे हैं। यदि संभाल लो, तो सब कुछ हो सकता है और समय का उचित बर्ताव तभी होगा, जब नियम व क्रम से मनुष्य अपने समय को बांटे लेगा। संसार में बहुत से ऐसे मनुष्य हैं, जो अपने समय का उत्तम विभाजन न कर, जब जो चाहा करते हैं, जिसका फल यह होता है कि जितनी कार्यव्यापियां उनको होती हैं, वे अधूरी रह जाती हैं, यदि दृढ़ संकल्प से किसी कार्य पर सन्नद्ध हो मनुष्य उसको यथोचित बांटकर विचार करेगा, तभी वह उसे कर सकेगा, अव्यवस्थित चित्त कभी कुछ भी नहीं कर सका है। समय को खोने वालों को समय का यथार्थ रूप नहीं जान पड़ता, हां एक दिन अवश्य इसका आदर उन्हें करना होगा, और वह तब कि जब क्षण के शतांश के भी पाने की उनकी प्राप्तीना व्यर्थ होगी, तभी अपने अमूल्य जीवन की फेंकी घड़ियों का मूल्य उन्हें यथार्थ में समझ पड़ेगा।

वर्तमान में जिएं

सूत्र

भविष्य आज शुरू होता है, न कि कल। यदि आप किसी चीज के बारे में सोचने में बहुत अधिक समय लगाते हैं, तो आप उसे कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी से काम को शुरू कर दें। लोग कहते हैं कि समय चीजों को बदल देता है, लेकिन वास्तव में आपको उन्हें स्वयं बदलना होगा। वर्तमान में जिएं। भविष्य आप नहीं जान सकते। और अतीत अब पास नहीं है।

दूसरा पहलू

महाकुंभ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 'एक थैला-एक थाली' अभियान पर्यावरण संरक्षण में अहम योगदान दे रहा है।

महाकुंभ, पर्यावरण और सनातनी समाधान

यह महाकुंभ अनेकानेक मायनों में अद्वितीय और अनुकरणीय भी है। इसके तमाम पक्षों में जहां प्रबंधन, सुरक्षा, विशालता, भव्यता इत्यादि की हर ओर चर्चा है, वहीं यहां अपनाए जाने वाले पर्यावरण सम्मत अभिनव अनुष्ठानों की मिसाल भी दुनिया में आने वाले कई वर्षों या सदियों तक दी जाएगी। इन नवाचारों का उद्देश्य यह है कि विश्व के सबसे बड़े समागम में सूखे एवं गीले कचरे के साथ-साथ किसी भी प्रकार के तरल कचरे को या तो उत्पन्न ही न हो और यदि हो, तो उसका समुचित निराकरण भी किया जाए।

विवेक एस अग्रवाल
प्रयागराज महाकुंभ में अपनाए जाने वाले पर्यावरण सम्मत अभिनव अनुष्ठानों की मिसाल दुनिया में आने वाली कई सदियों तक दी जाएगी।

महाकुंभ में आ रहे करोड़ों लोगों में कुछ तो पूरी अवधि के लिए यहां रुक हैं, तो कुछ एक या दो दिन के लिए। मिसाल के तौर पर अगर यह माना जाए कि 40 करोड़ लोग मात्र एक दिन के लिए महाकुंभ में आए हुए हैं, तो वे औसतन 250 ग्राम प्रति व्यक्ति कचरा उत्पन्न करेंगे। पूरे आयोजन के दौरान लगभग एक लाख मीट्रिक टन कचरा उत्पन्न होगा, जो कि यह कचरा प्रयागराज में सृजित होने वाले छह से आठ माह के कुल कचरा उत्पादन के बराबर है। इस आयोजन के कचरे को एकत्र करने के लिए जहां विपुल संसाधनों की आवश्यकता होगी, वहीं इसका निष्पादन करने के लिए भी कम से कम दो लाख वर्ग मीटर जमीन की आवश्यकता होगी। यह ज्ञात तथ्य है कि कचरे का एकत्रीकरण, परिवहन और निष्पादन सभी स्तरों पर अपारिमित कार्यन उत्सर्जन करता है, जो कि मानवता के लिए खतरा भी है। लेकिन इस बार का पर्यावरणसम्मत महाकुंभ विश्व को भारत की स्वच्छता की दृष्टि से सनातनी परंपरा की व्यापकता के रूप में पुख्ता जवाब देगा। महाकुंभ के दौरान अनेकानेक नवाचारों में स्वयंसिक प्रभावशील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा संपूर्ण राष्ट्र में छेड़ा गया 'एक थैला-एक थाली' अभियान है, जिसके माध्यम से यह आह्वान किया गया कि प्रत्येक तीर्थयात्री अपने साथ एक कपड़े का थैला और एक स्टील की थाली अवश्य लाए, ताकि एकबारगी उपयोग होने वाले प्लास्टिक को प्रभावी तौर पर नकारा जा सके। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा पूरे राष्ट्र में जहां समस्त तीर्थयात्रियों तक अधिक से अधिक थैला और थाली वितरण का लक्ष्य रखा है, वहीं इस संदेश को आमजन तक पहुंचाने के लिए घर-घर से थैला और थाली एकत्रित भी की गई है, ताकि उसकी महत्ता को योगदान देने वाले परिवार और स्वीकार्य करने वाले परिवार दोनों के मध्य बराबरी से समझा जा सके। उम्मीद है कि थैला और थाली अभियान महाकुंभ तक ही सीमित नहीं रहेगा, अपितु यह एक संदेश और महत्वपूर्ण अवयव के रूप में परिवारों तक पहुंचेगा, जो इसे अपने व्यवहार में अपनाने के लिए प्रेरित होंगे।

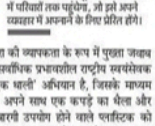

उम्मीद है कि थैला और थाली अभियान महाकुंभ तक ही सीमित नहीं रहेगा, अपितु यह संदेश एक महत्वपूर्ण अवयव के रूप में परिवारों तक पहुंचेगा, जो इसे अपने व्यवहार में अपनाने के लिए प्रेरित होंगे।

आंकड़े

विदेश में शिक्षा

कोरोना महामारी के दौर को छोड़ दें, तो विदेश में शिक्षा हासिल करने के लिए जाने वाले भारतीय विद्यार्थियों की संख्या में हर साल इजाफा हो रहा है।

2019	5,86,337
2020	2,59,655
2021	4,44,553
2022	7,50,365
2023	8,92,989

आंकड़े विदेश में पढ़ने के लिए जाने वाले भारतीय विद्यार्थियों के | स्रोत : MoE

नामदेव जी ने भगवान विट्ठल को अपना दुख सुनाया। भगवान विट्ठल बोले, यह सच है कि जब तक गुरु के चरणों में नहीं जाओगे, तब तक कच्चे ही रहोगे।

गुरु बिना ज्ञान नहीं

गोरा जी का जन्म तेरढोकी नामक स्थान पर हुआ था। इन्हें सभी लोग 'चाचा' कहा करते थे। गोरा जी बड़े ही विरक्त, दृढ़ निश्चयी और ज्ञानी भक्त थे। एक बार काशी की यात्रा से लौटते हुए ज्ञानेश्वर-नामदेव आदि संत गोरा जी के यहां ठहरे। सभी संत एक साथ बैठे हुए थे। पास ही एक थापी पड़ी हुई थी। उस पर मुक्ताबाई की दृष्टि पड़ी, उन्होंने पूछा-चाचा जी यह क्या चीज है? गोरा जी ने उत्तर दिया, यह थापी है, इससे मिट्टी के घड़े को ठोककर देखा जाता है कि घड़ा कच्चा है या पक्का है।

मुक्ताबाई ने कहा, 'हम मनुष्य भी तो घड़े ही हैं, इससे क्या हम लोगों की भी कच्चाई-पक्काई मालूम हो सकती है?' गोरा जी बोले, 'क्यों नहीं'। उन्होंने थापी उठाई और एक-एक संत के सिर पर थपकर देखने लगे। और संत तो यह कौतुक देखने लगे, पर नामदेव बिगड़े। गोरा जी जब उनके पास गए तो नामदेव को बुरा लगा। गोरा जी ने उनके भी सिर पर थापी थपी और बोले, सभी संतों में यही घड़ा कच्चा है। आगे बोले, नामदेव तुम भक्त हो, पर अभी तुम्हारा अहंकार नहीं गया, जब तक गुरु की शरण में नहीं जाओगे, तब तक ऐसे ही कच्चे रहोगे। नामदेव जी दुखी हुए। उन्होंने भगवान विट्ठल को अपना दुख सुनाया। भगवान ने कहा, 'यह सच है कि गुरु की शरण में जाए बिना कच्चे ही रहोगे। हम तुम्हारे साथ सदा हैं, पर तुम्हें देहधारी मनुष्य को गुरु मानकर उनके चरणों में अपना अहंकार लीन करना होगा।'

अंतर्यात्रा
संकलित

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 12 अक्तूबर, 1963

हेरोल्ड मैकमिलन का ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा

हेरल्ड मैकमिलन का ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से भी स्तीफा

महारानी एलिजाबेथ को दिलीपकुमार इस्तीफा भेजा

कंजर्वेटिव पार्टी के वार्षिक अधिवेशन में प्रधानमंत्री हेरोल्ड मैकमिलन ने घोषणा की कि वह अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। निर्णय की सूचना उन्होंने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को दे दी है और मंत्रिमंडल के सदस्यों को भी बता दिया है।

यह कैसी केवाईसी

केवाईसी-नो योर कस्टमर-से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करना आवश्यक है, लेकिन कई बैंकों ने इसकी प्रक्रिया को प्रताड़ना की हद तक पहुंचा दिया है।

संजय अभिज्ञान | आर्थिकी

आगामी एक फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट से आम नागरिकों की सबसे बड़ी उम्मीद क्या है? जवाब के लिए आज कोई राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण हो, तो मुमकिन है कि पब्लिक के दिल की आवाज कुछ इस तरह सुनाई दे कि वित्त मंत्री जी, बाकी तो हम झेल लेंगे, मगर सबसे पहले बैंकों में बारंबार केवाईसी वेरिफिकेशन के जंजाल से छुटकारा दिलाइए।

हर चार-पांच माह की अवधि के बाद आधार, पैन, एड्रेस प्रूफ, फोटो और मोबाइल नंबर के दस्तावेज सत्यापित कराने की कवायद की पीर वही जानते हैं, जो इसे भुगत चुके हैं। 'अपने ग्राहक को जानो'-के ऊंचे स्लोगन के साथ केवाईसी की चक्की सबको पीस रही है। इधर कुछ बैंकों ने जिस तरह केवाईसी अपडेशन के लिए खाते में लेनदेन रोकने जैसी हद पार करने वाली हरकत का सहारा लेना शुरू किया है, उससे यह जनउत्पीड़न का आकार ले रहा है। शहरी-कस्बों के निवेशक, बचतकर्ता, म्यूचुअल फंड ग्राहक और किस्म-किस्म के लोनधारकों

के अलावा देहात के ये गरीब लाभार्थी ज्यादा दुख झेल रहे हैं, जो अपनी सब्सिडी की किस्त, राशन भुगतान, सम्मान राशि या पेंशन जनधन खाते में गिरने का इंतजार करते रह जाते हैं। यह वही तकता है, जो पहले से न्यूनतम बैलेंस के नियम के कारण निष्क्रिय खातों का कहर झेल रहा था।

यूपी की एक ताजा घटना देखें। वाराणसी के पास सोनभद्र में पिछले साल 28 दिसंबर को बैंक की लाइन में खड़े 65 वर्षीय रम्मन अचानक गिर गए। अस्पताल पहुंचने पर वह मृत पाए गए। सभी स्थानीय अखबारों में यह खबर छपी और उसकी सुर्खियों में केवाईसी को जिम्मेवार बताया गया। परिवार का आरोप था कि वह तीन दिन से पेंशन खाते की केवाईसी के लिए बैंक का चक्कर लगा रहे थे, लेकिन कभी सर्वर डाउन होने के कारण और कभी किसी और वजह से काम पूरा नहीं हो पा रहा था। इस घटना से देश के वित्तजगत को चौंक जाना चाहिए था। खाते में लेनदेन रुक जाए और यूपीआई वगैरह के भुगतान ठप हो जाएं, तो हारी-बीमारी, आंधी-पानी, सर्दी-गर्मी में कितनी ही दूर स्थित बैंक ब्रांच तक लंबा सफर मजबूरी बन जाता है। देश में एक लाख साठ हजार से ज्यादा बैंक शाखाएं हैं। लेकिन विसंगति है कि इनमें से बस 30 फीसदी ग्रामीण भारत में हैं, जहां देश की 60 फीसदी आबादी बसती है। शाखाओं के इस कम घनत्व के कारण ही वहां घर से बैंक शाखा तक का फासला कई किलोमीटर लंबा होता है।

इस नई लीला के पीछे कौन है? जाहिर है जिस केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में देश के 53 करोड़ लोगों को जनधन खाता देने की ऐतिहासिक वित्तीय समावेशी योजना बनाई, वह क्यों चाहेगी कि खाता धारकों के साथ ऐसा सलूक हो। न ही रिजर्व बैंक चाहेगा, क्योंकि उसने तो वर्ष 2016 में जारी अपने मास्टर पॉलिसी डॉक्यूमेंट में साफ लिखा है कि केवाईसी में पहचान पत्र, पता, मोबाइल और ईमेल ही पर्याप्त हैं। यही नहीं, 6 नवंबर, 2024 को जारी नोटिफिकेशन में रिजर्व बैंक ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि अगर कस्टमर के केवाईसी में कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो ईमेल से भेजा गया उसका सेल्फ डिक्लेरेशन भी सत्यापन के लिए पर्याप्त होगा। नियम यह भी है कि यदि कस्टमर सामान्य रिस्क श्रेणी वाला है, तो दस साल में एक बार सत्यापन भी मान्य होगा। मगर कितने बैंक हैं, जहां इन नियम-कायदों की अनदेखी नहीं हो रही? वित्तीय लेनदेन की निगरानी वाले बिचौलिए विभाग और कुछ रिटेल बैंक विलेन बनकर उभर रहे हैं। उधर अनेक केस स्टडी देख चुके विशेषज्ञ बताते हैं कि केवाईसी के बहाने बीमा या म्यूचुअल फंड जैसे धर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स की बिक्री का माहौल बनाया जाता है। एक गंभीर खतरा यह भी है कि ग्राहकों की ताजा गोपनीय जानकारी का कीमती डाटाबेस निजी कंपनियों को बेचा जा सकता है।

कई जगह गांव-देहात में जनधन खाते खोलने का टारगेट पूरा करने की होड़ में कतिपय कर्मियों ने खासी हड़बड़ी में केवाईसी की जानकारी दर्ज की थी। डाटा एंट्री ऑपरेटर और क्लर्कों के स्तर पर हुई गलतियों तो अपनी जगह हैं ही, कोढ़ में खाज की तरह आधार कार्ड में दर्ज हुई पुरानी गलतियां भी उनमें जुड़ जाती हैं। अब जब यह मोबाइल और पैन से लिंक हो गया है-उसकी एक-एक बारीकी नाजुक हो चली है। बेशक, अभिलाषा श्रीवास्थ्वी के चलते केवाईसी की पड़ताल आवश्यक है। लेकिन जिस तरह खाने में मक्खी गिरने के डर से आप रसोईघर पर ताला नहीं लगा सकते, उसी तरह दुरुपयोग के अंदेशे में किसी का अकाउंट नहीं फ्रीज किया जा सकता। अगर सरकारी विभाग साइबर अपराधियों से निपटने में सक्षम नहीं हैं या बैंकों में स्टाफ कम है, तो ये उनकी अपनी समस्याएं हैं। उनका खामियाजा आम खाताधारक क्यों भुगतें? केवाईसी की व्यवस्था खाताधारकों के लिए कष्टकारी नहीं, मददगार हो, क्या ऐसी व्यवस्था नहीं की जा सकती? उम्मीद है वित्त मंत्री एक नई, सरल केवाईसी नीति बनाने की दिशा में कदम उठाएंगी।

1.55 करोड़ मतदाता हैं दिल्ली में, हालिया आंकड़ों के अनुसार, जिनमें से 83.49 लाख पुरुष हैं, जबकि 71.73 लाख महिलाएं हैं।

डा. विकास सिंह
मैनेजमेंट गुरु तथा वित्तीय एवं समस्त विकास के विशेषज्ञ

आजकल

तात्कालिक लाभ से प्रभावित मतदाता

दिल्ली विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार जोर-शोर से चल रहा है। यहां चुनाव लड़ रहे सभी प्रमुख राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए तरह-तरह के वादे कर रहे हैं। मुफ्त बिजली, पानी और महिलाओं को खाते में रकम भेजने के अलावा स्वास्थ्य, पेंशन और गैस सिलिंडर जैसे मामलों से जुड़ी 'रेवड़ियों' की बहार है। राजनीतिक दल मतदाताओं से तुलनात्मक रूप से अधिक चीजें मुफ्त प्रदान करने के वादे कर रहे हैं। ऐसे में मतदाताओं के लिए तात्कालिक लाभ की व्यवस्था ने कई सवाल भी खड़े किए हैं

मतदाता के नजरिये से तात्कालिक लाभ प्राप्त करने वाला दृष्टिकोण देश की राजनीति में हावी होता जा रहा है। फाइल

लोकतंत्र की जटिल व्यवस्था में सत्ता अंततः लोगों के हाथों में ही होती है। आजकल इसमें एक चिंताजनक मिथ्याभास देखने को मिल रहा है। विकल्पों की प्रचुरता का सामना कर रहे मतदाता, सरकार के दीर्घकालिक दृष्टिकोण की तुलना में तात्कालिक लाभ से अधिक प्रभावित होते प्रतीत होते हैं। सरकारें बेहतर कार्य करने के बावजूद सत्ता से बाहर हो जाती हैं और वे अक्सर उन वादों की तलाश में होती हैं जो स्थायी विकास के बजाय अल्पकालिक राहत प्रदान करते हैं। मतदाताओं और उनकी आशाओं दोनों की ओर से फोकस में यह बदलाव, हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली और हमारे समाज के भविष्य के बारे में गंभीर सवाल उठाता है। जबकि विकल्पों में बिविधता एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है, विकल्पों की अधिकता ने एक अजीब प्रवृत्ति को जन्म दिया है। चुनावी प्राथमिकताओं में यह नजरिया लोकतंत्र की बुनियादी समझ के बारे में चिंता पैदा करता है। क्या हम एक समाज के रूप में विकास की कीमत पर तत्काल संतुष्टि के आकर्षण को प्राथमिकता दे रहे हैं?

अधिकल एक नई प्रवृत्ति उभर कर सामने आई है, वह है सरकारों का तेजी से बदलना। यह अक्सर तत्काल संतुष्टि की इच्छा और अल्पकालिक लाभ के आकर्षण से प्रेरित होती है। ऐसा लगता है कि मतदाता मुफ्त सुविधाओं और तत्काल लाभ के वादों से तेजी से प्रभावित हो रहे हैं, जो अक्सर एक निर्वाचित सरकार द्वारा प्रदान की जा सकने वाली दीर्घकालिक दृष्टि और स्थिरता को प्रभावित कर रहा है। त्वरित समाधान और त्वरित पुरस्कारों के इस युग में, राज्य चलाने में निर्वाचित प्रतिनिधि की भूमिका पर विचार करना अनिवार्य हो जाता है। जबकि मतदाता किसी राष्ट्र की नियति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नागरिकों के लिए भी यह उतना ही महत्वपूर्ण है कि वे अपने पास मौजूद शक्ति और उसके साथ आने वाली जिम्मेदारियों को पहचानें।

निर्वाचित अधिकारियों का मूल उद्देश्य लोगों की आवाज के रूप में सेवा करना, मतदाताओं की विविध आकांक्षाओं एवं आकांक्षाओं को सार्थक नीतियों और कानून में परिवर्तित करना है। हालांकि वर्तमान परिदृश्य से पता चलता है कि समाज के भविष्य को आकार देने वाली व्यापक, अधिक सूक्ष्म चिंताओं पर ध्यान देने के बजाय सारा फोकस तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने की ओर स्थानांतरित हो गया है।

दबाव के आगे झुकना : निर्वाचित प्रतिनिधि वोटों की तलाश में अल्पकालिक समाधान और त्वरित संतुष्टि की पेशकश के दबाव के आगे झुक सकते हैं। चुनौती तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने और समय की कसौटी पर खरी उतरने वाली नीतियां तैयार करने के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने में है। निर्वाचित प्रतिनिधि की भूमिका मुफ्त सुविधाओं और अल्पकालिक लाभ के माध्यम से कहीं अधिक है। इसमें एक ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करना शामिल है जो आने वाले वर्षों में राष्ट्र की समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करे। इसी तरह, मतदाताओं को तत्काल इच्छाओं से परे सजग विकल्प चुनने की जिम्मेदारी अपनानी चाहिए, उनके निर्णयों का समाज के ताने-बाने पर पड़ने वाले स्थायी प्रभाव का आकलन करना आना चाहिए।

निर्वाचित प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी केवल चुनावी वादों को पूरा करने तक सीमित नहीं है। इसमें शासन की जटिलताओं के बारे में जनता को शिक्षित और जागरूक करने का कर्तव्य शामिल है। लोकतंत्र की जटिल रूपरेखा में राजनीतिक दल देश के भविष्य के वास्तुकार के रूप में कार्य करते हैं। उनकी विचारधाराएं, घोषणापत्र और नेतृत्व शासन की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर भी दीर्घकालिक विकास पर अल्पकालिक लाभ को प्राथमिकता देने की मौजूदा प्रवृत्ति ने एक स्थायी लोकतांत्रिक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने में राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजनीतिक दलों को अपने स्वार्थ के आगे झुकने के बजाय लोकतांत्रिक मूल्यों को आकार देना चाहिए।

सुधरें निर्वाचित प्रतिनिधि : आधुनिक राजनीतिक परिदृश्य की चुनौतियों से निपटने के लिए मानसिकता में बदलाव जरूरी है। निर्वाचित प्रतिनिधियों को तत्काल पुरस्कारों के प्रलोभन से ऊपर उठना चाहिए और एक ऐसे दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए जो अगले चुनाव चक्र से आगे तक फैला हो। इसके साथ ही, मतदाताओं को अल्पकालिक लाभ के आकर्षण से आगे बढ़कर उन नेताओं को महत्व देना चाहिए जो राष्ट्र के दीर्घकालिक कल्याण को प्राथमिकता देते हैं। तीव्र सूचना प्रवाह और निरंतर कनेक्टिविटी के युग में, चुनावों के दौरान मतदाताओं पर विकल्पों की बौछार हो जाती है। उन्हें तत्काल संतुष्टि के आकर्षण से दूर रहने का साहस और दृढ़ विश्वास लाना चाहिए।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व : राजनेताओं और मतदाताओं के बीच संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव ने इस मिथ्याभास में योगदान दिया है। राजनेता, जिन्हें कभी व्यापक भलाई के लिए काम करने वाले लोक सेवक के रूप में देखा जाता था, अब मतदाताओं को ग्राहक के रूप में देखते हैं, अपना वोट सुरक्षित करने के लिए उनकी जरूरतों को पूरा किया जाता है। परिप्रेक्ष्य में इस बदलाव के दूरगामी परिणाम होंगे, विशेषकर मध्यम वर्ग के लिए। तात्कालिक इच्छाओं को पूरा करने की चुनावी रणनीति अक्सर दीर्घकालिक योजना की कीमत पर, आर्थिक रूप से वंचितों का पक्ष लेती है। मुफ्त सुविधाएं और अल्पकालिक राहत कार्यक्रमों के तहत मध्य वर्ग इन लाभों के लिए योग्य नहीं हो सकता है, लिहाजा वह स्वयं को उपेक्षित महसूस करता है। इस प्रतिमान में संसाधनों से सज्जित अमीर वर्ग सरकारी हस्तक्षेप पर कम निर्भर हैं। राजनीतिक माहौल चाहे जो भी हो वे अपने हितों को सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरी ओर, गरीब अपनी कमजोरी के कारण मुफ्त चीजों और अल्पकालिक लाभों के प्राथमिक प्राप्तकर्ता बन जाते हैं। असमंजस में उलझा मध्य वर्ग सतत विकास और आर्थिक वृद्धि की आकांक्षाओं के अनुरूप प्रतिनिधित्व पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। यह बढ़ता हुआ सामाजिक-आर्थिक अंतर सवाल पैदा करता है कि क्या व्यवस्था टूट गई है? क्या लोकतंत्र जिसे प्रतिनिधित्व और सामूहिक निर्णय लेने का एक तंत्र बनाया गया है, अपनी मंशा के अनुरूप कार्य कर रहा है?

सभी की भागीदारी से संभव समतामूलक विकास

प्रत्येक हितधारक समतापूर्ण विकास के लिए लोकतंत्र को नया आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे वर्तमान चुनौतियों का सामना करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। इस प्रयास के केंद्र में मतदाताओं को शिक्षित करना अनिवार्य है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में एक जागरूक नागरिक मूल आधार है। ऐसे में आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने और उम्मीदवारों के बारे में विश्वसनीय जानकारी तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके साथ ही, राजनीतिक नेताओं के व्यवहार में भी आमूलचूल बदलाव की आवश्यकता है। ऐसे में चुनावी सफलता के लिए अल्पकालिक लाभ को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति को छोड़कर दीर्घकालिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को अपनाना चाहिए। सतत विकास के लिए आवश्यक बलिदानों के बारे में खुली बातचीत सरकारी दृष्टिकोण की परिभाषित विशेषताएं बननी चाहिए। यह पुनर्निर्देशन राजनीतिक विमर्श को तात्कालिक लाभ के आकर्षण से लेकर समय के साथ एक लचीले समाज के निर्माण तक बढ़ा सकता है।

इसके अलावा, आर्थिक नीतियां समावेशी होनी चाहिए जो समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए तैयार की गई हो, जिसमें मध्यम वर्ग पर विशेष ध्यान दिया जाए। लक्षित नीतियां विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समूहों के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों का समाधान कर सकती हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि विकास से कुछ चुनिंदा लोगों के बजाय पूरे देश को लाभ हो। मैदान को समतल करने के लिए राजनीतिक अभियान के वित्तपोषण पर पुनर्विचार आवश्यक है। इस पहलू में सुधार करने से सभी उम्मीदवारों के लिए समान अवसर सुनिश्चित होते हैं, राजनीतिक आवाजों में विविधता को बढ़ावा मिलता है और व्यापक प्रचार के अनुचित प्रभाव को कम किया जाता है। इसके अतिरिक्त, स्थानीय शासन को सशक्त बनाने से एक उत्तरदायी और जवाबदेह राजनीतिक व्यवस्था में योगदान मिलता है। स्थानीय प्रतिनिधि, विकसित शक्तियों के साथ दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाते हुए चिंताओं का समाधान कर सकते हैं।

लोकतंत्र में नागरिक भागीदारी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। सक्रिय भागीदारी और सार्वजनिक वार्तालाप नागरिकों को जवाबदेही की मांग करने और दीर्घकालिक हितों को प्राथमिकता देने वाली नीतियों की वकालत करने के लिए सशक्त बनाती हैं। नीति केंद्रित अभियानों के माध्यम से राजनीतिक फोकस को लोकलुभावन उपायों से व्यापक नीतियों पर स्थानांतरित कर निरंतर विकास पर जोर देते हुए चुनावी परिदृश्य को नया आकार दिया जा सकता है। राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक जवाबदेही भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। मजबूत आंतरिक तंत्र जो नीतियों की पारदर्शिता और जांच को बढ़ावा देते हैं, आंतरिक आडिट के साथ मिलकर पार्टी के लक्ष्यों को देश के दीर्घकालिक हितों के साथ जोड़ते हैं। इसके अलावा, राजनीतिक दल अपने सदस्यों को शासन की पेचीदगियों के बारे में शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे अल्पकालिकवाद के परिणामों के प्रति जागरूक एक जिम्मेदार राजनीतिक वर्ग तैयार करने में मदद मिलती है। एकजुट होकर ये रणनीतियां लोकतांत्रिक व्यवस्था में योगदान कर सकती हैं जो समान विकास को प्राथमिकता देती है और समय की कसौटी पर खरी उतरती है।

(डा. विकास सिंह)

खरी-खरी

कंवल वनाम रजाई

अतुल चतुर्वेदी

यह कंबलों का युग है। जहां देखिए कंबल छाए हुए हैं। कंबल हर कहीं उपलब्ध है, बस ओढ़ाने वाला चाहिए। सही टाइमिंग और घटना को उत्सव बनाने की कला चाहिए। राजनीति में तो कंबल ओढ़ाकर कइयों के भविष्य पैक कर दिए गए तो दूसरी ओर कंबल ओढ़ा कर सस्ती, लोकप्रिय राजनीति भी खूब की गई। सड़कों के किनारे गरीब गुरबे ठिठुर रहे हैं और नेता जी कंबल बांटने में लगे हैं।

आखिर कौन नहीं चाहता कंबल? सब रेडीमेड व्यवस्था चाहते हैं। भौजन बह जो आनलाइन आर्डर किया जा सके। प्रोडक्ट वह जिसे तुरंत लांच किया जा सके। आखिर संतान भी है तो बायलाजिकल प्रोडक्ट ही एक तरह से। तभी तो उसके गर्भ में होते समय ही लांचिंग के मंसूबे बनने लगते हैं।

लेकिन आज समय बदल गया है। पुलिस वाले भी अब कंबल ओढ़ा कर अपराधी का सम्मान समारोह नहीं करते। कारण चाहे कुछ भी रहे हों, कंबलों ने बहुत प्रगति की है। आजकल के कंबल रंग बिरंगे और मजबूत होते हैं। उनमें से होकर ठंड तो क्या स्वाभिमान का एक कण भी नहीं गुजर सकता। रजाइयां आउटडेटेड हो गई हैं। वे दकियानूसी का प्रतीक मान ली गई हैं। जबकि कंबल प्रगतिशील मूल्यों का वाहक है। कंबल शर्म और धूल प्रूफ होता है अर्थात मान-अपमान से परे।

कंबल ओढ़ाने के भी अपने अलग अर्थ हैं। जब आपको अपने विरोधी को बर्फ में लगाना हो तो आप उसे उपेक्षा का कंबल ओढ़ा कर चुप कर सकते हैं या ठिकाने भी लगा सकते हैं। पुलिस वाले अपराधियों से साथ इसी उच्च तकनीकी का सहारा लेकर अनुसंधान की गति प्रदान करते हैं। जबकि रजाई के साथ यह व्यवस्था नहीं हो पाती है। वहां कंटकाकीर्ण मार्ग है, उसके पर्याप्त रखरखाव की मांग है, जबकि दू मिनट मैगी के जमाने में कौन इतनी संभाल करेगा। लोगों से रिश्ते, कार्यकर्ता और पार्टी नहीं संभाली जा रही और आप परंपरा की बात कर रहे हैं। रजाई तो एक तरह का परंपरागत मूल्य है, बिसरत है तो केवल आधुनिक भाव बोध है। रैप के युग में शास्त्रीयता की तलाश व्यर्थ है, आलाइन के जमाने में मां के हाथ की रोटियों का स्वाद कहां नसीब है।

पोस्ट

हरित क्रांति के बाद पंजाब कृषि महाशक्ति जरूर बना, लेकिन उसे इस मुकाम तक पहुंचाने में यूपी और बिहार से आने वाले हिंदू श्रमिकों का अहम योगदान रहा है।
अर्शदीप सिंह@the_lama_singh

मुझे लगा था कि अगर शुभमन गिल चैंपियंस ट्राफी के लिए टीम में चुने गए तो वह भाग्यशाली होंगे, पर वह तो उपकप्तान बन गए। बीसीसीआइ में बहुत चीजें रहस्यमय ढंग से हो रही हैं।
सुमत रमण@sumanthraman

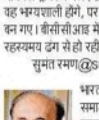

भारत को जाति मुक्त समाज बनाने के बजाय राहुल गांधी का जातिगत जनगणना पर जोर देना देश को और जाति-केंद्रित बनाने का काम करेगा। सामाजिक मोर्चे पर इससे प्रतिगामी कदम और कोई नहीं हो सकता।
मिन्हाज मर्चंट@MinhazMerchant

बांग्लादेशी घुसपैठिये इस देश की सुरक्षा लिए खतरा हैं, वह सभी को स्वीकार कर लेना चाहिए। सैफ अली खान के घर में घुसकर उन पर जानलेवा हमला करने वाला बांग्लादेशी निकला। अब समय आ गया है कि पूरे देश में बांग्लादेशियों को खदेड़ने का अभियान शुरू होना चाहिए।
संजय निरुपम@sanjaynirupam

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या महिलाओं को प्रति माह पैसा देने का वादा चुनावी जीत की गारंटी है?

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या चैंपियंस ट्राफी के लिए चुनी गई भारतीय टीम टूर्नामेंट जीतने में सक्षम दिख रही है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

नेता दे झूठ हाथ से लेते दूजे हाथ,
देकर भारी टैक्स हम मलते अपना हाथ।
मलते अपना हाथ किंतु हम समझ न पाते,
पाय चुनावी लाभ उन्हें हम सह हैं जाते।
पाता वह नुकसान मगर पछ तो है लेता,
कभी स्वयं नुकसान उठाता है ना नेता!
- ओमप्रकाश तिवारी

सतीश चंद्र श्रीवास्तव
संपादकीय प्रभारी, रायपुर

छत्तीसगढ़ डायरी

नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों में परीक्षा

राज्य और केंद्र में सत्ता प्राप्ति के बाद भाजपा के समक्ष कांग्रेस के दबदबा वाले नगरीय निकायों और पंचायतों के चुनावों में भी सफल होने की चुनौती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ ही लगातार दूसरी बार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चुने गए किरणदेव सिंह के लिए यह कठिन परीक्षा होगी। रविवार को कैबिनेट बैठक की घोषणाओं के साथ स्पष्ट हो गया कि किसानों, गरीबों, महिलाओं और अन्य लोक हितकारी योजनाओं के साथ भाजपा स्थानीय निकाय चुनाव के मैदान में उतरने जा रही है। महतारी वंदन योजना को पार्टी पहले ही महिलाओं के बीच अपनी मजबूत पकड़ का आधार मान रही है। दूसरी तरफ रविवार को ही कांग्रेस की नगरीय निकाय घोषणा पत्र समिति की बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने दावा किया कि पार्टी का घोषणा पत्र जन आकांक्षाओं को पूरा करने वाला होगा। इन सबके बीच आरक्षण पर और बवाल करने का नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत के आह्वान ने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है।

जिला पंचायतों में अनुसूचित जनजाति और जाति के हितों को साधते हुए भाजपा पूरी तैयारी में है। उम्मीद की जा रही है कि सोमवार को घोषणा के साथ ही 24 फरवरी को बजट सत्र शुरू होने के पहले चुनावी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 50 प्रतिशत की सीमा के निर्धारण के आलोक में आरक्षण की व्यवस्था में बदलाव के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज से लेकर सभी छोड़े-बड़े कांग्रेस नेता प्रदेश सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के साथ धोखा और अन्याय की बात कर रहे हैं। कार्यकाल समाप्त होने के कारण महापौर और पालिका अध्यक्षों के स्थान पर प्रशासक नियुक्त किए जा चुके हैं। कांग्रेस इसे मुद्दा बनाने में जुटी हुई है। नेता प्रतिपक्ष ने राज्य चुनाव आयोग से साथ ही सरकार को भी पत्र लिखकर समय से चुनाव नहीं हो पाने के लिए घेरा है। जिला पंचायत अध्यक्ष का एक भी पद अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित नहीं होने को कांग्रेस ने मुद्दा बनाया है तो मुख्यमंत्री अरुण साव के साथ ओबीसी मंत्री टंकराम वर्मा और लक्ष्मी राजवाड़े ने मोर्चा संभाल लिया है। पेशे से वकील साव ने दावा किया कि प्रदेश के 33 में से कुल 20 जिलों में पंचायत अध्यक्ष के पद एससी व एसटी के लिए पहले ही आरक्षित हैं। यही 50 प्रतिशत की सीमा से कहीं अधिक है। बस्तर और जशपुर क्षेत्र सहित प्रदेश के 16 जिलों में अनुसूचित क्षेत्र में आने के कारण एसटी आरक्षण हैं तो चार जिलों में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण है। प्रदेश में 14 नगर निगमों, 53 नगर पालिकाओं और 125 नगर पंचायतों में चुनाव होते हैं।

सवती जिले में नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देते विष्णुदेव साय। नईदुनिया

इधर प्रदेश के शराब घोटाले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद इस बात के संकेत दिए जाने लगे हैं कि अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कार्रवाई की जद में आ सकते हैं। लखमा ने स्वयं के अनपढ़ होने का बहाना बनाया है तो फाइलों पर लखमा के सथ ही बघेल के हस्ताक्षर की भी बात सामने आ रही है। प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड का नाम भी घोटाले के मास्टर माइंडों की सूची में जोड़ा जा चुका है। इस मामले में पहले ही एपी त्रिपाठी और अनवर ढेबर सहित कई अधिकारी और कारोबारी जेल में है। लखमा की गिरफ्तारी के बाद दो कांग्रेस विधायक जेल में हैं। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि स्थानीय निकाय चुनाव को प्रभावित करने के लिए ही विधायक लखमा की गिरफ्तारी कराई गई है।

इस तरह स्थानीय निकाय चुनाव ही प्रदेश में चर्चा के केंद्र में है। रविवार को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट के निर्णय भी इससे प्रेरित माने जा रहे हैं। प्रदेश के 27 लाख किसानों को फरवरी के पहले सप्ताह में 800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान की अंतरराशि के भुगतान करने का निर्णय ले लिया गया है। इसी के साथ 'मोदी की गारंटी' के तहत 5.62 लाख भूमिहीन श्रमिकों को भी प्रति वर्ष 10-10 हजार रुपये भुगतान की घोषणा कर दी गई है। 70 लाख महिलाओं को पहले ही प्रत्येक महीने एक हजार रुपये का भुगतान किया जा रहा है। इधर नियम और शर्तों में ढील देते हुए पीएम आवास योजना का दायरा भी बढ़ा दिया गया है और 1.32 लाख पीएम आवासों के लिए अनुदान राशि भी स्वीकृत कर दी गई है।

प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए पृष्ठभूमि तैयार है। कांग्रेस यदि कानून व्यवस्था को मुद्दा बना रही है तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध भाजपा की कार्रवाई भी चर्चा के केंद्र में है। पत्रकार मुकेश चंद्रकार की हत्या के आरोप में ठेकेदार व कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी के बाद पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की प्रक्रिया उम्मीद जगा रही है कि भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध शून्य सहिष्णुता की नीति जारी रहेगी।

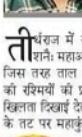

राकेश पांडेय
संपादकीय प्रभारी, प्रयागराज

सनातन परंपराओं से साक्षात्कार

तीर्थराज में संवरता महाकुंभ शनैः शनैः महाआकार लेता जा रहा है। जिस तरह ताल में स्थित कमल सूर्य की रश्मियों की प्रखरता के साथ-साथ खिलता दिखाई देता है, उसी तरह संगम के तट पर महाकुंभ की आभा भगवान भास्कर के मकर में चक्रमण के साथ ही बढ़ती जा रही है। इस बार का महाकुंभ अद्वितीय होगा, इसमें कोई शंका नहीं थी। प्रत्येक स्नान पर्व के साथ बढ़ती भीड़ ने इसकी पुष्टि कर दी है। यह अचरज की बात नहीं रही कि पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति के स्नान पर्व पर धर्म और आध्यात्म का समुद्र ज्वार मारते दिखा। पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति पर स्नान करने वाले पांच करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के जन ज्वार ने पिछले सारे आंकड़े भुलवा दिए।

इस बार महाकुंभ में आ रहे जनसमूह ने प्रबंधन में लगे लोगों के माथे पर लकीरें तो डाल दी थीं, लेकिन संगम में डुबकी लगाने वालों की संख्या के पूर्वानुमान और सटीक प्रबंधन के चलते पहले दोनों स्नान पर्व कुशलता से संपन्न हो गए। ऐसा लग रहा था कि संपूर्ण विश्व 'चलो महाकुंभ की ओर' के संकल्प के साथ तीर्थराज पहुंच जाना चाहता है। मकर संक्रांति का स्नान कर विदा होने वालों के लिए रेलवे को 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन का संचालन करना पड़ा। रेलवे स्टेशन पर इस बार पूर्व कुंभों की तुलना में बहुत अधिक भीड़ थी, लेकिन कुशल प्रबंधन से सब कुशलतापूर्वक संपन्न हो गया। जबकि 2013 में इसी प्रयागराज जंक्शन पर बड़ा हादसा हुआ था।

45 दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ का पहला चरण बेहद अद्भुत रहा। अब तैयारी 29 जनवरी को होने वाले मौनी अमावस्या के स्नान की है जो किसी भी कुंभ का बृहत्तर स्नान माना जाता है। यह स्नान विश्व के परिदृश्य पर एक अद्भुत दृश्य उकेरता है, जब मौन का संकल्प बांधे करोड़ों लोग गंगा जी की ओर बढ़ते हैं। यह वो समय होता है जब शब्द नहीं पदचाप गूंजते हैं। पदचापों की बढ़ती धमक के साथ ही बढ़ती रहती है प्रबंधन से जुड़े लोगों के हृदय की धड़कनें। यह दोनों हृदय में गंगा-स्तुति करते रहते हैं, एक के हृदय की स्तुति मोक्ष को लेकर होती है तो दूसरे के हृदय में उन्हें सकुशल मोक्ष प्रदान करने की याचना के साथ मोक्षदायिनी की अभ्यर्थना होती रहती है। वैसे भी अनुमान है कि मौनी अमावस्या पर इस बार आठ से दस करोड़ लोग लोगों की जुटान होगी।

निहारते बन रही है कल्पवासियों की कुटिया। श्रद्धालुओं को ठहरने के लिए बिक्रा कर रहा उनके तंबुओं का संसार। महाकुंभ है तो दस लाख से अधिक श्रद्धालु कल्पवास कर रहे हैं। एक बेला सात्विक भोजन और दो से तीन बेला स्नान और शेष समय में प्रभु का ध्यान। मध्यकाल को ये तट पर चल रहे प्रवचनों के श्रवण व प्रभु की लीलाओं का मंचन देखने में रमे मिलते हैं। बड़ी संख्या में कल्पवासी तो ऐसे हैं जो दशकों से कल्पवास करते आ रहे हैं। कुछ तो पिछली पीढ़ियों का अनुसरण करते हुए प्रतिवर्ष कल्पवास करने आते हैं। गंगा के तट पर लगा मेला इन्हीं कल्पवासियों से सुवासित रहता है।

महाकुंभ अब चरम की ओर अग्रसर है। सनातन की विभिन्न शाखाओं की सहभागिता और इतने कड़ाके की ठंड में भी करोड़ों के स्नान-ध्यान, तप-दान के उत्साह ने विश्व को रोमांचित कर रखा है। सर्वाधिक आकर्षण नागाओं का संसार है जिसे गूढ़वादित करने में लोग आज तक असफल ही रहे हैं। अखाड़ों के इस रहस्यमयी संसार को जानने की उत्कंठा संपूर्ण विश्व को संगम के तट पर खींच लाई है। दुनियादारी से अप्रभावित ये नागा-साधु निर्लिप्त और निर्विकार भाव से अपने उस कार्यों को संपादित करने में लीन हैं जिन्हें शेष-विश्व अविश्वसनीय कहता आया है।

इस बार के महाकुंभ की विशेषता : सनातनियों में इस तथ्य का बोध है कि भारतीय संस्कृति और सनातनी-मूल्यों को अगली पीढ़ी में बीजरोपण करने की ललक है। बड़ी संख्या में लोग अपने साथ अपने बच्चों को लेकर पहुंच रहे हैं, ताकि उन्हें सनातन की महान परंपराओं से साक्षात्कार कराया जा सके। सभी जुटे हैं इस अनुष्ठान में कि ये पीढ़ी सनातनी परंपरा से तनिक भी विमुख न होने पाए। यह महाकुंभ एक ऐसा सुअवसर है जिसमें उन्हें अवगत कराया जा सके कि संपूर्ण विश्व किस विस्मय से सनातनी परंपराओं की अनुभूति कर रहा है और इसका सहभागी बनने को आतुर है।

इस कालखंड का महत्वपूर्ण सनातनी उत्सव हो और कर्मयोगी अमृत स्नान को न आएं, यह कैसे संभव है। दिनकर सनातनियों में प्रतिदिन नई ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। उस ऊर्जा से सिक्त होकर प्रदेश को गतिशीलता देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ नगर में 22 जनवरी को अपने मंत्रिमंडल की बैठक करने जा रहे हैं। सभी स्नान भी करेंगे। फरवरी की दस तारीख प्रस्तावित है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के आगमन की। स्वयं द्वारा शासित राष्ट्र के नागरिकों के उत्साहवर्धन, सनातन के बढ़ते रथ को गतिमान करने और मान गंगा से राष्ट्र के सुख-समृद्धि की कामना के उद्देश्य के साथ किया जाने वाला उनका पूजन-अर्चन सनातन के इतिहास की एक सुनहरी बानगी होगा।

प्रयागराज महाकुंभ में नई पीढ़ी को सनातन की परंपराओं से परिचित कराते अभिभावक। जागरण

****

दैनिक जागरण
विचारों के धागों से ही चरित्र रूपी वस्त्र का निर्माण होता है

शांति की संभावना

वह केवल पश्चिम एशिया ही नहीं, बल्कि विश्व शांति के लिए एक शुभ संकेत है कि इजरायल और फलस्तीनी संगठन हमास के बीच समझौता हो गया। इस समझौते के तहत हमास उन बंधकों को छोड़ेगा जिन्हें उसने सात अक्टूबर 2023 के एक भीषण हमले में इजरायल में घुसकर अपहृत कर लिया था। इसके बदले इजरायल फलस्तीनी कैदियों को छोड़ने के साथ गाजा पट्टी से पीछे हटेगा और अपनी सैन्य कार्रवाई रोकेगा। इस समझौते के तीन चरण हैं। समझौता पूरी तरह तभी लागू हो पाएगा जब पहले और दूसरे चरण को पूरा करने में सफलता मिलेगी। देखना यह है कि ऐसा हो पाता है या नहीं। समझौते के पूरा होने और उसके कायम रहने के आसार इसलिए कम हैं, क्योंकि एक ओर जहां यह दिख रहा है कि हमास इजरायल को नष्ट करने की अपनी सनक का परित्याग नहीं करने वाला। वहीं दूसरी ओर इजरायल सरकार यह मानती है कि हमास के खात्मे के बगैर शांति संभव नहीं। इसको भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि दोनों पक्षों के बीच यह समझौता पहले भी हो सकता था यदि हमास बंधकों को छोड़ने पर राजी हो जाता, लेकिन वह इजरायल पर कठोर शर्तें थोपता रहा। हमास की इस जिद के चलते गाजा पट्टी के 46,000 से अधिक लोग मारे गए और लाखों को पलायन के लिए विवश होना पड़ा।

यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि यह समझौता इसीलिए हो सका, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं और वह हर हाल में दोनों पक्षों के बीच समझौता होते देखना चाहते थे। अच्छा होता कि ऐसी ही प्रतिबद्धता राष्ट्रपति जो बाइडन दिखाते। वह शांति और समझौते की बात तो करते रहे, लेकिन न तो हमास पर दबाव बना सके और न ही उसे समर्थन देने वाले कतर पर। बाइडन इजरायल पर भी इसके लिए कोई दबाव नहीं बना सके कि वह ईंट का जवाब पत्थर से देने की अपनी नीति छोड़े और अपनी सैन्य कार्रवाई में आम लोगों को निशाना न बनाए। इसके स्थान पर वह इजरायल को हर तरह की सैन्य सहायता देते रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि इजरायल यह जानते हुए भी गाजा पर अंधाधुंध हमले करता रहा कि वह इस तरह हमास को समाप्त नहीं कर सकता। निश्चित रूप से पिछले 15 महीनों में गाजा में जो तबाही हुई, उसके लिए हमास ही अधिक जिम्मेदार है। यदि उसने इजरायल में घुसकर आतंकी हमले को अंजाम नहीं दिया होता तो संभवतः इतना अधिक विनाश नहीं हुआ होता। चिंताजनक यह है कि समझौते के बाद भी हमास और इजरायल के बीच अविश्वास दिख रहा है। यह स्थिति कभी भी समझौते के भंग होने का कारण बन सकती है। इसलिए यह आवश्यक है कि सभी पक्ष यह सुनिश्चित करें कि ऐसा न होने पाए।

विकास की पहल

आने वाले वित्तीय वर्ष में नए आरओबी, बाइपास, फुल से लेकर रिंग रोड तक के लिए बजट बिहार के विकास की गति को और तेज करने में सहायक सिद्ध हो सकेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा में जिन आधारभूत संरचनाओं पर जोर दे ते हुए अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिया है, उससे संबंधित क्षेत्र की आर्थिकी को बल मिलने की संभावना प्रबल हो गई है। यह एक सराहनीय पहल है, जिस पर तीव्र गति से कार्य किया जाना चाहिए। राज्य में सड़कों के निर्माण से यातायात सुगम हुआ है, पर भविष्य को देखते हुए अभी से आधारभूत संरचनाओं को और अधिक बढ़ाना भी समय की मांग है। यह एक दूरदर्शी सोच है, ताकि उन जरूरतों को देखते हुए अभी से इसके लिए तैयारी कर ली जाए। बेतिया में नए बाइपास की घोषणा के साथ ही इनरवा से बाल्मीकिनगर तक दोनों कैनाल पर सड़क निर्माण का जो निर्देश दिया गया है, वह इन क्षेत्रों के लिए बड़ी जरूरत है। खगड़िया में एनएच-31 से बाइपास तक बूढ़ी गंडक पर पुल एवं पहुंच पथ के निर्माण की घोषणा से भी इस क्षेत्र को बहुत लाभ होगा। सारण में नए एलिवेटेड सड़क निर्माण के साथ ही सारण तटबंध पर सिंगल लेन सड़क को डबल लेन में परिवर्तित करने की पहल जाम से छुटकारा में सहायक सिद्ध हो सकेगी। आबादी बढ़ रही है और उस हिसाब से नई बसावट भी हो रही है। इसे ध्यान में रखते हुए योजना जरूरी है, ताकि आगे चलकर समस्या उत्पन्न नहीं हो।

> अधिकारियों का दायित्व है कि योजनाओं का कार्यान्वयन समय पर हो जाए, ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके

ट्रंप से उम्मीदें और चिंताएं

शिवकांत शर्मा

ट्रंप के मित्र और शत्रु देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती उनकी नाटकीय अप्रत्याशितता की है जो नीति निर्माताओं के लिए बहुत बड़ा जोखिम है

अमेरिका के 47वें और सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति बनने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को लेकर भारत समेत पूरे विश्व में उत्सुकता एवं आशंका का माहौल है। यूरोपीय विदेश संबंध परिषद ने आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से 24 देशों के नागरिकों का एक सर्वेक्षण कराया था, जिसमें भारत, चीन, पश्चिम एशिया, ब्राजील, तुर्किए और दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने ट्रंप की सत्ता में वापसी का स्वागत किया। उनका मानना था कि ट्रंप प्रशासन उनके देशों और विश्व शांति के लिए अच्छा साबित होगा। ट्रंप की सबसे अधिक लोकप्रियता भारत में दिखी जहां 80 प्रतिशत से अधिक लोगों ने उनकी वापसी को अच्छा माना। इसके विपरीत यूरोप, दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे अमेरिका के मित्र देशों के लोगों ने ट्रंप की वापसी पर चिंता जताई। सर्वेक्षण से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अमेरिका के पारंपरिक मित्र देशों के लोग ट्रंप की बरसों पुरानी संधियों और गठबंधनों को ताकालिक लाभ के तराजू पर तौल कर देखने की नीति को नापसंद करते हैं। अपने पिछले कार्यकाल में वह नाटो गठबंधन, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान की सुरक्षा से लेकर संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न संस्थाओं में दूसरे देशों की तुलना में अमेरिका के बड़े योगदान की उपादेयता पर सवाल उठा चुके हैं। वह उसकी कीमत तक मांग चुके हैं।

ट्रंप अमेरिका की बाजार शक्ति को व्यापारिक और सामरिक सौदेबाजी का सबसे बड़ा हथियार मानते हैं और आयात शुल्क लगाने की धमकियां देते रहते हैं। उनके मित्र और शत्रु देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती उनकी नाटकीय अप्रत्याशितता की है जो नीति निर्माताओं के लिए बहुत बड़ा जोखिम है। इन्हीं अब उन्होंने कुछ और नई चुनौतियां जोड़ दी हैं। अमेरिका का वफादार नाटो मित्र डेनमार्क इससे परेशान है कि वह उसके उत्तरध्रुवीय द्वीप ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं। पड़ोसी कनाडा इससे चिंतित है कि वह उनकी शर्तें न मानने पर उसे अमेरिका का 51वां राज्य बनने पर विवश करने की बात कर रहे हैं। मध्य अमेरिकी देश पनामा इसे लेकर डरा हुआ है कि चीनी खतरे की दलील देकर वह पनामा नहर छीनना चाहते हैं, जो उस देश की आय का प्रमुख स्रोत है। ट्रंप के अरबपति मित्र एलन मस्क ने तो यूरोप में समाजवादी राजनीति के सफाए के लिए ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों में अतिदक्षिणपंथी पार्टियों को धन से लेकर मीडिया का समर्थन देना शुरू कर दिया है। जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान इस असमंजस में हैं कि उनकी सुरक्षा की

अवधेश राजपूत

न जाने कितनी कीमत मांगी जाएगी।

ऐसी चुनौतियां भारत के समक्ष भी हैं। यद्यपि राष्ट्रपति ट्रंप चीन को अमेरिका की सबसे बड़ी आर्थिक एवं सामरिक चुनौती के रूप में देखते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने प्रशासन में फ्लोरिडा के चीन विरोधी सीनेटर मार्को रूबियो को विदेश मंत्री और दूसरे चीन विरोधी सीनेटर माइकल वाल्ट्स को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया है। संयोग से ये दोनों भारत समर्थक रहे हैं। रूबियो ने भारत-अमेरिका सैन्य-रणनीति के समझौते का प्रस्ताव सदन में रखा था और वाल्ट्स भारत काकस के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसलिए नए ट्रंप प्रशासन से यह उम्मीद की जा सकती है वह भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी रणनीति की धुरी बनाकर चलेगा और चीनी वर्चस्व की काट में भारत का सहयोग करेगा। इस वर्ष भारत को क्वाड शिखर बैठक की मेजबानी भी करनी है जिसमें भाग लेने ट्रंप के भारत आने की उम्मीद भी है। उनका दौरा रिश्तों को और प्रगाढ़ करने में सहायक सिद्ध हो सकता है।

भारत और दूसरे एशियाई देशों में ट्रंप की लोकप्रियता का एक कारण निर्णायक फैसले लेने की उनकी प्रवृत्ति भी हो सकती है। वह इस्लामी आतंकवाद जैसे मुद्दों पर सीधी बात करते हैं, जिससे कई बार जटिल समस्याएं भी हल हो जाती हैं। गाजा में सवा साल की लड़ाई के बाद हुआ युद्धविराम उसकी एक मिसाल है। हालांकि यूक्रेन में तीन साल से चल रही लड़ाई का हल उतना आसान नहीं दिखता। फिर भी, जेलेंस्की और पुतिन के हालिया बयानों से बातचीत शुरू करने की इच्छा के संकेत मिलने लगे हैं। ट्रंप यूक्रेन की सैन्य सहायता बंद करना और रूस के प्रतिबंध हटाना चाहते हैं जिससे अमेरिका को व्यापार लाभ हो सके। हकीकत यह है कि अमेरिका की सैन्य मदद के बिना यूक्रेन और नाटो में टिक पाने का दम नहीं और ट्रंप अमेरिका को दूसरों के युद्धों में उलझाए रखने के मूड में नहीं हैं। यह दीगर बात है कि वह ग्रीनलैंड और पनामा नहर को अपनी धौंस दिखा कर हासिल करना चाहते हैं।

दूसरी ओर, उनकी आर्थिक धौंस वाली नीति दुनिया के समक्ष बड़ी चुनौती खड़ी कर सकती है। चीनी आयातों पर 60 प्रतिशत और बाकी देशों के आयातों पर 10 प्रतिशत संभावित शुल्क से अमेरिका में भी महंगाई बढ़ेगी। अमेरिकी केंद्रीय बैंक को ब्याज दरें घटाने में देरी करनी पड़ेगी जिससे निवेश कम होगा। जिन देशों के आयातों पर शुल्क लगेगा उन्होंने यदि जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी चीजों पर शुल्क लगाना शुरू किया तो व्यापार युद्ध शुरू हो जाएगा। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी की आशंका बढ़ जाएगी जो पहले से ही सुस्त चल रही है। भारतीय शेयर बाजार में तो इसके आसार मात्र से ही गिरावट शुरू हो गई है। आप्रवासन पर लगने वाले अंकुश का तो खास असर भारत पर शायद न हो, क्योंकि भारत से जाने वाले अवैध आप्रवासियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है, लेकिन एच1बी वीजा पर जाने वाले पेशेवरों और पढ़ने जाने वाले छात्रों के बीजा पर स्वयं ट्रंप और कांग्रेस के सलाहकार मस्क, रामास्वामी और श्रीराम कृष्णन अंकुश लगाने के पक्षधर नहीं हैं। एक ऐसी समय जब भारत को अपनी विकास की गति बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक माल बेचने और निवेश आकर्षित करने की सख्त जरूरत है, उस समय आयात शुल्क और व्यापार युद्ध का खतरा गंभीर चुनौती खड़ी करता है।

(लेखक बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक हैं)
response@jagran.com

दिल्ली में आप और कांग्रेस का द्वंद्व

उमेश चतुर्वेदी

कांग्रेस समझ गई है कि उसके वजूद के लिए आप बड़ा खतरा है, इसलिए दिल्ली में उसके खिलाफ आक्रामक हो गई है

कांग्रेस दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुछ उसी अंदाज में आम आदमी पार्टी के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है, जैसा उसने 2013 में किया था। कांग्रेस का आक्रामक रुख 2015 के विधानसभा चुनावों में भी रहा, लेकिन आप की ऐसी आंधी चली कि कांग्रेस के बुलंद इतिहास और राजनीति, दोनों को एक साथ बहा ले गई। आप की आंधी में सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को ही उठाना पड़ा। इसके बावजूद पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उसी आम आदमी पार्टी का साथ दिया, जिसका पूरा वजूद ही उसी के विरोध पर स्थापित हुआ है। राष्ट्रीय राजनीति में नरेन्द्र मोदी की अजेय बढ़त पर ब्रेक लगाने के मकसद से 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर आइएनडीआइए के नाम से विपक्षी दलों का जो मोर्चा बना, उसमें तेलंगाना की भारत राष्ट्र समिति को छोड़कर अधिकांश विपक्षी दल शामिल हुए। उनकी समन्वित ताकत ने भाजपा को कुछ नुकसान जरूर पहुंचाया, लेकिन उसे इतना कमजोर नहीं कर पाई कि भाजपा सत्ता से चूक जाए। इसके लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार बताते हुए सबसे पहले उनके नेतृत्व पर ममता बनर्जी की ओर से सवाल उठाया गया। उसके बाद जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 'आइएनडीआइए को लोकसभा चुनावों के लिए बनाया गया था, लिहाजा इसे भंग कर देना चाहिए।' फिर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 'दिल्ली चुनाव के लिए आइएनडीआइए नहीं है।' एक तरह से उन्होंने कांग्रेस को विधानसभा चुनावों में अलग-थलग करने की कोशिश की।

यह सच है कि केजरीवाल के साथ से कांग्रेस को फायदे के बजाय नुकसान ही होता रहा है। केजरीवाल की पार्टी अगर आज पंजाब और दिल्ली की सत्ता पर काबिज है तो वह भाजपा की कीमत पर नहीं है। दोनों ही राज्यों में उसने कांग्रेस की न सिर्फ जगह छीन ली है, बल्कि उसका वोट बैंक भी हथिया लिया। गोवा में भी बेशक आम आदमी पार्टी को कम वोट मिले हों, लेकिन वह भी उसी के वोट बैंक का हिस्सा हैं। गुजरात में भी आप को मिले वोट कांग्रेस के वोट बैंक का ही हिस्सा हैं। 2008 में दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई कांग्रेस अगले ही विधानसभा चुनाव यानी 2013 में 24.6

राहुल गांधी ने अपनाए आक्रामक तेवरां फाइल

प्रतिशत वोट पाकर तीसरे स्थान पर खिसक गई। फिर महज दो साल बाद ही हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट बैंक 9.7 प्रतिशत पर पहुंच गया और 2020 के चुनावों में उसका जैसे वजूद ही मिट गया। उसे महज 4.26 प्रतिशत वोट मिले। इस बीच आम आदमी पार्टी 54 प्रतिशत से ज्यादा वोट पाकर अजेय दिखने लगी। अव्वल तो कांग्रेस की उसी बखत सचेत होना चाहिए था। कांग्रेस की राजनीतिक दुश्मन नंबर वन आप को होना चाहिए था, मगर वह उसके साथ ही गलबहियां करने लगी थी।

लगता है कांग्रेस समझ गई कि उसका वजूद केजरीवाल के रहते बच नहीं सकता इसीलिए दिल्ली के चुनावों में वह आप के खिलाफ आक्रामक दिख रही है। जिस शराब घोटाले को लेकर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जमानत पर हैं, सबसे पहले दिल्ली कांग्रेस के नेता अजय माकन ने उसे उजागर किया था। माकन कुछ दिनों पहले केजरीवाल के खिलाफ एक और तथ्य सामने लाने वाले थे, लेकिन उनकी प्रेस कांफ्रेंस बिना कोई कारण बताए रद कर दी गई। कहा जा रहा है कि इसके लिए केजरीवाल ने डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन को फोन किया और कांग्रेस की रोकने के लिए गुहार लगाई। आपसी राजनीतिक सहयोग और दबाव की वजह से राजनीतिक दलों को कई बार ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। कांग्रेस चूंकि तमिलनाडु की सत्ता में भागीदार है, लिहाजा उसे भले ही चुप रहना पड़ा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह हमेशा के लिए चुप रहेगी।

राहुल गांधी ने दिल्ली की चुनावी रैली में इसकी शुरुआत कर भी दी है। राहुल ने कहा कि 'जब दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी और केजरीवाल आए, तब वह क्या कहते थे। उन्होंने भ्रष्टाचार मिटाने, दिल्ली को पेरिस बनाने का वादा किया था, लेकिन क्या हो रहा है। प्रदूषण इतना बढ़ रहा है कि बाहर निकलना मुश्किल है। महंगाई बढ़ रही है। केजरीवाल ने कहा था कि वह भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। क्या अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में भ्रष्टाचार मिटा दिया? जैसे प्रचार मीडिया में मोदी जी करते हैं, झूठे वादे करते हैं, वैसी ही रणनीति केजरीवाल जी की भी है। दोनों में कोई फर्क नहीं है।' राहुल ने ऐसा कहकर एक तरह से केजरीवाल के मर्म पर चोट की है। उनका वादा पारंपरिक राजनीति के इतर स्वच्छ राजनीति करने, भ्रष्टाचार मिटाने और दिल्ली को चमकाने का था। राहुल ने उनके तीनों ही वादों पर सवाल उठा दिया है। इस हमले से केजरीवाल कितना तिलमिलाए हैं, वह उनके जवाबी हमले से पता चलता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राहुल की लड़ाई कांग्रेस बचाने की लड़ाई है और उनकी यानी केजरीवाल की लड़ाई देश बचाने की लड़ाई है।

अपने अस्तित्व के लिए कांग्रेस के लिए जरूरी है कि वह पहले आप से अपना वोट बैंक वापस ले। केजरीवाल भी जानते हैं कि उनका वजूद कांग्रेस की कीमत पर ही है। भाजपा का अपना ठोस वोट बैंक है। इसलिए अब उन्हें कांग्रेस भी अपना बड़ा दुश्मन नजर आने लगी है। यही कारण है कि उनके निशाने पर कांग्रेस भी है। इस जंग में कांग्रेस अगर अपना पारंपरिक समर्थन आधार हासिल करती है तो यर्कानन दिल्ली विधानसभा के लिए केजरीवाल की राह कठिन होगी।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

भक्ति भाव

भक्ति भाव से होता है। भाव के अभाव में भक्ति का रंग नहीं खिलता। भाव प्रबल हो तो भगवत् साक्षात्कार भक्त को जरूर होता है। भक्ति के पथ से ही व्यक्ति भगवान को प्राप्त करने में सफल होता है। भक्ति से ही भगवान रीझते हैं और भक्त को दर्शन देते हैं। भगवान से कुछ छुपा नहीं रहता है, वह तो अंतर्यामी हैं। कौन सच्ची भक्ति करता है कौन झूठा, उनको सब पता है। ध्रुव, प्रह्लाद, मीरा, रैदास, सूर, तुलसी, चैतन्य महाप्रभु आदि ने भक्ति का अप्रतिम उदाहरण सामने रखा।

भक्ति नित्य-प्रतिदिन का नियम है। भक्ति के नौ प्रकार हैं-श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। भोजन नित्य करते हैं तो भजन भी नित्य नियमपूर्वक करें। जिसने भक्ति रस का स्वाद चखा है, उसे फिर कोई और रस नहीं भाता। मानव जीवन भक्ति हेतु मिलता है। भक्ति के बिना यह जीवन सार्थक नहीं होता। दुर्लभ मानव जीवन पाकर भी भक्ति न की तो दुर्भाग्य है। भक्त की भक्ति इतिहास रचती है और भगवान को प्रकट होने के लिए बाध्य कर देती है। भगवान को बांधने में कोई इस सृष्टि में समर्थ नहीं, पर वह भक्त की भक्ति, प्रेम से बंध जाते हैं। भगवान अपने भक्तों की सदा संकटों से रक्षा करते हैं।

भक्त को भगवान से प्रेम होता है, पर अभक्त को संसार से। जिसे संसार से प्रेम है, वह भक्ति नहीं कर पाता और संसार के माया-मोह के कीचड़ एवं लोभ-लालच के फंदे में आकंठ डूबकर आजीवन दुख भोगता है। जो भक्ति करता है, उसे भगवान का आशीष, कृपा, संरक्षण जरूर मिलता है। भक्ति मार्ग में पग-पग पर परीक्षा होती है। जिनकी श्रद्धा, विश्वास, समर्पण प्रभु के चरणों में है, उनकी नैया पार होती है, लेकिन जो भक्ति नहीं कर पाते, उनकी नैया बीच भंवर में डूब जाती है। उन्हें आवागमन से छुटटी नहीं मिलती। भक्ति से ही जीवन में मुक्ति मिलती है। भक्ति भक्त को भव से पार करती है।

मुकेश ऋषि

ड्रोन से बदलेगा कृषि का स्वरूप

रंजना मिश्रा

ड्रोन तकनीक किसानों को अधिक कुशल, टिकाऊ और लाभदायक तरीके से खेती करने में मदद कर रहीहै

भारत जैसे देश में कृषि अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। ड्रोन तकनीक कृषि क्षेत्र में एक गेम-चेंजर साबित हो रही है। ड्रोन तकनीक न केवल किसानों के लिए, बल्कि पूरे कृषि क्षेत्र के लिए अपार संभावनाएं प्रदान करती है। यह किसानों को अधिक कुशल, टिकाऊ और लाभदायक तरीके से खेती करने में मदद कर रही है। सरकार, निजी क्षेत्र, अनुसंधान संस्थानों और किसानों के संयुक्त प्रयासों से ड्रोन तकनीक का उपयोग और बढ़ेगा। यह भारतीय कृषि को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी, जिससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी और किसानों की आय में वृद्धि होगी।

ड्रोन को मानवरहित हवाई वाहन भी कहा जाता है। आधुनिक सेंसर, कैमरों, जीपीएस और अन्य तकनीकों से लैस होते हैं। ये कृषि कार्यों में विभिन्न तरीकों से उपयोगी साबित हो रहे हैं। वे रोगग्रस्त पौधों, कीटों के प्रकोप, खरपतवारों की उपस्थिति और पोषक तत्वों की कमी वाले क्षेत्रों की सटीक पहचान कर सकते हैं। इससे किसानों को समय पर उचित कदम उठाने, जैसे कि लक्षित कीटनाशक या उर्वरक का उपयोग करने और नुकसान को कम करने में मदद मिलती है। ड्रोन द्वारा एकत्रित डाटा से उपज का अनुमान भी लगाया जा सकता है, जिससे किसानों को फसल की कटाई और विपणन की योजना बनाने में मदद मिलती है। ड्रोन पारंपरिक तरीकों की तुलना में बहुत कम समय में एक बड़े क्षेत्र में कीटनाशक और उर्वरक का सटीक छिड़काव कर सकते हैं। यह न केवल समय और श्रम बचाता है, बल्कि रसायनों के उपयोग को भी अनुकूलित करता है, जिससे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव कम होता है। ड्रोन द्वारा सटीक छिड़काव से रसायनों की बर्बादी भी कम होती है और लागत में कमी आती है। ड्रोन भूमि सर्वेक्षण और मानचित्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह जानकारी किसानों को खेत की सीमाओं को परिभाषित करने, ढलान और जल निकासी का विश्लेषण करने, सिंचाई प्रणालियों को डिजाइन करने और अन्य कृषि गतिविधियों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करती है। कुछ विशेष रूप से डिजाइन किए गए ड्रोन बीजों को फैलाने और पौधरोपण करने में भी सक्षम हैं, जिससे बोआई और पौधरोपण की प्रक्रिया को तेज और अधिक कुशल बनाया जा सकता है। ड्रोन का उपयोग मवेशियों की गतिविधियों की निगरानी के लिए भी किया जा सकता है। ड्रोन खेतों में नमी के स्तर का आकलन भी कर सकते हैं, जिससे किसानों को सिंचाई की योजना बनाने और पानी के उपयोग को अनुकूलित करने में मदद मिलती है। इससे पानी की बचत होती है और फसल की उपज में सुधार होता है।

कुल मिलाकर एआइ, मशीन लर्निंग और इंटरनेट आफ थिंग्स जैसी तकनीकों के साथ ड्रोन का एकीकरण कृषि को और भी अधिक कुशल और टिकाऊ बना देगा।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

निम्न स्तर की राजनीति

चुनावों के वर्तमान परिदृश्य में राजनीति का स्तर निम्न से निम्नतर होता जा रहा है। बात कुछ होती है, परोस कुछ और दिया जा रहा है। कर्मान में टीवी चैनलों की राजनीतिक चर्चाओं में तो इसका और भी बुरा हाल है। टीका टिप्पणी आपस में वक्ताओं के मध्य होती है, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई वक्तव्य व्यक्ति विशेष के संदर्भ में भी हो तो भी वह अपनी जाति-प्रजाति एवं पूरी कौम को इस प्रकार इससे जोड़ देता है, जैसे संपूर्ण कौम का अकेला वही रहनुमा है। संबंधित राजनीतिक दल भी झूठ को सच स्थापित करने में जुट जाते हैं। ऐसे राजनेता या राजनीतिक दल जनता का भला क्या करेंगे?

जय प्रकाश अग्रवाल, दिल्ली

सरकारी कामकाज की गुणवत्ता

आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर ही सरकार द्वारा आठवें वेतन आयोग का गठन किया गया है। दिल्ली में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों की तादाद ज्यादा है। सातवें वेतन आयोग के समय ही सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अगला वेतन आयोग गठित नहीं होगा। कर्मचारियों की कार्यशैली की संतुष्टि से ही उनकी वेतन वृद्धि होगी। संतुष्टि प्रणाली में काफी विसंगतियां उत्पन्न होने की शिकायतें मिलने लगीं। सरकारी कर्मचारियों पर यह आरोप उचित है कि उनकी कार्यशैली से सरकार की योजनाएं सालों-साल लटकी रहती हैं और ये सरकारी दफ्तरों को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाए हुए हैं। सरकार ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों से कड़ाई से निपटती है। इसी परिणाम का फल है कि आज सीबीआइ, ईडी आदि जांच एजेंसियों द्वारा देश के विभिन्न अदालतों में जो मामले दाखिल किए गए हैं, उनमें लगभग नब्बे प्रतिशत सरकारी सेवकों के विरुद्ध हैं। कर्मचारियों की काम की अकुशलता पर सातवें वेतन आयोग ने अंगुली उठाई थी। इस पर अमल करने के लिए सरकार को कई सुझाव दिए गए थे। बावजूद इसके कतिपय सरकारी सेवकों की कार्यशैली में कोई बदलाव नहीं आया। सरकारी नौकरी मतलब आरामतलबी। इसे समाप्त करने के लिए नए वेतन आयोग को गहनता के साथ इस पर काम करना होगा। कर्मचारियों को भी अब ईमानदारी पूर्वक निष्ठा एवं लगन से समय पर फाइलों का निष्पादन करना होगा ताकि कोई उनपर अंगुली न उठा सके। ऐसी संस्कृति पनपने से भारत को विकसित राष्ट्र बनने की राह आसान हो जाएगी।

युगल किशोर राही, ग्रेटर नोएडा

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक- संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

आठवां वेतन आयोग

गठन को हरी झंडी

केंद्रीय कैबिनेट ने आठवें वेतन आयोग के गठन को हरी झंडी दिखा कर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण का रास्ता साफकर दिया है। केन्द्रीय कैबिनेट द्वारा बजट के पहले आठवें वेतन आयोग के गठन को सहमति देना वेतन एवं पेंशन ढांचे के पुनरीक्षण का महत्वपूर्ण कदम है। इससे 49 लाख केन्द्र सरकार के कर्मचारियों तथा लगभग 65 लाख पेंशनधारियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में लिए गए इस निर्णय में कर्मचारियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार तथा उपभोग बढ़ा कर आर्थिक गतिविधियों को गति देने का लक्ष्य समाहित है। आठवें वेतन आयोग को केन्द्र सरकार कर्मचारियों तथा पेंशनरों के वेतन, भत्ते और पेंशन संशोधन का लक्ष्य दिया जाएगा। इसके लिए संस्तुतियां करने से पहले केन्द्र और राज्य सरकारों तथा अन्य पक्षों से विचार-विमर्श किया जाएगा। आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी। उनकी संस्तुतियां वर्तमान सातवें वेतन आयोग ढांचे का स्थान लेंगी जिसका कार्यकाल 2026 में समाप्त हो रहा है। ऐतिहासिक रूप से वेतन आयोगों का गठन हर दशक में मुद्रास्फीति, आर्थिक प्रगति तथा कर्मचारियों की बदलती वित्तीय आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने रेखांकित किया है कि संशोधित वेतन ढांचा अतिरिक्त खर्च योग्य आय बढ़ा कर उपभोग को बढ़ावा देगा। वेतन और पेंशन बढ़ने से वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च बढ़ने की उम्मीद है जिससे खुदरा व्यापार, रियल इस्टेट व आटोमोबाइल क्षेत्रों में मांग बढ़ने की आशा की जाती है।

उपभोग में इस वृद्धि से उत्पादन और रोजगार में और वृद्धि होगी जिससे अर्थव्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन का चक्र बनेगा। उम्मीद है कि आयोग की संस्तुतियों से केन्द्र सरकार के कर्मचारियों तथा पेंशनरों की आजीविका पर खर्च की समस्या संबोधित होगी तथा उनकी वित्तीय स्थिति बेहतर होगी। हालांकि, वेतन और पेंशन संशोधनों से अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ेगी, पर इससे सरकारी खजाने पर काफी बोझ भी बढ़ेगा। वेतन में बढ़ोत्तरी के कारण बजटीय व्यवस्थाओं में परिवर्तन की आवश्यकता हो सकती है जिसका प्रभाव ढांचागत संरचना तथा कल्याण जैसे अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ सकता है। हालांकि, सार्वजनिक उद्यम-पीएसयू तथा राज्य सरकार के कर्मचारी केन्द्रीय वेतन आयोगों के दायरे से बाहर होते हैं, पर आठवें वेतन आयोग की संस्तुतियां इनके लिए भी बेंचमार्क का काम कर सकती हैं। अनेक राज्य सरकारें तथा पीएसयू अपने वेतनमानों को केन्द्र सरकार के मानकों से जोड़ते हैं अत: इसका व्यापक प्रभाव सभी सार्वजनिक क्षेत्रों पर पड़ेगा। इसका अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। अतिरिक्त खर्च योग्य आमदनी से मांग बढ़ेगी जिससे खासकर आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। मुद्रास्फीति प्रबंधन के लिए संतुलित मौद्रिक नीति जरूरी होगी। इसके साथ ही केन्द्रीय वेतन आयोग के लाभों से पीएसयू कर्मचारियों व 'ग्रामीण डाक सेवकों' को अलग करने से ऐसे ही संशोधनों की मांग तेज होगी। इससे अशांति तथा राजनीतिक दबाव की स्थिति बन सकती है। वेतनों और पेंशनों पर खर्च बढ़ने से सरकार पूंजी-बहुल परियोजनाओं पर निवेश में कठिनाई का अनुभव कर सकती है, जिसका अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालीन प्रभाव हो सकता है। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद आठवें वेतन आयोग की संस्तुतियां मांग और उत्पादन में बढ़ोत्तरी से उत्प्रेरक का काम कर सकती हैं। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी कैबिनेट को इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि उन्होंने सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने के पहले ही आठवें वेतन आयोग की घोषणा कर दी, जबकि अतीत में कई बार कर्मचारी संगठनों को इसके लिए आंदोलन तक करने पड़े थे। आशा करनी चाहिए कि आठवें वेतन आयोग की संस्तुतियां अर्थव्यवस्था में प्रगति के साथ कर्मचारियों व पेंशनरों की समृद्धि में भी महत्वपूर्ण योगदान करेंगी।

आस्था और आधुनिकता का संगम

कुंभ मेला परंपरा और आधुनिकता का संगम है। यह खगोलीय परिघटना को धरती के त्योहारों से जोड़ता तथा उसके प्रति पूरे समुदाय में सकारात्मक भावना पैदा करता है।

राजदीप पाठक
(लेखक, गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति से संबद्ध हैं)

महान महा कुंभ मेला शुरू हो चुका है जो दुनिया का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक समागम है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महान व पवित्र आयोजन के लिए पूरी तैयारी की है जो हर 12 साल बाद होता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व्यक्तिगत रूप से इस आयोजन पर नजर रख रहे हैं। 13 जनवरी, 2025 से शुरू महा कुंभ में आश्चर्यजनक व असाधारण रूप से 45 करोड़ से अधिक लोगों के भाग लेने की आशा है। इस प्रकार महा कुंभ आयोजन में लगभग 450 मिलियन तीर्थयात्री, संत, संन्यासी, पर्यटक और श्रद्धालु आएंगे।

इस दैवी 'संगम' के केन्द्र में गंगा, यमुना व आध्यात्मिक सरस्वती नदियों का पवित्र संगम या त्रिवेणी है। करोड़ों भक्त यहां आध्यात्मिक पवित्रता तथा ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पवित्र स्नान करते हैं। महा कुंभ आस्था, एकता और मानवता तथा देवत्व के बीच सनातन संबंध का अनादि काल से प्रतीक बना हुआ है। इसका आधार पौराणिक व आध्यात्मिक इतिहास है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि ग्रहों के विशिष्ट संयोजन के अवसर पर यहां पवित्र स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है तथा मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। योग गुरु तथ वेदांत के प्रचारक स्वामी शिवानंद ने उचित ही कहा है कि 'कुंभ मेले में पवित्र स्नान केवल एक परंपरा न होकर ईश्वरीय शक्ति के समक्ष समर्पण है।' पौराणिक रूप से इससे 'समुद्र मंथन' की कथा जुड़ी है जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

प्राचीन ग्रंथों के अनुसार देवताओं और दानवों ने अमृत की तलाश में समुद्र का मंथन किया था। जब देवता अमृत कलश लेकर भाग रहे थे तब उसकी कुछ बूंदें चार स्थानों-हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में गिरीं और ये स्थान भी पवित्र हो गए। इस प्रकार कुंभ मेले की परंपरा शुरू हुई। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में तुलनात्मक धर्म एवं भारतीय अध्ययनों की प्रोफेसर डायना इक के अनुसार, 'कुंभ मेला पौराणिकता और भूगोल को एकसाथ जोड़ने की भारतीय भावना का प्रतिनिधित्व करता है और इस प्रकार उसे बहुत पवित्र बना देता है।' कुंभ के संदर्भ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद के वैदिक पाठों में मिलते हैं। इसका संबंध ज्योतिषीय प्रतीक कुंभ से भी है। पहली शताब्दी ईस्वी में यूनानी विचारों में इसकी व्याख्या की गई है। 'मेला' का अर्थ लोगों के 'समूह' या उनके 'एकत्र होने' से है। प्राचीन हिंदू ग्रंथों में इसे सामुदायिक रूप से महत्वपूर्ण मेलों के रूप में परिभाषित किया गया है।

> **कुंभ मेला का अर्थ 'जल या अमृत को केन्द्र में रख कर मनुष्यों के मिलन' से है। ऐतिहासिक रूप से कुंभ मेला का पहला रिकार्ड उल्लेख चीनी यात्री ह्वेनसांग के सातवीं शताब्दी में लिखे यात्रा विवरणों से मिलता है। ह्वेनसांग ने सम्राट हर्ष के शासनकाल की अनेक घटनाओं का दस्तावेजीकरण किया था।**

इस प्रकार कुंभ मेला का अर्थ 'जल या अमृत को केन्द्र में रख कर मनुष्यों के मिलन' से है। ऐतिहासिक रूप से कुंभ मेला का पहला रिकार्ड उल्लेख चीनी यात्री ह्वेनसांग के सातवीं शताब्दी में लिखे यात्रा विवरणों से मिलता है। ह्वेनसांग ने सम्राट हर्ष के शासनकाल की अनेक घटनाओं का दस्तावेजीकरण किया था। सम्राट हर्षवर्धन का शासन 606 से 647 ईस्वी तक अधिकांश उत्तर भारत में था और उनके शासनकाल को तुलनात्मक रूप से शांति और समृद्धि वाले काल के रूप में किया जाता है। ह्वेनसांग ने प्रयाग में कुंभ मेला का वर्णन किया है जिसमें सम्राट हर्षवर्धन ने भाग लिया था।

पिछली शताब्दियों में यह त्योहार संन्यासियों के समागम से बढ़ कर एक विशाल आयोजन में बदल गया है जो करोड़ों लोगों को आकर्षित करता है। कुंभ मेला का ऐतिहासिक परिवर्तन इसकी दृढ़ता और परिवर्तनशीलता प्रकट करता है तथा आध्यात्मिक भावनाओं को सामाजिक परिवर्तनों से जोड़ता है। कुंभ मेले में बड़ी संख्या में संत, संन्यासी और आध्यात्मिक गुरु एकत्र होते हैं जो जनता को दिशानिर्देश देते हैं। सनातन धर्म को मजबूत बनाए रखने में विभिन्न अखाड़ों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है। भगवा वस्त्र पहले या भभूत लगाए संत भौतिक इच्छाओं के त्याग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार उनका पवित्र संगम में स्नान गहरे आध्यात्मिक अर्थ वाला है। यह अपने पाप और अहंकार धो डालने तथा स्वच्छ आध्यात्मिक शुरुआत का प्रतीक है। इतिहासकार विलियम डेलीरिम्पल ने लिखा था, 'कुभ मेले में एकत्र संत भारत की अनादि और अनन्त आध्यात्मिक विरासत के संरक्षक हैं।'

कुंभ मेला बड़ी खूबसूरती से धर्म और विज्ञान का मेल कराता है। इसका समय सटीक खगोलीय गणना से निर्धारित होता है जो हिंदू नक्षत्र-विज्ञान का महत्व प्रकट करता है। जब बृहस्पति कुभ में प्रवेश करता है और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है तब ग्रहीय व्यवस्था एक शुभ समय का संकेत देती है जिसका आध्यात्मिक संबंध है। यह पवित्र त्योहार ग्रहीय परिघटना को धरती के त्योहार से जोड़ता है। इससे ब्रह्मांड तथा मानवीय आध्यात्मिकता में गहन संबंध स्पष्ट होता है। आर्यभट्ट ने ग्रह-नक्षत्रों के बारे में अपने प्रख्यात अध्ययन में इस ग्रहीय परिघटना का उल्लेख किया है जिसमें ग्रहों की गति तथा ग्रहणों का विवरण शामिल है। इस प्रकार अनेक ग्रहों-नक्षत्रों की गति कुंभ के समय को प्रभावित करती है।

कुंभ मेला विभिन्न संस्कृतियों, दर्शनों तथा मानव समूहों के मिलन का अवसर भी है। यहां आने वालों में दुनिया त्याग चुके संन्यासियों के साथ आम लोग और विदेशों के अनेक लोग शामिल हैं। यह विविधता आध्यात्कि खोज की सर्व-व्यापकता का प्रतिनिधित्व करती है। समाजविज्ञानी सुधीर कक्कड़ ने एक बार लिखा था, 'कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन न हो कर मनुष्यों के परस्पर संबंधों और जुड़ाव का महान आयोजन है।' मेले में विभिन्न विचारों, कर्मकांडों और दर्शनों का आदान-प्रदान एक उल्लेखनीय वैश्विक एकता का प्रतीक बन जाता है।

करोड़ों लोगों के समागम वाले कुंभ मेले के लिए व्यापक तैयारियों की जरूरत होती है। इसमें अनेक अद्यतन तकनीकों का प्रयोग किया जाता है जिनमें एआई-संचालित भीड़ प्रबंधन व्यवस्थायें, सुरक्षा के लिए ड्रोनों से निगरानी तथा चिकित्सकीय आपातस्थितियों से निबटने के लिए मोबाइल स्वास्थ्य क्लीनिकें भी शामिल हैं। मोबाइल एपों व लाइव-स्ट्रीमिंग सेवाओं से सहज संचार और दुनिया भर से श्रद्धालुओं की पहुंच सुनिश्चित हुई है। 2025 का कुंभ मेला 800 हेक्टर क्षेत्र में फैला है जहां रोज पांच लाख वाहनों के लिए 101 स्मार्ट पार्किंग व्यवस्थायें तथा श्रद्धालुओं के लिए 1.8 लाख टेंटों की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार चुनौतियों के बावजूद महा कुंभ मेले में परंपराओं और आधुनिकता का सहज संगम हो रहा है।

हमारे कर्म देते हैं जीवन को आकार

> **जीवन और मृत्यु नवीनीकरण के एक शाश्वत चक्र में गुंथे हुए हैं, जो आत्मा को विकास के अवसर प्रदान करते हैं।**

अजीत कुमार बिश्नोई
(लेखक, आध्यात्मिक उपदेशक हैं)

हम सभी को कर्मफलों के बारे में पता होना चाहिए। ये हमारे द्वारा अतीत में मन, वचन और शरीर से किए गए अच्छे और बुरे कर्मों के परिणाम हैं। मैंने मन का उल्लेख शरीर से अलग करके किया है क्योंकि मन द्वारा किए गए कर्म सूक्ष्म होते हैं। और वे काफी घातक हो सकते हैं। मानसिक रोग क्या है? आपने सही अनुमान लगाया है; यह हमारे मन के कारण होता है।

इसी तरह, शब्द भी कम खतरनाक नहीं हैं। हाँ, शब्द बहुत घातक हो सकते हैं, जैसा कि हम सभी ने अनुभव किया है, जब हम मूर्खतापूर्ण बात करने का विकल्प चुनते हैं। और ये बुरे कर्मफल किसी भी उम्र में प्रकट हो सकते हैं लेकिन बुढ़ापे में ये सबसे अधिक नुकसान पहुँचाते हैं जब हम कमजोर होते हैं और हमारे पास ज्यादा विकल्प नहीं होते।

यह तब होता है जब कोई व्यक्ति अपनी बदकिस्मती पर विलाप करता है और उसके लिए सहानुभूति रखने वाले बहुत कम होते हैं। क्या हम उम्र बढ़ने के साथ खत्म नहीं हो जाते? यह लेख बताता है कि हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। आखिरकार हम इतने असहाय नहीं हैं। पहला कदम इसी क्षण से सभी बुरे काम करना बंद करना है। और हम जानते हैं कि ये क्या हैं। सभी अच्छे काम करके हमारे अंदर अच्छाई बढ़नी चाहिए।

हमें मधुरता से बोलना चाहिए; हमें अच्छे कार्यक्रमों को देखना चाहिए; हमें अच्छे खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए; इत्यादि। इससे हम अपने वर्तमान कार्यों के बुरे प्रभावों से बचेंगे। नियंत्रक मानसिकता पर अंकुश लगाया जाना चाहिए; हमें यथार्थवादी बनना चाहिए क्योंकि नियंत्रक केवल एक ही है और वह है ईश्वर। यदि ऐसा नहीं होता तो हम

जो चाहें प्राप्त कर लेते, जो शायद ही कभी होता है। अहंकार पर अंकुश लगाया जाना चाहिए क्योंकि केवल एक ही श्रेष्ठ सत्ता है, जो ईश्वर है। हम जीवन भर अपनी श्रेष्ठता साबित करने की कोशिश करते हैं और क्या होता है? हम दूसरों के बीच बहुत अलोकप्रिय हो जाते हैं, खासकर अपने परिवार के सदस्यों के बीच, जिनकी हमें बुढ़ापे में बहुत जरूरत होती है। आध्यात्मिक अभ्यास सही ईमानदारी से शुरू किए जाने चाहिए। यदि हम यह महसूस कर लें कि हम आत्मा हैं, ईश्वर के अंश हैं, तो वे बहुत सार्थक होंगे। क्या अंशों को समग्र पर निर्भर नहीं होना चाहिए? क्या हमें ईश्वर के प्रति सम्मान नहीं होना चाहिए, जैसा कि एक बेटे को अपने पिता के प्रति होना चाहिए? जब कोई हमारा कुछ उपकार करता है तो क्या हम उसका धन्यवाद नहीं करते? ईश्वर हमेशा हम पर बहुत उपकार करता है। सबसे पहले, उन्होंने सूर्य का प्रकाश, जल, ऑक्सीजन युक्त वायु आदि सभी आवश्यक वस्तुएँ नि:शुल्क प्रदान की हैं।

अंत में भगवान को सहायता करनी ही पड़ती है, क्योंकि भाग्य को कोई और नहीं बदल सकता। वे भी नहीं करते, लेकिन बुरे कर्मफलों से निपटने में सहायता करते हैं; हमारा अंत बुरा नहीं होगा। (9.31) यह बहुत बड़ी कृपा है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है उनकी दया, जो हमें हमारे अच्छे कर्मफलों से बचाती है, जब हम स्वयं को बुरी तरह चोट पहुँचाने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं। क्योंकि अच्छे समय को सहन करना कठिन है। और भगवान और केवल भगवान ही हमारे स्वभाव को सुधारने में सहायता कर सकते हैं, जो हमारे भाग्य का भी हिस्सा है।

क्या हमारा स्वभाव हमें बार-बार निराश नहीं करता? हम देखते हैं कि लोग क्रोध, वासना, ईर्ष्या आदि से खुद को नष्ट कर रहे हैं। भगवान हमें मूर्खतापूर्ण कार्यों से बचाते हैं, यदि हम उनकी शरण में रहें। मैं अपने बुढ़ापे में जब मैं पहले से ही कमजोर हूँ, तब दुर्भाग्य की संभावना से बहुत डरता हूँ। भगवान को मेरी रक्षा करनी ही होगी।

मैं कोई जोखिम नहीं उठा रहा हूँ; मैंने भगवान की शरण ली है। केवल भगवान ही मदद कर सकते हैं, क्योंकि वे स्वामी और नियंत्रक हैं। भगवान हस्तक्षेप कर सकते हैं और भगवान अपने भक्तों के लिए ऐसा करते भी हैं। (भगवद गीता 18.58) क्या इससे हमें शांति नहीं मिलेगी? इससे मैं धीरे-धीरे शांत हो गया हूँ क्योंकि मेरी आध्यात्मिक साधनाओं से भगवान के साथ मेरा संबंध मजबूत होता जा रहा है। कृपया जोखिम न लें।

आप की बात

कुंभ मेले में आग

महोदय, प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र में आग लगने की घटना ने एक बार फिर से कुंभ की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा दिए हैं। यह घटना शास्त्री पुल और रेलवे पुल के बीच इलाके में हुई, जो मेला क्षेत्र में आता है। बताया जा रहा है कि खाना बनाने के दौरान सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, जिससे आग तेजी से फैल गई। देखते ही देखते 20-25 टेंट जलकर खाक हो गए। यह घटना कुंभ की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाती है। यदि यही घटना पर्व स्नान के वक्त होती तो दमकलों का घटना स्थल पहुंचना ही मुश्किल होता। कुंभ मेले में लाखों-करोड़ों लोग आते हैं और ऐसी घटना से बड़ा हादसा हो सकता था। कुंभ की सुरक्षा व्यवस्था के लिए सरकार और प्रशासन ने भरपूर व्यवस्था की थी, लेकिन फिर भी यह घटना हुई। यह घटना यह दर्शाती है कि सुरक्षा व्यवस्था में अभी भी कुछ कमियां हैं। कुंभ की सुरक्षा व्यवस्था के लिए सरकार और प्रशासन को और अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मेले में आने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके अलावा, कुंभ की सुरक्षा व्यवस्था के लिए सरकार और प्रशासन को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि मेले में आने वाले लोगों की सुरक्षा के बारे में जागरूक किया जाए। उन्हें यह बताया जाए कि वे अपनी सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं।

– **सुभाष बुड़ावनवाला,** रतलाम

किसान आंदोलन का सच

कैसी विडम्बना है कि तथाकथित किसान आन्दोलन जिसके कारण एक मुख्य राजमार्ग बाधित होने से जनसामान्य, व्यापारियों, कर्मचारियों को इतनी भीषण समस्या है और दूसरी ओर उन अराजक तत्वों का आतंक जो स्वयं को किसानों का प्रतिनिधि कह कर ऐसी मांगों को अपना अधिकार मान कर मनवाने पर अड़े हैं जो असम्भव हैं, के समाधान के लिए विपक्षी राजनैतिक दल और सुप्रीम कोर्ट ने इन अराजक व आतंकी तत्वों को आश्रय दिया है और मार्ग बाधित होने के समाज को होने वाली क्षति के प्रति उदासीनता का भाव। सुप्रीम कोर्ट चिंतित है अनशनकारी किसान नेता के स्वास्थ्य के प्रति किन्तु उसकी ज़ानेंद्रियां मार्गबाधा के कारण असंख्य जनसामान्य की पीड़ा के प्रति निष्क्रिय। क्या डल्लेवाल का जीवन शेष भारत के नागरिकों से अधिक महत्वपूर्ण है ? क्या सरकारों अथवा सुप्रीम कोर्ट को इस प्रकार के अनुचित दबाव में आकर नीतिगत निर्णय करने चाहिएं ? होना ये चाहिए कि इन्हें स्पष्ट शब्दों में राजमार्ग खाली करने का आदेश दिया जाना चाहिए, वार्ता यदि कोई हो तो उसके बाद। यदि पंजाब सरकार इन्हें नहीं हटाती तो पंजाब में केन्द्रीय शासन लगा कर राजमार्ग खाली कराने चाहिएं, शेष सभी कुछ बाद में।

– **जय प्रकाश गुप्ता,** अंबाला छावनी

महत्वपूर्ण कदम

आठवें वेतन आयोग की नियुक्ति घोषणा के साथ ही, सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह और सेवाओं की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। यह आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन की सिफारिशें करेगा, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर की अधिकतम रेंज के तहत न्यूनतम सैलरी 26, 000 रुपये हो जाएगी. कर्मचारी यूनियन और बाकी संगठन आठवें वेतन आयोग में इसे 2.86 से 3 के बीच रखने की मांग कर रहे हैं. यह मांग मानी गई तो सैलरी में 180त्न बढ़ोतरी होगी. रिपोर्ट्स के अनुसार, आठवें वेतन आयोग में न्यूनतम आधार वेतन को बढ़ाकर 34,650 रुपये किया जा सकता है, जो कि सातवें वेतन आयोग में 17,990 रुपये है. वहीं, पेंशन को 9,000 रुपये से बढ़ाकर 17,280 रुपये किया जा सकता है. इससे सरकार पर भारी आर्थिक बोझ बढ़ेगा। सरकारी सेवाओं के प्रति युवाओं के आकर्षण का कारण पर्याप्त तनख्वाह और सुविधाओं के साथ-साथ आराम से काम करने का माहौल है। इसके अलावा, सरकारी नौकरियों में ऊपरी आमदनी भी भरपूर होती है। लेकिन, प्राइवेट सेक्टर की तनख्वाह, काम और कार्य समय की तुलना में सरकारी नौकरियों में वेतन और सुविधाएं अधिक होती हैं। आठवें वेतन आयोग के लागू होने से कई महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलेंगे।

– **विभूक्ति बुपक्या,** खाचरोद

संयम बरतें राहुल

लगातार कांग्रेस की फजीहत के बाद भी पार्टी नेता उलजलूल बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे है।अपने बयानों से किरकिरी झेलते राहुल गांधी ने एक बार फिर संघ, भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी को देश के लिए कब्जाधारी संस्था बताया है। भाजपा और संघ ही नहीं बल्कि इंडियन स्टेट से भी दो-दो हाथ करने पर मजबूर दिखते राहुल इस बयान को लेकर सवालों के घेरे में है। राहुल यह स्पष्ट नहीं कर पाए कि उनके इंडियन स्टेट का आखिर दायरा क्या है? सरकार से विरोध उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। मगर इसे भारतीय राजव्यवस्था से संघर्ष में उनके अस्पष्ट आशय से जोड़ा जाए तो उसका गंभीर अर्थ एक अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसा लगता है संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को समझने में राहुल संदर्भित विषय से भटक जाते है और वे अर्थ का भी अनर्थ कर देते है।कितना अच्छा हो कि राहुल अपनी सोच में गंभीरता लाए और भाषा संयम से तथ्यों का विश्लेषण करें इससे उनकी विपक्ष के नेता की भूमिका के साथ भी न्याय होगा। राहुल के आधारहीन आरोप खुद की संकीर्ण मानसिकता और विषयक अधूरे ज्ञान का उदाहरण है।

– **अमृतलाल मारू,** इंदौर

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से **responsemail.hindipioneer@gmail.com** पर भी भेज सकते हैं।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 288

अनिश्चित दुनिया और वृद्धि की क्षमता

इस वर्ष घटी आर्थिक घटनाओं के परिणामों पर दुनिया भर में काफी चिंता का माहौल है। काफी कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि डॉनल्ड ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका में क्या नीतिगत बदलाव आते हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक ने गत सप्ताह अपने आर्थिक अनुमान जारी कर दिए। उन्होंने इसमें अनिश्चितता का संकेत दिया, जो हमें अमेरिकी नीतिगत बदलावों से परे भी दिखती रहेगी। दोनों बहुपक्षीय संस्थानों का मानना है कि इस वर्ष वैश्विक वृद्धि स्थिर रहेगी मगर उनके अनुमान अलग-अलग हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान है कि 2025 में विश्व अर्थव्यवस्था 3.3 फीसदी दर से विकसित होगी जबकि विश्व बैंक का अनुमान 2.7 फीसदी वृद्धि का है। किंतु आईएमएफ ने अपने अनुमान में स्पष्ट कहा है कि वृद्धि दर इस सदी के पहले दो दशकों की तुलना में कम रहेगी।

विश्व बैंक के मध्यम अवधि के अनुमान में खास तौर पर उभरते बाजारों और विकासशील देशों के लिए उसका आकलन ऐसी तस्वीर पेश करता है, जो नीति निर्माताओं को चिंतित कर सकती है। रिपोर्ट कहती है कि वैश्विक वृद्धि में 60 फीसदी हिस्सेदारी रखने वाले ये देश जिस प्रति व्यक्ति आय के साथ इक्कीसवीं सदी के दूसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं उसके कारण उन्हें विकसित देशों के स्तर तक पहुंचने में पहले से भी अधिक समय लगेगा। मध्यावधि में धीमी वैश्विक वृद्धि का नतीजा भारत को भी भुगतना होगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के पहले अग्रिम अनुमानों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 6.4 फीसदी दर से बढ़ेगी। यह गत वित्त वर्ष में हासिल 8.2 फीसदी की गति से बहुत धीमी है। अर्थशास्त्र के विद्वानों का तर्क है कि भारतीय अर्थव्यवस्था महामारी के बाद की तेज वापसी के पश्चात अपनी सामान्य वृद्धि दर की ओर लौट रही है। ऐसे में मध्यम अवधि की वृद्धि संभावनाओं को तेज करने पर ध्यान देना होगा।

मध्यम अवधि में वृद्धि के पूर्वानुमान तो चुनौती भरे हैं ही, निकट भविष्य में भी अनेक जोखिम हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी संकेत किया है: 'टैरिफ की नई लहर के रूप में संरक्षणवादी नीतियों के गहराने से व्यापार में तनाव बढ़ सकता है, निवेश घट सकता है, बाजार क्षमता में कमी आ सकती है, व्यापार का प्रवाह बिगड़ सकता है और आपूर्ति श्रृंखला में उथलपुथल मच सकती है।' इससे मध्यम और निकट दोनों अवधियों में वृद्धि को झटका लग सकता है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन से संरक्षणवादी नीतियों के साथ जिस तरह की मौद्रिक नीति की अपेक्षा है, उससे निकट भविष्य में अमेरिका की वृद्धि दर बढ़ सकती है। किंतु इसकी वजह से राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों में भारी बदलाव हुए तो दुनिया भर में धन के प्रभाव और डॉलर की ताकत पर असर पड़ सकता है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने अपने अनुमानों में बदलाव करते हुए दर में कटौती की रफ्तार मंद रखने की बात कही, जिसके बाद दुनिया भर में बॉन्ड यील्ड चढ़ गईं। हालांकि ज्यादा लोग फेड का रुख पलटने की बात नहीं कह रहे हैं मगर अमेरिका में शिथिल राजकोषीय-नीति के साथ शुल्कों में इजाफा हुआ तो फेड को अपने रुख पर फिर विचार करने के लिए विवश होना पड़ेगा। दरें बढ़ने की संभावना बनी तो वैश्विक वित्तीय बाजारों में तगड़ी उठापटक हो सकती है।

भारतीय नीति निर्माताओं के सामने फिलहाल जो चुनौती है वह है वित्तीय स्थिरता बनाए रखना और दुनिया भर में कमजोर रुझानों के बीच देश में वृद्धि की संभावनाएं तेज करने की कोशिश। मुद्रा बाजार की गतिविधियां पिछले कुछ महीनों से चर्चा में हैं और उन पर काफी बहस देखने को मिली है। उदाहरण के लिए रिजर्व बैंक ने रुपये को थामने के लिए नवंबर में 20 अरब डॉलर खर्च कर दिए। आज के हालात में अमेरिकी नीतिगत कदमों से रुपये पर दबाव जारी रह सकता है। रिजर्व बैंक को मुद्रा का अवमूल्यन होते रहने देना चाहिए और प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए ही हस्तक्षेप करना चाहिए। रुपये की कीमत सही होगी तो ही निकट और मध्यम अवधि में बाहरी प्रतिकूल हालात से निपटने में भारत को मदद मिल सकेगी।

हर वाद पर भारी लोकलुभावनवाद

नई दुनिया में केवल एक ही विचार है जो तमाम वोट बैंकों में पहुंच बना सका है और वह है लोकलुभावनवाद। इसकी खूबसूरती, आकर्षण और सफलता इस बात में निहित है कि इसे इस्तेमाल करना आसान है।

राष्ट्र की बात

शेखर गुप्ता

हम 2025 में प्रवेश कर चुके हैं और अब यह तय करना उचित होगा कि कौन सा 'वाद' हार चुका है और कौन सा जीत रहा है। अगर हम पश्चिम को देखें तो वामपंथ या वाद अब लगभग समाप्त हो चुका है। यह न केवल राजनीतिक रूप से समाप्त हो चुका है बल्कि सामाजिक स्तर पर भी इसका अंत हो चुका है। ब्रिटेन इसका अपवाद है, हालांकि वहां भी कीर स्टार्मर को इलॉन मस्क समर्थित धुर दक्षिण से हमलों का सामना करना पड़ रहा है और लेबर पार्टी भी खतरे में नजर आ रही है।

इसके साथ ही दक्षिणपंथ भी अच्छी स्थिति में नहीं दिख रहा है। कम से कम राजनीतिक दक्षिणपंथ पर यह बात लागू है। अमेरिका में रिपब्लिकन ट्रंप के उभार के आगे झुक गए हैं। हाल के दिनों में ट्रंप ने जिन लोगों को निशाने पर लिया है वे रिपब्लिकन हैं। निक्की हेली को उन्होंने 'बर्डब्रेन' (चिड़िया जैसा दिमाग रखने वाली), जॉन बोल्टन को 'डंब ऐज ए रॉक' (पत्थर की तरह खामोश), डिक चेनी को 'डिस्लॉयल वारमॉन्गर' (गैर वफादार युद्धोन्मादी) और उनकी बेटी लिज को 'साइको' (मनोरोगी) कहा। इसके अलावा उन्होंने चार्ल्स कोच तथा कुछ अन्य को समृद्धि विरोधी अमेरिकी कहा जिनमें मिट रोमनी, जिम मैटिस, मार्क एस्पर आदि शामिल हैं। ट्रंप का कहना है कि ये सभी टीडीएस यानी ट्रंप डिरेंजमेंट सिंड्रोम से पीड़ित हैं।

वे पुराने वामपंथियों को लेकर ऐसी भाषा इस्तेमाल नहीं करते। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी नजर में पुराने दक्षिणपंथी डेमोक्रेट्स से भी अधिक अनैतिक हैं। ट्रंप के मागा (मेक अमेरिका ग्रेट अगेन) समर्थक रिपब्लिकंस भी पारंपरिक जीओपी (ग्रांड ओल्ड पार्टी यानी रिपब्लिकन पार्टी) से उतनी ही दूर हैं जितने कि वामपंथी डेमोक्रेट्स। रुचिर शर्मा ने फाइनैंशियल टाइम्स में अपने ताजा आलेख में इस बात को रेखांकित किया है कि गत वर्ष विकसित देशों में 85 फीसदी ऐसे नेता चुनाव हार गए जो सरकार में रहते हुए चुनाव लड़ रहे थे। मैं इसमें यह बात जोड़ना चाहूंगा कि इस बीच जो नया विचार उभरा है वह कोई पुराना 'वाद' नहीं रहा है। यह बात फ्रांस और इटली के लिए भी सही है। जर्मनी में भी ऐसा ही होने की संभावना है। अब जबकि वाम राजनीति खारिज हो रही है, दक्षिणपंथ नए सिरे से परिभाषित हुआ है और मध्य-दक्षिण का विचार गहरे संकट में है।

हमें अब तक जो भी वाद पढ़ाए गए मसलन वाम, दक्षिण और मध्य मार्ग आदि, वे सभी या तो मर रहे हैं या फिर गहरे संकट में हैं? उनकी जगह कौन ले रहा है? यह बात सोना महापात्र के कुछ साल पुराने गीत की याद दिलाती है: (इक नए किस्म का इज्म)। जाहिर है गीतकार राम संपत हमारे दिलों को प्रेरित करते हैं कि हम सभी पुराने और विभाजनकारी वादों को खारिज करके एक नया वाद खोजें जो हमें जोड़ने वाला हो।

राजनीति के लिए यह बहुत रूमानी है। इसके साथ ही लोकतांत्रिक व्यवस्था में विचारों का अभाव भी नहीं रह सकता। सच तो यह है कि अगर महापात्र ने एक नए किस्म के 'इज्म' के लिए गीत गाया था तो अब वह इज्म यानी वाद सामने भी आ चुका है। वह है लोक लुभावनवाद। पूरी दुनिया में इसने वाम, दक्षिण और मध्य को परेशान कर रखा है। यकीनन यह अलग देशों, मतदाताओं और समाजों के लिए अलग-अलग है। विकसित देशों में इसमें प्रवासियों को बड़े पैमाने पर वापस भेजना, अलग संस्कृतियों और आस्थाओं से भय (ज्यादातर इस्लाम), अति राष्ट्रवाद, व्यापारिक संरक्षणवाद और इतिहास या मिथकों में राहत तलाशना शामिल हैं। ट्रंप, जियोर्जिया मेलोनी, विक्टर ओर्बन और मरीन ले पेन कुछ सर्वाधिक सफल लोकलुभावनवादियों में शामिल हैं। उन्हें दक्षिणपंथी कहना गलत होगा। नाइजल फराज की यूके रिफॉर्म पार्टी भी इसी जमात का हिस्सा बनने के प्रयास में है। इससे सबसे अधिक डर किसे है? लेबर पार्टी को डर नहीं है क्योंकि उसके पास सहज बहुमत है। सबसे बड़ा खतरा ब्रिटिश कंजरवेटिव पार्टी को है। क्या यूके रिफॉर्म उनके साथ वही कर सकती है जो ट्रंप ने अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के साथ किया? लोकलुभावनवाद की खूबसूरती, आकर्षण और सफलता इस्तेमाल की सहजता में निहित है क्योंकि यह आपके दिलोदिमाग से या आपकी चेतना से कुछ खास नहीं मांगती। इस पर नैतिकता का दबाव नहीं होता, इतिहास का बोझ नहीं होता और यह तथ्यों से भ्रमित नहीं होता।

एक स्तर पर यह पूरी तरह लेनदेन पर आधारित हो सकता है और भारत में ऐसा घटित होता दिख रहा है। 'मैं आपको, आपकी बहन या मां को बहुत अधिक पैसे दूंगा और बदले में आप मुझे वोट दो।' या फिर 'निःशुल्क बस यात्रा', 'कुछ यूनिट बिजली मुफ्त', 'मुफ्त पानी' आदि। एक साल से कुछ पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे रेवड़ी कहकर इसका मखौल उड़ा रहे थे जो नेताओं को उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी यानी शासन से दूर करती है। उनका कहना सही था लेकिन उनकी बातें बहुत जल्दी गलत साबित हो गईं। अब खुद भारतीय जनता पार्टी दूसरों से कहीं अधिक 'रेवड़ियां' बांटती नजर आ रही है। उसे महाराष्ट्र में कामयाबी भी मिली। दिल्ली में वह महिलाओं को आम आदमी पार्टी से भी अधिक मदद की पेशकश कर रही है। यह इतना अधिक बढ़ गया है कि भाजपा जो देश की सबसे सफल और सुपरिभाषित विचारधारा वाली पार्टी है, वह अब हिंदुत्व और हिंदुत्व आधारित राष्ट्रवाद से अधिक भरोसा मुफ्त उपहारों पर कर रही है।

हम कह चुके हैं कि लोकलुभावनवाद विचारधारा से मुक्त है। देखना होगा कि कैसे वाम ताकतों या कांग्रेस ने लेनदेन वाली राजनीति शुरू की। आम आदमी पार्टी जैसी विचारधारा रहित पार्टी ने उन्हें राह दिखाई। अब भाजपा भी वही कर रही है। इसका बोझ राहुल गांधी पर नहीं है लेकिन उन्होंने जिस मुहब्बत की दुकान की बात की थी वह रेवड़ियों के एक बड़े बाजार में बदल गई है। व्यापक लोकलुभावनवाद में भावनात्मक कारक भी हैं मसलनः धर्म, राष्ट्रवाद, संस्कृति, अतीत मोह, यह वकीन होगा कि अतीत में कभी हम आज की तुलना में महान थे। यही वजह है कि लोग मेक अमेरिका ग्रेट अगेन (अमेरिका को फिर से महान बनाएं) के लिए मतदान करेंगे। क्या अमेरिका शीत युद्ध में जीत के समय से ही महान नहीं है? क्या इसी आधार पर भारत में लोग 'दोबारा सोने की चिड़िया' बनाने के विचार को कबूल नहीं कर लेंगे? यही वही चीज है। लोकलुभावनवाद आपसे उन चीजों का वादा करता है जो आपने पहले कभी नहीं देखीं लेकिन वो आपको बेहतर महसूस करवाती हैं। इसके बाद इन्हें अधिक परिभाषित नजरियों से देखा जाता है मसलनः प्रवासी मुद्दा, दूसरे मुल्क की जमीन पर दावा, लैंगिकता और नस्ल आदि। शाब्दिक व्यंजना और नस्लीय शुद्धता आदि की धारणा को तो छोड़ ही दें।

विकसित देशों में प्रवासियों की समस्या बहुत बड़ी है। भारत में सीएए का मुद्दा इसी पर जोर दे रहा है। केवल 40-50 हजार की आबादी वाले रोहिंग्या इतना बड़ा मुद्दा बने हैं। दूसरे देश पर कब्जे का मुद्दा कैसे काम करता है इसे इस तरह देखें कि ट्रंप मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलना चाहते हैं, पनामा नहर को वापस लेना चाहते हैं और ग्रीनलैंड पर कब्जा चाहते हैं। भारत के लिए यह मुद्दा है अक्साई चिन और पाक अधिकृत कश्मीर। और इन दिनों भले ही उसकी अधिक बात नहीं हो रही हो लेकिन अखंड भारत के गौरव को बहाल करने की भावना भी बरकरार है। लिंग और नस्ल का मसला भारत में उस तरह नहीं है जैसा कि पश्चिमी देशों में। भारत की सुरक्षा उसकी बुनावट में निहित विविधता और वोट बैंक की बहुलता है। यहां एक नस्ल या पहचान पर जोर देने से दूसरी नस्लें या पहचानें अलग-थलग पड़ सकती हैं।

बहरहाल भारत भी लोकलुभावनवाद की दिशा में बढ़ रहा है। साल 2014 में मोदी सत्ता में आए। उस समय उन्होंने न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन का वादा किया था। लेकिन हमने देखा कि सरकार का आकार बढ़ता गया। एवर इंडिया को छोड़ दिया जाए तो निजीकरण का वादा पूरी तरह भूला दिया गया है। उसकी जगह अब गर्व से कहा जाता है कि सरकारी कंपनियों का प्रदर्शन पहले कभी उतना बेहतर नहीं रहा जितना इस सरकार के कार्यकाल में है। जिस समय मैं यह आलेख लिख रहा था, इस बात का जश्न मनाया जा रहा था कि सरकार विशाखापत्तनम स्थित सरकारी इस्पात संयंत्र में 11,440 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश कर रही है। यह संयंत्र वर्षों से विनिवेश किए जाने वाले संयंत्रों की सूची में शामिल था। मतदाताओं को लुभाने के लिए खराब चीजों पर धनराशि खर्च करना ही तो लोकलुभावनवाद है।

डेढ़ दशक में ठहर सी गई दिल्ली

नीति नियम

मिहिर शर्मा

राष्ट्रीय विकास का पैमाना कहलाने वाले शहर बदलते भी रहते हैं। उनका भौतिक, सामाजिक और बौद्धिक बुनियादी ढांचा हर 15 साल में नया रूप ले लेता है। यदि सोल के 1970 और 1985 तथा शांघाई के 2010 और 2025 के दौर की तुलना करें तो दोनों दौर में ये शहर एकदम बदले हुए लगेंगे। ये एकदम अलग शहर प्रतीत होते हैं। यही बात 1995 और 2010 के बीच के दिल्ली पर भी लागू होती है। साल 2010 में जिस दिल्ली ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी, उसकी शक्ल उस दिल्ली से बिल्कुल अलग थी, जहां मैं डेढ़ दशक पहले अपने बचपन में आया था।

राष्ट्रमंडल खेलों के बाद से दिल्ली ठहर सी गई है। इस राज्य में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इसलिए इस बात पर चर्चा लाजिमी है कि पिछले 15 साल किस तरह बरबाद कर दिए गए हैं। प्रगति मैदान की जगह नए परिसर का निर्माण और सेंट्रल विस्टा के नाम पर हुए कुछ बदलावों को छोड़ दें तो बुनियादी ढांचे में ऐसा कोई विकास नहीं हुआ है, जिसका जिक्र किया जा सके। सौंदर्यीकरण के ये काम भी केंद्र सरकार के शीर्ष से आई खास मांगों को पूरा करने के लिए हुए हैं और इनसे आम दिल्ली वालों के लिए राजधानी के मायने और अनुभव शायद ही बदले हैं।

बीते डेढ़ दशक का यह दौर दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी के उभार का दौर रहा है। राष्ट्रमंडल खेलों के समापन के बाद 2011 से 2014 तक दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन और आंदोलनों का दौर चलता रहा। इन्हीं में से एक आंदोलन से एक पार्टी का उदय हुआ, जिसे आम आदमी पार्टी (आप) का नाम दिया गया और जो बाद के वर्षों में दिल्ली राज्य की राजनीति पर छा गई।

आप और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल को कुछ सवालों का जवाब अवश्य देना होगाः पिछले दस साल से सत्ता में रहते हुए उन्होंने आम आदमी की जिंदगी में किस तरह का बदलाव किया? इस सवाल का जवाब सत्तारूढ़ पार्टी और उसके मुखिया को बिना किसी लाग-लपेट और आरोप-प्रत्यारोप के देना चाहिए। हां, केंद्र सरकार ने बेशक उनका कामकाज कुछ मुश्किल बनाया मगर ऐसा तो केंद्र ने लगभग हर राज्य की सरकार के साथ किया। इसके बाद भी उनमें से कुछ राज्यों की सरकारें अपने नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करती रहीं। दिल्ली 2010 के बाद से दिल्ली आर्थिक एवं उद्यमशील ऊर्जा का केंद्र रही है और ऐसी ऊर्जा इतिहास में कभी देखी ही नहीं गई। इसी के बल पर दिल्ली ने कई मामलों में मुंबई और बेंगलूरु को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन शहर के ताने-बाने या प्रशासन में यह ऊर्जा किस तरह नजर आती है? यदि इस सवाल का जवाब 'बिल्कुल नहीं' है तो आम आदमी पार्टी के होने - न होने से फर्क ही क्या पड़ता है?

सच कहूं तो आम आदमी पार्टी जब पहली बार सत्ता में आई थी तो इसके और पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के पास स्थानीय प्रशासन की अलहदा और अनूठी कल्पना थी, जो अनुभवहीन होने बाद भी उसे पुरानी पार्टियों से अलग करती थी। राजनीति में 'स्वराज' पर अपनी पुस्तक में केजरीवाल सत्ता के जबरदस्त विकेंद्रीकरण की वकालत करते दिखते हैं। हममें से कुछ लोगों ने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से सहमत नहीं होने के बावजूद सोचा कि आप की विचारधारा का यह तत्व दिल्ली से बाहर की कुछ जगहों पर उभरते शहरी मध्य वर्ग को पसंद आ सकता है। स्थानीय जरूरतों के हिसाब से नए स्कूल खोलने का वादा और मोहल्ला क्लिनिक की योजना देखकर लगा कि विकेंद्रीकरण का एजेंडा वास्तव में लागू किया जा रहा है। ठीक तरीके से लागू होने पर इन योजनाओं ने भारतीय शासन के सबसे जमीनी स्तर पर सुधार किया होता और जवाबदेही पैदा की होती क्योंकि देश के प्रशासनिक ढांचे का यही पहलू बाकी सबके मुकाबले हमेशा नाकाम रहा है।

लेकिन इन मोहल्ला क्लिनिकों ने उस तरह का काम नहीं किया, जैसी योजना बनाई गई थी। कई जगह कर्मचारियों की कमी से ताले लग गए हैं तो कई क्लिनिकों में आए दिन दवा और सामान की कमी की शिकायत लगी रहती है। इन क्लिनिकों में कर्मचारियों और आसपास के लोगों के बीच बहस तथा लड़ाई भी देखने को मिली है। स्कूलों में भी उतना सुधार नहीं हुआ है, जितना होना चाहिए था। इधर क्लिनिकों पर ध्यान देने का मतलब यह भी नहीं है कि बड़े अस्पताल बनाए ही नहीं जाएं मगर यहां मोहल्ला क्लिनिक होने का नतीजा ऐसा ही दिख रहा है।

जी20 शिखर सम्मेलन के लिए नए सिरे से सजाई गई मध्य दिल्ली को छोड़ दें तो नई यातायात प्रबंधन प्रणाली से भी कोई फर्क आता नहीं दिखा है। जल निकासी और वायु गुणवत्ता पहले के मुकाबले ज्यादा बिगड़ी है। हवा खराब होने का दोष कुछ हद तक दूसरे राज्यों खास तौर पर पंजाब की सरकार पर डाला जा सकता है मगर जल निकासी दुरुस्त करना तो पूरी तरह दिल्ली सरकार की ही जिम्मेदारी है। आईआईटी दिल्ली ने शहर में जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने की योजना तैयार की है और उसी के मुताबिक व्यवस्था सही करने की कोशिश की जा रही थी मगर आप सरकार ने उसे बीच में ही छोड़ दिया। इसके बाद उसने नई योजना के साथ निविदा जारी कर दीं। नतीजतन हर साल बारिश के दिनों में शहर को बाढ़ जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है।

दिल्ली में अपने हिस्से का काम करने और उसे चमकाने के बजाय आम आदमी पार्टी खुद को राष्ट्रीय स्तर पर विकल्प बताने और प्रधानमंत्री के सामने मुख्य विपक्षी दल बताने का दम भरने लगी। नई पार्टी होकर भी इस तरह की कोशिश कर आप ने खुद को हंसी का पात्र ही बनाया है।

अंत में सामाजिक नीतियों के आधार पर भी इस सरकार का बचाव नहीं किया जा सकता। हम यह भी नहीं कह सकते कि इस सरकार के पास दिल्ली को उदार, समावेशी और बहु सांस्कृतिक माहौल वाला विश्वस्तरीय शहर बनाने का नजरिया है। इस दल के एक लोक सभा उम्मीदवार ने अपना नाम भी कथित रूप से इसीलिए बदल लिया क्योंकि वह नाम कुछ ज्यादा ही 'ईसाई' लगता था। उस पार्टी से और क्या उम्मीद की जा सकती है, जिसके एक वरिष्ठ नेता ने कभी दिल्ली में अप्रीकी नागरिकों पर छापे मारे हों?

आप वैसे ही पूरी तरह नाकाम साबित हुई है, जैसे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हुआ था। पिछले 15 साल में दिल्ली में थोड़ा ही बदलाव दिखा है और यह शहर शायद ज्यादा बुरी स्थिति में पहुंच गया है। दिल्ली देश की राजधानी है और आने वाले वर्षों में इसकी व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए आम आदमी पार्टी के पास क्या ठोस योजना है? इस सवाल का जवाब अगर उसके पास नहीं है तो समझ नहीं आता कि लोग उसे दोबारा क्यों चुनेंगे।

आपका पक्ष

इजरायल-हमास समझौता एक सकारात्मक कदम

इजरायल और फिलिस्तीन के बीच 15 महीनों से जारी संघर्ष के अंत की घोषणा विश्व शांति के लिए एक बड़ा कदम है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और फिलिस्तीन के बीच हुए समझौते से इस क्षेत्र में स्थिरता आने की उम्मीद है। यह समझौता अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण से कुछ दिन पहले हुआ है, जो वैश्विक राजनीति में एक महत्त्वपूर्ण संदेश देता है। इस युद्धविराम से कई सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। इससे न केवल निर्दोष नागरिकों को राहत मिलेगी, बल्कि पुनर्वास कार्य भी शुरू हो सकेगा। लोगों के अपने घरों को लौटने और सामान्य जीवन की बहाली की राह खुलेगी। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के नेतृत्व में यह निर्णय साहसिक और प्रशंसनीय है, जिसने कूटनीतिक वार्ता के महत्त्व को फिर से उजागर किया है। यह शांति समझौता एक उदाहरण है कि संवाद और सहमति से कठिन समस्याओं का हल संभव है। विश्व समुदाय को इस पहल का समर्थन करना चाहिए ताकि शांति और समृद्धि की ओर एक नई शुरुआत हो सके।

प्रो. आरके जैन, बड़वानी

इजरायल और हमास के बीच शांति समझौते के बाद अपने घर लौटते फिलिस्तीन के लोग

गाजा में शांति समझौता

गाजा में शांति समझौता मानवता के हित में उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है। अब इसका व्यावहारिक असर नजर आना चाहिए ताकि युद्ध और संघर्ष से पीड़ित लोग अपनी दिनचर्या में दोबारा लौट सकें। जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनके प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हुए जल्द से जल्द पुनर्वास कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। इस पर एक वैश्विक जिम्मेदारी तय करना चाहिए ताकि विस्थापितों को दोबारा बसाने के लिए और उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए पूरा विश्व एकजुट हो। अब रूस-यूक्रेन को भी शांति समझौते के लिए सहमत होना चाहिए। पश्चिमी देश हमेशा से युद्ध को बढ़ावा देने वाली परिस्थितियों का निर्माण करते हैं इसलिए अपने स्तर पर बातचीत से कोई रास्ता निकालना चाहिए। युद्ध का अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर देखने को मिलता है और देश की कार्य क्षमता प्रभावित होती है।

शेर सिंह मेरूपा, लाहौल-स्पीति

बुजुर्गों के लिए कानून

सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में दिए गए उस फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए, जिसमें कहा गया है कि अगर बच्चे, माता-पिता की देखभाल नहीं करते हैं, तो माता-पिता द्वारा दी गई संपत्ति की गिफ्ट डीड को रद्द किया जा सकता है। यह फैसला माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम के तहत दिया गया है। अगर किसी वरिष्ठ नागरिक को दुर्व्यवहार, बेदखली आदि के कारण गिफ्ट डीड को रद्द करने की जरूरत महसूस होती है, तो कानून में प्रावधान है, जिससे वे अपनी संपत्ति वापस ले सकते हैं। हालांकि अगर यह 29 दिसंबर, 2007 से पहले निष्पादित की गई हो तो वरिष्ठ नागरिक के पास इस अधिनियम के तहत कोई उपाय नहीं है। वे इसे अदालत में चुनौती दे सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि बहुत से वरिष्ठ नागरिक कानूनी उपचार नहीं चाहते हैं। इसके लिए कानून से परे अलग दृष्टिकोण की भी जरूरत है।

सुधीर कुमार सोमानी, देवास

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

भारतीय महिला टीम ने पहले खो-खो विश्व कप के फाइनल में रविवार को नई दिल्ली में नेपाल पर 78-40 की शानदार जीत के साथ खिताब अपने नाम किया।

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • सोमवार • 20 जनवरी • 2025
www.rashtriyasahara.com

न्याय पर सवाल

पश्चिम बंगाल के आरजी कर अस्पताल में रेप के बाद हत्या के मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय को निचली अदालत ने दोषी करार दिया है। यह फैसला बीते साल नवम्बर में शुरू हुई सुनवाई के लगभग दो महीने बाद और इस अपराध के 162 दिन बाद सुनाया है। संजय को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64, 66 व 103 (1) के तहत रेप व हत्या का दोषी पाया गया। सब न्यायाधीश ने कहा कि उसे बोलने का मौका दिया जाएगा। संजय का दावा है, उसे फंसाया गया है। मृतका के मां-बाप ने उसे दोषी ठहराए जाने से खुशी व्यक्त की। मगर दोहराया कि वह अकेला नहीं था, उसके साथ और भी लोग थे, जिन्हें सजा मिलने तक संघर्ष जारी रखेंगे। 9 अगस्त को अस्पताल के आपातकालीन

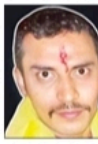

विभाग की चौथी मंजिल में पीड़िता का शव बरामद किया गया था। मामले में साक्ष्यों के आधार पर सीबीआई ने सिविक वालंटियर संजय रॉय को मुख्य आरोपी बनाया। इस वीभत्स घटना से पूरे देश में आक्रोश फैल गया। चिकित्साकर्मियों व डॉक्टरों समेत आम लोगों ने लंबे समय तक विरोध-प्रदर्शन भी किए। अदालत के अनुसार उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास मिल सकती है। जैसा कि मृतका के पिता ने कहा, अभी बहुत से सवालों के जवाब बाकी हैं क्योंकि जांच के दौरान खुलासा हुआ था कि घटना जितनी वीभत्स थी, उसमें अन्य लोग भी शामिल थे। हालांकि अस्पताल से जुड़े तमाम अन्य घोटालों व आर्थिक घपलों का भी खुलासा हुआ जिन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर दोषियों का पक्ष लेने जैसे गंभीर आरोपों के बाद अस्पताल प्रबंधन में मामूली फेरबदल करने सरीखी कवायद भले ही हुई मगर समस्याओं के समाधान का प्रयास होता नहीं नजर आया। तमाम कड़े कानूनों के बाद भी देश में महिलाएं प्रति दिन असुरक्षा भरे माहौल से जूझने को मजबूर हैं। कड़ी-बड़ी बातों के अतिरिक्त उन्हें कुछ नहीं मिलता। दोषी को कड़ी-से-कड़ी सजा होना स्वरित न्याय के प्रतिमान गढ़ने वाला साबित हो सकता है। मगर बाकी दोषियों पर हाथ डालने में कोताही क्यों हो रही है। सबसे नीचे के आरोपी पर कड़ी कार्रवाई कर लीपापोती की आदतों का प्रतिफलन है, गंभीर अपराधों में संलिप्त दोषियों का छुट्टा घूमते रहना। बात यहां रात्रि पाली में काम करने वाली महिलाओं तक सीमित नहीं है। यह हर नागरिक की सुरक्षा से जुड़ा मसला है। आपराधिक प्रवृत्ति वालों के प्रति पक्षपाती रवैया न्याय प्रणाली पर सवालिया चिन्ह लगाते हैं। जिससे बचना आवश्यक है।

जातीय जनगणना की हुंकार

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जातीय जनगणना कराए जाने की मांग को दोहराते हुए कहा कि उनकी पार्टी सत्ता में आने के बाद किसी भी कीमत जातीय जनगणना करवा कर रहेगी। बुधवार को पटना में 'संविधान सुरक्षा सम्मेलन' को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि इस बाबत उन्होंने संसद में भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में स्पष्ट कहा है कि संविधान को कमजोर करने और हाशिए पर पड़े समुदायों की अनदेखी नहीं करने दी जा सकती। राहुल आरोप लगा चुके हैं कि भाजपा और आरएसएस यह कृत्य कर रहे हैं। यह भी आरोप लगा चुके हैं कि संघ प्रमुख मोहन भागवत का 'सच्ची आजादी' वाला बयान 'देश के संविधान के खिलाफ है'। बेशक, आर्थिक प्रगति में समाज के हर हिस्से की भागीदारी होना जरूरी है। इसी से समावेशी समाज की परिकल्पना मूर्तिकार हो सकती है, लेकिन हकीकत यह है कि समाज का एक बड़ा हिस्सा प्रगति में हिस्सेदार नहीं बन सका है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने भी इस तरफ ध्यान दिलाया है। 'दलितों, अल्पसंख्यकों और सामाजिक रूप से हाशिए पर रह रहे समुदायों की आबादी देश की कुल जनसंख्या का नब्बे फीसद है, लेकिन वे व्यवस्था का हिस्सा नहीं हैं...यही कारण है कि हम जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं' यह ध्यान दिलाते हुए राहुल ने बिहार में की गई जाति आधारित गणना को 'फर्जी' करार दिया। कहा कि यह 'लोगों को बेवकूफ बनाने वाली है।' ऐसा है तो राहुल को सबसे पहले कांग्रेस शासित राज्यों और कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार शासित राज्य में भी जाति आधारित जनगणना कराई जानी चाहिए। बिहार में जातीय गणना की गई थी न कि जातीय जनगणना, लेकिन इस तकनीकी पचड़े में न भी पड़ें तो इतना तो साफ है कि जातियों और समुदायों की वास्तविक संख्या का आंकड़ा न होने पर उनके लिए कल्याणकारी कार्यक्रम और योजनाओं का क्रियान्वयन बेमानी रहता है, और ऐसा होता भी रहा है। शायद यह भी कारण रहा देश की संपत्ति में इन जातीय समूहों की हिस्सेदारी का आकलन आज भी हमारे पास नहीं है। कहना न होगा कि जातीय गणना या जातीय जनगणना-भले ही जो भी कहें-से ही हमें उन समूहों की सटीक संख्या मिल सकेगी जिन्हें लक्षित करके योजनाएं बनाकर क्रियान्वित की जा सकेंगी। समावेशी विकास तभी सुनिश्चित हो सकेगा।

क्रिकेट/के. विक्रम राव

रंग लाया था वानखेड़े का वार

तीव्र वर्ण संघर्ष के अंजाम में जन्में मुंबई के मशहूर वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम की 19 जनवरी 2025 स्वर्ण जयंती थी। पुराने ब्रेबोर्न स्टेडियम (1937) के पदाधिकारियों से अतिरिक्त टिकट मांगने पर झड़प के कारण मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने तय (1975) किया था कि उनका अलग से स्टेडियम बने। बंबई राज्य के अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड माइकेल ब्रेबोर्न (1939) के नाम पर रखा यह पुराना स्टेडियम तभी बे-रंगत हो गया। स्वाभिमान और स्वदेश प्रेम का परिणाम है वानखेड़े स्टेडियम।

यूं तो बंबई साक्षी है कि ब्रिटिश राज ने क्रिकेट द्वारा भी भारत के टुकड़े करने की साजिश रची थी। वहां गुलामी के दौर में पेंटागन (पंचकोणीय) क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित होती थीं। हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई और यूरोपियन टीमें सांप्रदायिक गुटों के रूप में भिड़ती थीं। अंग्रेजी उपनिवेशवाद की साजिश के तहत। हालांकि स्वाधीन भारत में ब्रेबोर्न स्टेडियम भारतीय था पर कुछ निहित हाथों में। तभी की बात (फरवरी 1973 की) है। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर और बंबई क्रिकेट एसोसिएशन अध्यक्ष शेषराव वानखेड़े और ब्रेबोर्न स्टेडियम के प्रबंधकों के बीच एक अंतरराष्ट्रीय मैच के टिकटों की साझेदारी पर विवाद हुआ। तब ब्रेबोर्न स्टेडियम के संचालक विजय मर्चेन्ट ने वानखेड़े से कहा, 'आप खुद अपना स्टेडियम क्यों नहीं बना लेते?' बात का बतंगड़ बना स्वदेश भक्ति ने जोर मारा। बस वानखेड़े के प्रयास का अंजाम है आज का भव्य नया स्टेडियम। निडर वानखेड़े ने स्टेडियम के मालिकों से ठान ली थी। अपनी बेहतरीन पिच के लिए मशहूर इस स्टेडियम ने 1948 से 1972 के बीच कई टेस्ट मैचों की मेजबानी की है। अध्यक्ष वानखेड़े का करिश्मा था कि इस नवनिर्मित स्टेडियम (1975) में वेस्टइंडीज से पहला मैच खेला गया था। श्रमिकों की करिश्माई मेहनत थी कि स्टेडियम वक्त पर तैयार हो गया। खुद विजय मर्चेन्ट (ब्रेबोर्न स्टेडियम वाले) जिन्होंने वानखेड़े की खिल्ली उड़ाई थी, केवल 1500 टिकट मांगने पर चकित होकर बोले, 'इतना बड़ा लक्ष्य इतने कम वक्त में?' यूं भी बंबई प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अठारवें अध्यक्ष स्वर्गीय शेषराव कृष्णराव वानखेड़े अध्ययनशील ज्यादा रहे। वे दलित महार जाति के थे। डॉ. अंबेडकर की तरह। उन्होंने इंग्लैंड से कानून की पढ़ाई की फिर भारतीय स्वाधीनता संघर्ष में गांधीजी के साथ हो गए। वानखेड़े नागपुर में मेयर तथा मध्य प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे।

प्रवासियों पर दारोमदार

विदेशी निवेश

डॉ. जयंतीलाल भंडारी

हाल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 9 जनवरी को ओडिशा के भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि इस समय जहां प्रवासी भारतीय भारत के विकास में बड़ा योगदान दे रहे हैं, वहीं भारत के टैलेंट का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। हमारे प्रोफेशनल दुनिया की बड़ी कंपनियों के जरिए ग्लोब में अपना अभूतपूर्व योगदान रहे हैं। वस्तुतः विदेशों में भारतीय प्रवासी भारत के राजदूत हैं, और अपने-अपने देशों में प्रभाव रखते हैं। ऐसे में भारत ने 2024 तक विकसित देश बनने का जो लक्ष्य रखा है, उसे पाने के लिए प्रवासी भारतीयों से सहयोग अपेक्षित है। अपेक्षा है कि वे भारत की विभिन्न परियोजनाओं में स्वयं निवेश करें और अपने विदेशी मित्रों को भी इसके लिए प्रेरित करें।

उल्लेखनीय है कि 18वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के बाद प्रवासी भारत के विकास में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) बढ़ाने के लिए प्रेरित हुए हैं। सम्मेलन में शामिल कई प्रवासी उद्यमी और कारोबारी कहते हुए दिखाई दिए कि वर्ष 2025 में भारतीय प्रवासियों से एफडीआई से संबंधित उजली संभावनाओं को मुट्ठी में लेने के लिए जरूरी होगा कि भारत विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने, नियामक बाधाएं हटाने, बुनियादी ढांचे के विकास, व्यापार-कारोबार में बेहतरी, निवेश की क्षेत्रीय सीमाओं को उदार बनाने, नियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, नौकरशाही संबंधी बाधाओं को कम करने और कॉरपोरेट को उनके विवादों को सुलझाने में मदद करने के लिए न्यायिक परिवेश बेहतर बनाने की डगर पर आगे बढ़े।

गौरतलब है कि प्रवासी भारतीयों ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जिसके मुताबिक देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का प्रवाह अप्रैल, 2000 से सितम्बर, 2024 तक 1000 अरब डॉलर को पार कर गया। खास तौर से चालू वित्त वर्ष 2024-25 में अप्रैल से सितम्बर, 2024 के दौरान 42.1 अरब डॉलर का विदेशी निवेश आया। यह निवेश 60 सेक्टर, 31 राज्य और केंद्रशासित क्षेत्रों में रहा है तथा एफडीआई का यह अब तक का रिकॉर्ड प्रवाह है। खास बात यह भी है कि 2014 के बाद से अब तक पिछले 10 वर्षों में 667.4 अरब डॉलर का एफडीआई आया है। भारत के आर्थिक विकास की यात्रा में एफडीआई का यह विशाल आकार बड़ी उपलब्धि है। यह वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में भारत के बढ़ते प्रभाव को भी दिखाता है। यदि हम भारत में एफडीआई के स्रोत देशों की ओर देखें तो पाते हैं कि भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत मॉरीशस रहा है। मॉरीशस ने कुल विदेशी निवेश में 25 प्रतिशत का योगदान

दिया है। सिंगापुर 24 प्रतिशत एफडीआई के साथ दूसरे स्थान पर है। अमेरिका 10 प्रतिशत निवेश के साथ तीसरे स्थान है। बड़े निवेशक देशों में नीदरलैंड्स, जापान और ब्रिटेन भी शामिल हैं।

भारत में जिन क्षेत्रों में विदेशी निवेश आकर्षित हुआ है, उनमें आईटी, फाइनेंशियल सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशंस, ट्रेडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट केंसल्टेंसी सहित सर्विस सेक्टर प्रमुख सेक्टर हैं। निस्संदेह देश को विदेशी निवेश का पसंदीदा देश बनाने में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, आर्थिक और वित्तीय सुधारों की अहम भूमिका है। इसमें दो मत नहीं हैं कि प्रवासी भारतीय इस बात से वाकिफ हुए हैं कि वैश्विक स्तर पर सुस्त बाजारों और चीन की आर्थिक रफ्तार सुस्त होने के बीच भारत ने विदेशी निवेश प्राप्त करने का अब तक शानदार मुकाम हासिल किया है। विनिर्माता और निवेशक चीन का विकल्प तलाश रहे हैं, और इस समय एशिया में अधिकांश निवेशकों को भारत से बेहतर कोई देश नहीं दिख रहा। देश की अर्थव्यवस्था की चाल में लगातार सुधार और विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफपीआई) से अच्छा निवेश प्राप्त होने की बदौलत भारतीय शेयरों में तेजी दर्ज की जा रही है। देश में शेयर बाजार ने शानदार प्रदर्शन किया है। विदेशी निवेश की बदौलत भारत विश्व में नई परियोजनाओं की घोषणा करने वाला तीसरा देश बन गया है, और अंतरराष्ट्रीय परियोजना वित्त सौदों में दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है।

निश्चित रूप से देश का बढ़ता मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देश में एफडीआई की बड़ी ताकत बन गया है। मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में चीन दुनिया में पहले स्थान पर है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी भारत 456 अरब डॉलर विनिर्माण मूल्य के साथ दुनिया में पांचवें स्थान पर है तथा भारत नया विश्व मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर अग्रसर है। भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जिस तरह सुविधाओं के साथ तेजी से बढ़ाया जा रहा है, उससे दुनिया भर के निवेशक भारत आने के लिए उत्सुक हैं। इस समय भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब इसे तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने और भारत को विकसित देश बनाने की डगर पर आगे बढ़ाने के लिए उद्योगपतियों द्वारा अहम भूमिका निभाई जा रही है। हम उम्मीद करें कि 2025 में सरकार प्रवासी भारतीयों और उनके विदेशी मित्रों से भारत के लिए अधिक एफडीआई प्राप्त करने के नये रणनीतिक प्रयास करेगी। एफडीआई के लिए भारत को पसंदीदा देश बनाए जाने की बहुआयामी संभावनाओं को साकार करने के लिए भी सरकार और अधिक प्रयास करेगी। हम उम्मीद करें कि 2025 में भारत की विशाल कौशल-प्रशिक्षित युवा आबादी नवाचार, तकनीकी और डिजिटल नवोन्मेषों के साथ भारत को दुनिया के विदेशी निवेशकों की नजरों में और अधिक पसंदीदा देश बनाने की डगर पर तेजी से आगे कदम बढ़ाएगी। हम उम्मीद करें कि 18वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के बाद अब 2025 में प्रवासी भारतीयों और उनके विदेशी मित्रों से अधिक एफडीआई प्राप्त होने, भारत की नई लॉजिस्टिक नीति और गति शक्ति योजना के कारगर कार्यान्वयन, नीतिगत सुधारों, उत्पादों के कारोबार के लिए सिंगल विंडो मंजूरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, श्रमिकों के नये दौर के अनुरूप शिक्षण-प्रशिक्षण के साथ-साथ विभिन्न आर्थिक और वित्तीय सुधारों से भारत दुनिया के पहले पांच सबसे पसंदीदा एफडीआई वाले देशों के ऊंचे क्रम पर रेखांकित होते हुए दिखाई देगा। इससे देश को 2047 तक विकसित देश बनाने की डगर पर आगे बढ़ने में भी मदद मिलेगी।

(लेख में विचार निजी हैं)

प्रवासी भारतीय इस बात से वाकिफ हुए हैं कि वैश्विक स्तर पर सुस्त बाजारों और चीन की आर्थिक रफ्तार सुस्त होने के बीच भारत ने विदेशी निवेश प्राप्त करने का अब तक शानदार मुकाम हासिल किया है। विनिर्माता और निवेशक चीन का विकल्प तलाश रहे हैं, और इस समय एशिया में अधिकांश निवेशकों को भारत से बेहतर कोई देश नहीं दिख रहा। विदेशी निवेश की बदौलत भारत विश्व में नई परियोजनाओं की घोषणा करने वाला तीसरा देश बन गया है

बुरी आदतें | श्रीराम शर्मा आचार्य

छोटी बुरी आदतों से लड़ाई आरंभ करनी चाहिए और उनसे सरलतापूर्वक सफलता प्राप्त करते हुए क्रमशः अधिक कड़ी-अधिक पुरानी और अधिक प्रिय बुरी आदतों से लड़ाई आरंभ करनी चाहिए। यह प्रयास देर तक जारी रहना चाहिए। लाखों योनियों के कुसंस्कार विचार मात्र से समाप्त नहीं हो जाते। मार खा कर अन्तःकरण के किसी कोने में जा छिपते हैं, और अवसर पाते ही छद्मावरों की तरह घातक आक्रमण करते हैं। इनसे सतत सजग रहने की आवश्यकता है। आजन्म यह सतर्कता अनवरत रूप से बरती जानी चाहिए कि कहीं वेखबर पाकर दुर्बुद्धि और दुष्प्रवृत्ति की घातें फिर न पनपने लगें। आत्म-निर्माण का तीसरा चरण इस प्रयोजन के लिए है कि श्रेष्ठ सज्जनों में गुण, कर्म, स्वभाव की जो विशेषताएं होनी चाहिए उनकी पूर्ति के लिए योजनाबद्ध प्रयत्न किया जाए। दुर्गुणों की प्रतिष्ठापना भी तो होनी चाहिए। कंटीली झाड़ियां उखाड़ कर साफ कर दी गईं, यह तो आधा ही प्रयोग पूरा हुआ। आधी बात तब बनेगी जब उस भूमि पर सुरम्य उद्यान लगाया जाए और उसे पाल-पोस कर बड़ा किया जाए। बीमारी दूर हो गई, यह आधा काम है। दुर्बल स्वास्थ्य को बलिष्ठता की स्थिति तक ले जाने के लिए जिस परिष्कृत आहार-विहार को जुटाया जाना है, उसकी ओर भी तो ध्यान देना चाहिए। आलस्य दूर करने की प्रतिक्रिया श्रमशीलता में समुचित रुचि एवं तत्परता के रूप में दृष्टिगोचर होनी चाहिए। प्रमाद से पिंड छूटा हो-लापरवाही और गैर-जिम्मेदारी हटा दी तो उसके स्थान पर जागरूकता, तन्मयता, नियमितता, व्यवस्था जैसे मनोयोग का परिचय मिलना चाहिए। मधुरता शिष्टता, सज्जनता, दुरदर्शिता, विवेकशीलता, ईमानदारी संयमशीलता, मितव्ययिता, सादगी, सहृदयता, सेवा भावना जैसी सत्प्रवृत्तियों में ही मानवी गरिमा परिलक्षित होती है। उन्हें अपनाने को स्वभाव का अंग बनाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहा जाना चाहिए। लोग धन उपार्जन को प्रमुखता देते हैं, उसी के लिए श्रम, संयम, मनोयोग लगाए रहते हैं। उत्कर्ष के इच्छुकों को सम्मति से अधिक महत्त्व सुगों की विभूतियों को देना चाहिए। परिष्कृत व्यक्तित्व वह कल्प वृक्ष है, जिस तक जा पहुंचने वाला भौतिक और आत्मिक, दोनों ही क्षेत्रों की सफलता प्राप्त करता है।

रीडर्स मेल

बीमा का सिकुड़ता साया

भारत में वैसे भी आबादी का बेहद छोटा हिस्सा बीमा कवरेज में रहा है लेकिन समय गुजरने के साथ इस कवरेज का साया सिकुड़ता ही जा रहा है। बीमा विनियमन एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) की 2023-24 के बारे में जारी ताजा रिपोर्ट से सामने आया है कि इस वित्त वर्ष में बीमा कवरेज में 3.7 फीसद गिरावट आई यानी इसके पहले वाले वित्त वर्ष में जिन लोगों ने बीमा करा रखा था, उनमें 3.7 फीसद लोग इसकी सुरक्षा के घेरे से बाहर हो गए। यह सामाजिक सुरक्षा के साथ-साथ बीमा व्यवसाय के लिए अशुभ संकेत कहा जा सकता है।

मनोज श्रीवास्तव, सुलतानपुर, उप्र

महिला श्रम की महत्ता समझी जाए

रोजा लक्जमबर्ग का कथन है, 'जिस दिन महिलाओं के काम का हिसाब होगा उसे दिन मानव इतिहास की सबसे बड़ी चोरी पकड़ी जाएगी'। बाकई यह कथन हजारों वर्षों से चली आ रही हमारी उस कुंठित सोच को उजागर करता है, जिसमें हम मानते हैं कि घरेलू श्रम कोई श्रम नहीं होता और गृहिणियों के कामों को मजाक में उड़ा देते हैं। आज आवश्यक है कि हम घरेलू महिलाओं के श्रम को भी सम्मान और सराहना दें क्योंकि कोई भी वेतन उनके काम के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता। हम उन्हें जितना अधिक सम्मान देंगे, उनके श्रम का सही अर्थों में वही पारिश्रमिक होगा। समाज में व्याप्त रूढ़िवादी सोच केवल काम के बदले वेतन मिलने को ही महत्वपूर्ण समझती है, और इस सोच में बदलाव की गहन आवश्यकता है।

नितिन रावत, ई मेल से

जीत समीकरण बिठातीं पार्टियां

दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप, कांग्रेस और भाजपा ने मुफ्त की योजनाओं की बाढ़ लगा दी है। आप ने महिला सम्मान एवं बुजुर्ग सम्मान योजना एवं पुजारी को 18000 रुपये महीने की घोषणा की है। कांग्रेस ने मासिक 8,500 बेरोजगारों के लिए, 300 यूनिट बिजली मुफ्त योजना, महिलाओं के लिए 2500 रुपये प्रति माह और 500 रुपये का गैस सिलेंडर देने का वादा है। भाजपा के संकल्प पत्र में महिलाओं के लिए 2500 रुपये, मुफ्त बिजली 300 यूनिट, गर्भवती महिलाओं के लिए 21000 रुपये और ऐसी ही योजनाओं की घोषणा की है। एक समय था, जब चुनाव में मुफ्त की योजना का कोई महत्त्व नहीं था। लेकिन उपभोक्तावादी संस्कृति के इस दौर में राजनीतिक दल मुफ्त की योजनाओं से जीत का समीकरण बना रहे हैं।

चंद्रेन्द्र कुमार जाटव, दिल्ली

जंग खत्म करने का समझौता

कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अलसानी ने गाजा में 15 महीने से जारी युद्ध को खत्म करने और कई इस्राइली बंधकों की रिहाई के लिए इस्राइल और हमास के बीच कतर की राजधानी दोहा में संघर्ष विराम समझौता होने की घोषणा की है। इस्राइल एवं हमास के बीच जंग की शुरुआत अक्टूबर, 2023 में हुई थी, जब हमास के आतंकी इस्राइल में घुस गए थे एवं उन्होंने हजार से अधिक लोगों की हत्याएं कर दी थी एवं 250 से अधिक लोगों को अगवा करके ले गए थे। अब जब इन दोनों के बीच में इस समझौते की घोषणा हुई है, तब यही विश्वास है कि इस्राइल एवं फिलिस्तीन तथा हमास के बीच में गाजा पट्टी में फिर से स्थाई शांति की स्थापना हो सकेगी।

एम एम राजावत ''राज', शाजापुर, मप्र

letter.editorsahara@gmail.com

हमारी लड़ाई सिर्फ भाजपा से ही नहीं है, बल्कि उस सिस्टम से है जिसमें संस्थाओं को कमजोर कर दिया गया है। महाराष्ट्र में एक करोड़ मतदाता एकाएक बढ़ जाना गंभीर चिंता की बात है। चुनाव आयोग मतदाता सूची साझा करने से क्यों इनकार कर रहा है। पारदर्शिता बनाए रखना उसका कर्तव्य है।

अभिषेक सिंघवी, पूर्व सांसद
@DrAMSinghvi

पेंगुइन | योगेश कुमार गोयल

जलवायु परिवर्तन की मार से त्रस्त

पेंगुइन ऐसा खूबसूरत पक्षी है जो पंखों के बावजूद उड़ नहीं पाता लेकिन पानी में वेहद तेज तैराक होता है। माना जाता है कि पेंगुइनों ने लाखों वर्ष पहले उड़ने की क्षमता खो दी थी। शक्तिशाली फ्लिपर्स और सुव्यवस्थित शरीर उन्हें बहुत अच्छा तैराक बनाते हैं। यह सबसे तेज तैरने और सबसे गहरा गोता लगाने वाली पक्षी प्रजाति है। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण तथा मानव गतिविधियों के कारण इस खूबसूरत पक्षी की कई प्रजातियां भी संकटग्रस्त हैं।

दुनिया भर में पेंगुइन की कुल 18 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो स्फेनिस्कीनाई उप-परिवार के अंतर्गत आती हैं। इनमें 'एडेली पेंगुइन', 'दक्षिणी रॉकहॉपर पेंगुइन' और 'मैकरोनी पेंगुइन' प्रमुख रूप से शामिल हैं। पेंगुइन की 18 प्रजातियों में से 11 प्रजातियां अब संकटग्रस्त अथवा विलुप्तप्रायः की श्रेणी में आती हैं। पेंगुइन की आबादी प्रति वर्ष खतरनाक दर से घट रही है, और दुनिया के अधिकांश लोग इस बात से इसीलिए अनजान हैं क्योंकि उन्हें अपने प्राकृतिक आवास में पेंगुइन देखने को नहीं मिलते। पेंगुइन की 72 प्रतिशत प्रजातियों की आबादी घट रही है, और 5 प्रजातियां लुप्तप्राय मानी जाती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि वेहतर सुरक्षा और संरक्षण उपायों को लागू नहीं किया गया तो इन प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है। आईयूसीएन ने पेंगुइन की अनेक प्रजातियों को संकटग्रस्त की श्रेणी में सूचीबद्ध किया है। यही कारण है कि पेंगुइन की सुरक्षा के लिए विभिन्न अंतरराष्ट्रीय और स्थानीय संगठन प्रयासरत हैं, और 2000 से प्रति वर्ष 20 जनवरी को 'पेंगुइन जागरूकता दिवस' भी मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य पेंगुइन के संरक्षण और उनके आवासों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यह दिवस पेंगुइन संरक्षण को बढ़ावा देने के प्रयास में पेंगुइन के आवासों की सुरक्षा पर जोर देता है।

जलवायु परिवर्तन के चलते वर्फकी चादर पिघलने और समुद्री तापमान में वृद्धि होने के कारण पेंगुइन के प्रजनन स्थल और भोजन के स्रोत प्रभावित हो रहे हैं। विषाक्त प्लास्टिक, मछली पकड़ने, तेल रिसाव, आवास विनाश और पर्यटन जैसी तेजी से बढ़ती मानवीय गतिविधियों के कारण भी पेंगुइन के आवासों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। समुद्र में 'लेपर्ड सील' और ऑर्का जैसे शिकारी भी पेंगुइन के लिए खतरा बनते हैं। पेंगुइन अपने बच्चों को

अंटार्कटिका की वर्फ पर पालते हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण वे खतरे में हैं। अमेरिका में 'सेंटर फॉर बायोलॉजिकल डायवर्सिटी' के जलवायु विज्ञान निदेशक शाय वुल्फ का कहना है कि पेंगुइन का अस्तित्व इस पर निर्भर करता है कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ सरकार क्या ठोस कदम उठाती है। अमेरिकी सरकार का मानना है कि जलवायु परिवर्तन इन पक्षियों के असफल प्रजनन का बड़ा कारण बन रहा है। वेडेल सागर में हैलीबे कॉलोनी दुनिया में एम्परर पेंगुइन की दूसरी सबसे बड़ी कॉलोनी है। इस कॉलोनी ने कई वर्षों तक समुद्री वर्फ की खराब स्थिति का सामना किया है। ऐसे में 2016 में सभी नवजात चूजे डूब गए थे, जिससे इनकी कॉलोनी को बहुत नुकसान हुआ था। इसीलिए अमेरिकी सरकार चेतावनी दे चुकी है कि एम्परर पेंगुइन को 'अर्जेंट क्लाइमेट एक्शन' की सख्त जरूरत है। हालांकि 'वाइल्ड लाइफ एजेंसी' का कहना है कि पिछले 40 वर्षों के उपलब्ध डेटा और अन्य सबूतों की जांच से सामने आया है कि पेंगुइन पर फिलहाल विलुप्त होने का तो खतरा नहीं है, लेकिन यदि तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो वह दिन भी दूर नहीं है। 'वाइल्ड लाइफ एजेंसी' द्वारा इस पक्षी को पर्यावरण समूह, सेंटर फॉर बायोलॉजिकल डायवर्सिटी द्वारा 2011 में लगाई गई एक याचिका की मदद लेकर 'ए डेंजर्ड स्पीशेज एक्ट' के तहत रखा गया है।

वहरहाल, बढ़ते तापमान के कारण समुद्री वर्फ पिघल रही है, जिससे पेंगुइन की प्रजनन और भोजन खोजने की क्षमता प्रभावित हो रही है। समुद्रों में प्लास्टिक और अन्य प्रदूषण पेंगुइन के लिए बड़ा खतरा बन रहे हैं। पेंगुइन अक्सर प्लास्टिक को भोजन समझ कर निगल लेते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। अत्यधिक मछली पकड़ने के कारण पेंगुइन के लिए भोजन की उपलब्धता कम हो रही है। पर्यावरणविद् जलवायु परिवर्तन के कारण अंटार्कटिका में रहने वाले एम्परर और एडेली पेंगुइन को लेकर तो वेहद चिंतित हैं क्योंकि उनका मानना है कि दो डिग्री तापमान परिवर्तन के साथ इन्हें आवास की गंभी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। पेंगुइन न केवल पृथ्वी की जैव विविधता का महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं, बल्कि समुद्री खाद्य श्रृंखला का भी महत्त्वपूर्ण अंग हैं, जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करते हैं। काले और सफेद रंग के उड़ने में असमर्थ पंख वाले खूबसूरत पेंगुइन पृथ्वी के सबसे प्यारे और अद्भुत जीवों में शुमार हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए सामूहिक प्रयास किए जाने जरूरी हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इन अद्वितीय पक्षियों की सुंदरता और विशिष्टता का आनंद ले सकें।

राष्ट्रीय सहारा
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया आबदी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 706-708, सहारा हाउस, नेहरू रोड, नई दिल्ली से प्रकाशित। । समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - सत्येन्द्र सिंह*।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23362368, 23362369, 23362371, 23362372, फैक्स - 23362370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750

सम्पादकीय

स्टेट से संघर्ष की राहुल गांधी की घोषणा आहतकारी

राहुल गांधी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। संप्रति लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं। उनसे अतिरिक्त शालीनता की अपेक्षा रहती है लेकिन हाल ही में उन्होंने एक खतरनाक वक्तव्य दिया है। उन्होंने कहा है कि, मैं भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ही नहीं लड़ रहा हूं, बल्कि मेरा संघर्ष भारतीय राष्ट्र राज्य से भी है। अंग्रेजी में देश के लिए 'स्टेट' शब्द का इस्तेमाल हुआ है। भारतीय परंपरा, इतिहास और संस्कृति में राष्ट्र का अस्तित्व बहुत प्राचीन है। इतिहास के वैदिक युग से लेकर आधुनिक काल तक राष्ट्र भाव को बढ़ाने की ही बातें राष्ट्रीय विमर्श में रही हैं। किसी शब्द का प्रयोग भिन्न-भिन्न संदर्भों में भी हो सकता है। लेकिन 'स्टेट' जैसे शब्द का अर्थ स्वत: स्पष्ट होता है। भारतीय संविधान की मूल धारा में स्टेट (राज्य) का अर्थ राजव्यवस्था है। संविधान भी राजव्यवस्था का अंग है लेकिन सर्वोपरि है। संवैधानिक संस्थाएं राजव्यवस्था का उद्देश्य पूरा करने की माध्यम हैं। न्यायपालिका एक संवैधानिक संस्था है। विधायिका और कार्यपालिका भी संवैधानिक संस्थाएं हैं। भारत के महालेखा परीक्षक (कैग) भी संवैधानिक संस्था हैं। निर्वाचन आयोग भी प्रतिष्ठित संवैधानिक संस्था है। ऐसी सारी संवैधानिक संस्थाओं का गठन संविधान के अनुरूप हुआ है। भारतीय राजव्यवस्था के सिद्धांतों, मान्यताओं, नियमों और विधियों से राष्ट्रजीवन की गतिशीलता है। भारतीय राज्य की सभी संस्थाएं स्टेट का हिस्सा हैं। राष्ट्र राज्य का अर्थ संप्रभु सत्ता है। भारत संप्रभु राष्ट्र राज्य है। भारत की धरती और आकाश तक इस संप्रभुता की गहन उपस्थिति है। यह संप्रभुता भारत के संपूर्ण जन गण मन के माध्यम से संविधान में प्रकट हुई है। स्टेट का सामान्य अर्थ राजव्यवस्था या राज्य हो सकता है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका स्टेट के अभिन्न अंग हैं। कोर्ट, कचहरी, विधायिका, कार्यपालिका सहित सभी घटक राजव्यवस्था के अविभाज्य अंग हैं। साधारण सिपाही और विभिन्न संस्थाओं में काम करने वाला लिपिक भी राजव्यवस्था का अंग हैं। राजव्यवस्था में किसी भी अंग से संघर्ष की घोषणा सामान्य अपराध नहीं है। मूलभूत प्रश्न है कि राहुल गांधी की लड़ाई आखिरकार किस स्टेट के विरुद्ध है? बेशक स्टेट राजव्यवस्था के सभी अंग अलग-अलग काम करते हैं। लेकिन वस्तुत: वे स्टेट नाम की संस्था के अभिन्न अंग हैं। भारत के प्राचीन काल में भी खूबसूरत राजव्यवस्था थी। वैदिक साहित्य में राजा के निर्वाचन की विधि मिलती है। राजा के निर्वाचन के समय उत्सव होते थे। ऐसे ही उत्सव में कहते हैं कि, हे राजा! हम आपको राष्ट्र की भूमि की रक्षा करने, कृषि और पशुपालन की व्यवस्था करने, नागरिकों के लिए शिक्षा का प्रबंध करने के लिए चुनते हैं। आगे कहते हैं, आप अजेय रहें, आपकी कीर्ति और यश फैले। हम आपका अभिषेक करते हैं। राजा की भी शपथ होती थी। राजा कहता था कि, मैं राष्ट्र की रक्षा करूंगा। कृषि और पशुपालन को विकसित करूंगा। इस देश को वैभवशाली बनाऊंगा। यदि मैं ऐसा न कर पाऊं तो मेरे सारे पुण्य नष्ट हो जाएं। भारत के सभी नागरिक राजव्यवस्था का संरक्षण पाते हैं। स्टेट का कर्तव्य राजव्यवस्था का संचालन व अनुशासन सुनिश्चित करना है। प्रश्न है कि राजव्यवस्था को नष्ट करने और उससे लड़ने का कोई भी प्रयास राजद्रोह के दायरे में आता है? माओवादी हिंसा करते हैं। निर्दोष मारे जाते हैं। स्टेट माओवादियों से यथानियम निपटता है। माओवादियों और स्टेट के बीच का युद्ध वस्तुत: स्टेट पर ही हमला है और राजद्रोह है। आतंकवादी देश के कई भूभागों में निर्दोष नागरिकों को मारा करते हैं। वे स्टेट की परवाह नहीं करते। स्टेट उनसे लड़ता है। संघर्ष करता है। पूर्वोत्तर के तमाम उग्रवादी संगठन भी इसी श्रेणी में आते हैं। स्टेट सभी हिंसक संगठनों से लड़ने को बाध्य है। राहुल गांधी किस स्टेट से लड़ने की बात कर रहे हैं? श्रीलंका के उग्रवादी संगठन लिट्टे ने राजीव गांधी को मारा था। ऐसे सभी संगठन व्यक्तियों को निशाना नहीं बना रहे थे, वे स्टेट से ही युद्ध कर रहे थे।

आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आप कई दिनों तक तो खूब कमेंगे। तब आप यह समझ रहते हैं कि आपके सौभाग्य के ऐसे सितारे चमे हैं, जब आपके जिंदगी बुरा होगी और दुःखों तक, आपके हिस्से कहते हैं तब आपका तनाव खत्म होगा। यह तो जिंदगी हमारा है और जीवन खुशी को खुशबुओं तक समाकलनाक जरूर को मजबूत करेंगे, बल्कि पारस्परिक संबंधों में भी, जब यह समाकलनाक नहीं संतुष्ट और बाधाएं से मुक्त प्रदान करेगा

मेष — सुबह का समय दोस्तों के साथ घूमने-फिरने, खान-पान एवं मनोरंजन में बीत सकता है। पार्टनरशिप काम में ध्यान रखें। व्यापार में ज्यादा लाभ की उम्मीद नहीं है। दोपहर के बाद आप को प्रतिकूलता का सामना करना पड़ सकता है।

वृष — स्वभाव में उग्रता हो सकती है, इसलिए वाणी पर संयम रखें। दोपहर के बाद आप आप मनोरंजन की ओर ज्यादा बढ़ेंगे। मित्रों और रिश्तेदारों के साथ प्रवास या पर्यटन का योग है। आज कोई महत्वपूर्ण डिसीजन आप ले पाएंगे।

मिथुन — दवाई खरीदने या अस्पताल की फीस पर आकस्मिक खर्च हो सकता है। आज दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास के साथ हर काम को आसानी से बना पाएंगे। गृहस्थ जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा।

कर्क — किसी तरह का आर्थिक लाभ भी हो सकता है। हालांकि, स्वास्थ्य को लेकर उतार-चढ़ाव बना रहेगा। गृह एवं संतान सम्बंधी शुभ समाचार आप को मिलेंगे। पुराने और बचपन के दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। मित्रों और प्रियपात्र के साथ मुलाकात सुखद होगी।

सिंह — व्यापार में किसी तरह का लाभ होगा। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। पूंजी निवेश में सावधानी बरतें। धार्मिक काम के पीछे धन खर्च हो सकता है। कोर्ट-कचहरी के विषय में संभलकर चलें।

कन्या — स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दोपहर के बाद पारिवारिक जीवन में इमोशंस का वातावरण बना रहेगा। आज कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। पिता से आपको लाभ होगा। ज्योतिष और आध्यात्मिक विषयों में आपकी रुचि बनी रहेगी। दोस्तों के साथ मुलाकात होगी।

तुला — आज के दिन बौद्धिक काम, नए सृजन और साहित्यिक गतिविधि आप उलझे रहेंगे। किसी धार्मिक यात्रा का आयोजन हो सकता है। व्यापार में लाभ का अवसर मिलेगा। आज आपको कार्यालय और व्यापार में थोड़ा संभलकर चलना होगा।

वृश्चिक — मित्रों का सहयोग भी आप को प्राप्त होगा। विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी। पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए निरर्थक वाद-विवाद न करें। धन और प्रतिष्ठा में हानि हो सकती है। आप की रचनात्मकता में सकारात्मक वृद्धि होगी।

धनु — अपनी वाणी और व्यवहार को संयमित रखना आपके ही हित में रहेगा। आज आपकी नौकरी और व्यवसाय में रुचि बढ़ेगी। आज स्वास्थ्य का ध्यान रखें। साथी कर्मचारियों का साथ मिलेगा। संतान की चिंता आपको हो सकती है।

मकर — आज वाणी पर संयम रखें। रिश्तेदारों के साथ किसी बात पर विवाद हो सकता है। आप की अपेक्षा व्यय अधिक रहेगा। किसी उलझन में दिन गुजरेगा। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। आप नए काम का आरंभ कर सकेंगे।

कुंभ — पारिवारिक और प्रोफेशनल दोनों ही क्षेत्रों में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। घर-परिवार में आनंद का वातावरण आप को खुश रखेगा। बहुत दिनों से अटके सरकारी कामों में सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है।

मीन — मानसिक रूप से आप में भावुकता की मात्रा अधिक रहेगी। किसी बात को लेकर ज्यादा विचलित ना हों। अपनी कल्पनाशक्ति से साहित्य-सृजन में आप नवीनता ला पाएंगे। सुख-शांति बनी रहेगी। व्यवसाय में सफलता प्राप्त होगी। आज का आपका दिन लाभकारी है।

आज का इतिहास — बढ़ता राजस्थान

20 जनवरी की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

- 1265 को संसद की पहली बैठक इंग्लैंड में हुई।
- अमेरिकी मामलों को सुलझाने के लिए स्पेन में 1503 में व्यापार बोर्ड का गठन हुआ।
- कलकत्ता में 1817 में हिन्दू कॉलेज की स्थापना।
- बोलीविया, पेरू की संयुक्त सेनाओं को 1839 में चिली ने पराजित किया।
- प्रथम अफीम युद्ध में चीन ने हांगकांग को 1841 में ब्रिटेन के हवाले किया।
- इंडोनेशियाई द्वीप सेलेब्स के वाटमपोन पर 1860 में डच सेना ने जीत हासिल किया।
- 'पर्ल हार्बर' को अमेरिकी सीनेट ने 1887 में नौसैनिक अड्डा बनाने की अनुमति दी।
- दुनिया में सबसे पहले बास्केट बॉल का खेल 1892 को आज ही के दिन खेला गया था।
- अमेरिका में नागरिक स्वतंत्रता संघ की 1920 में स्थापना।
- जापान और सोवियत संघ के बीच 1925 में सहयोग समझौता हुआ।
- 1942 में आज ही के दिन जापान ने बर्मा पर आक्रमण किया।
- अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने 1949 में अपनी चार सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की।
- दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम नीदरलैंड से 1950 में स्वतंत्र हुआ।
- मिस्र के शहर स्वेज नगर एवं इस्माएलिया पर 1952 में ब्रिटेन की सेना ने कब्जा किया।
- 1957 में पोलैंड में संसदीय चुनाव वामपंथी नेता गोलुल्का ने जीता।
- भारत के पहले परमाणु रिएक्टर 'अप्सरा' का 1957 को आज ही के दिन ट्रॉम्बे में उद्घाटन किया गया।
- 1957 में भारत द्वारा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाये जाने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय जहाज़ों को अपने यहाँ सुविधाएँ नहीं देने की घोषणा की।
- 'जॉन एफ केनेडी' ने 1961 में अमेरिका के 35 वें राष्ट्रपति पद की शपथ ली।
- 'सीट द बीटलेस' अमेरिका में 1964 में जारी हुआ।
- इराक के राष्ट्रपति आरिफ़ 1968 में हटा दिये गए।
- 'केंद्रशासित प्रदेश' के रूप में मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश का उदय 1971 में हुआ।
- भारतीय राज्य मेघालय की स्थापना 1972 में आज ही के दिन हुई थी।
- 1977 में सं.रा. अमेरिका के 39 वें राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर बने।
- अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर ने 1980 में मास्को ओलंपिक का बहिष्कार किया।
- होंडूरस जो मध्य अमेरिकी देश हैं उसमें सन 1982 में संविधान प्रभावकारी हुआ।
- जार्ज हर्बर्ट वाकर बुश ने 1989 को आज ही के दिन अमेरिका के 41 वें राष्ट्रपति पद की शपथ ली।
- बिल क्लिंटन द्वारा 1993 में संयुक्त राज्य अमेरिका के 42वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार गहन।

विशेष आलेख

डिजिटल युग में फेक न्यूज़ का ख़तरा अब धर्म के क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है

अशोक भाटिया

कुंभ मेले में स्नान की एक बड़ी चौकाने वाली घटना घटी। आचार्य प्रशांत के नाम से एक झूठा पोस्टर वायरल हुआ, जिसमें दावा किया गया कि उन्होंने कुंभ को अंधविश्वास बताया है। जांच में यह दावा पूरी तरह से फर्जी निकला। आचार्य प्रशांत ने ऐसा कोई बयान कभी नहीं दिया। लेकिन इस झूठी खबर के कारण हिंसा भड़क गई। मौके पर मौजूद पूर्व सैनिक मोहन सिंह ने बताया कि यह पूरी तरह से सुनियोजित षड्यंत्र था।कुछ लोगों ने पहले फर्जी पोस्टर वायरल किया और फिर कुंभ में वितरित की जा रही आचार्य प्रशांत द्वारा लिखित भगवद गीता, उपनिषद, महाभारत, दुर्गा सप्तशती, शिव सूत्र और रामायण जैसी पुस्तकों को जला दिया। इतना ही नहीं, पुस्तक वितरकों के साथ मारपीट भी की गई। इस फेक न्यूज़ के फैलाने में जयपुर डायलॉग्स के संजय दीक्षित, इंडिया स्पीक्स डेली के संजय देव और एबीपी न्यूज जैसे संस्थानों की संलिप्तता सामने आई है। डिजिटल युग में फेक न्यूज़ का ख़तरा अब धर्म के क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है।

कुंभ मेल का सफलता का देखते हुए कुंभ मेले के विरोधियों को उनकी हरकतों से पहचाना जा सकता है .कुछ समय पूर्व समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा था कि प्रयागराज में उतनी भीड़ नहीं है जितनी बताई जा रही है इसके अलावा 'हैलो, महाकुंभ में बम ब्लास्ट होगा...' वगैरह ऐसे कई फेक वीडियो फैलाये जा रहे है जिससे कुंभ विरोधियों की हताशा स्पष्ट झलकती है .

डिजिटल युग में फर्जी खबरें (फेक न्यूज) बड़ी चुनौती बनकर उभरी हैं, जिसमें जनता को गुमराह करने और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बाधित करने की क्षमता है। हालाँकि, गलत सूचना को संबोधित करने में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(डु) के तहत गारंटीकृत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को संतुलित करना आवश्यक है। चुनौती नागरिकों के असहमति व्यक्त करने या राय व्यक्त करने के अधिकार का उल्लंघन किए बिना गलत सूचना का मुकाबला करने में है। यह पवित्रता ही है जो समाचार को समाज में एक विशिष्ट स्थान प्रदान करती है। लेकिन फर्जी खबरों की परिघटना समाचार के मूल मूल्यों को निशाना बनाती है, जो असामाजिक तत्वों, अफवाह फैलाने वालों या उन उच्च और शक्तिशाली लोगों के निजी हितों को पोषित करती है, जो समाचार की आड़ में अपना निजी एजेंडा आगे बढ़ाते हैं। जब फर्जी खबरों को डिजिटल पंख लग जाते हैं, तो यह वायरल पत्रकारिता में बदल जाती है। यदि इसका दुरुपयोग किया जाता है, तो यह हिंसा और घृणा फैला सकती है, तबाही मचा सकती है और नागरिक समाज के लिए विनाशकारी साबित हो सकती है।

फैक्ट-चेकिंग संगठन समाचारों की पुष्टि करने और लोगों को फेक न्यूज़ के बारे में शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इन संगठनों को सरकार और मीडिया द्वारा प्रोत्साहित एवं समर्थित किये जाने की आवश्यकता है। ऐसी खबरें रोकने के लिए आजकल कुछ चैनलों व समाचारपत्रों के आजतक फैक्ट चेक न्यूज़ में किसी भी तरह का राजनीतिक या परिस्थितिजन्य भेदभाव न करते हुए किसी खबर को फैक्ट चेक के लिए चुनने में पूरी तरह से निष्पक्ष रहते हैं. फैक्ट चेक प्रक्रिया शुरू करने के लिए किसी दावे के चयन में पहला कदम दर्शकों से मिले अनुरोध को देखना होता है. संभावित सूचनाओं, दुष्प्रचार, संदिग्ध वायरल पोस्ट और गलत सूचनाओं, जैसे किसी सार्वजनिक हस्ती के विवादास्पद बयान आदि के लिए लगातार मेनस्ट्रीम और सोशल मीडिया पर नजर रखा जाता है. कौस भी तरह के उकसाने वाले हैशटैग या वायरल वीडियो, मीम्स, फेसबुक पेज और वॉट्सऐप जैसे मैसेजिंग ऐप के द्वारा पहुंच सकते हैं.एक बार जब फैक्ट चेक के लिए सामग्री तय हो जाती है, तो रिसर्च और जांच के लिए मौके पर जाकर क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाता है. फिर खबर तैयार करना और उसकी समीक्षा के लिए हम सत्यापित तथ्यों को देखते हैं और प्रासंगिक दृष्टिकोण के साथ ही सरल, सटीक और पारदर्शी तरीके से पेश करते हैं. फैक्ट चेक की खबर के प्रकाशन के बाद पाठकों और दर्शकों द्वारा स्टोरी पर या सोशल मीडिया के द्वारा की गई टिप्पणियों के रूप में मिले फीडबैक पर गहरी नजर रखी जाती है.

पत्र सूचना कार्यालय की माने तो उसकी तथ्य-परीक्षण इकाई ने नवंबर 2019 में अपनी स्थापना के बाद से अब तक गलत सूचना के 1,160 मामलों का भंडाफोड़ किया है। फेक न्यूज़ रोकने के लिए व्यक्तियों को अपने सोशल मीडिया उपयोग के लिये ज़िम्मेदारी लेने की आवश्यकता है। उन्हें असत्यापित समाचारों को साझा करने से बचने और ऑनलाइन कंटेंट पर विवेकपूर्ण दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता है।स्कूलों में और आम समाज में आलोचनात्मक सोच कौशल को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।लोगों को पढ़ी-सुनी गई बातों पर सवाल पूछ सकने और सूचना के विश्वसनीय स्रोतों की तलाश के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2020 में भारतीय दंड संहिता की धारा 505 के तहत 'फर्जी/झूठी खबर/अफवाह का प्रसार' करने वाले लोगों के विरुद्ध दर्ज मामलों की संख्या में 214% की वृद्धि हुई।भारत में फेक न्यूज़ के विरुद्ध सुदृढ़ कानूनी की ज़रूरत है, जबकि मीडिया संगठनों द्वारा तथ्य-परीक्षण को एक नियमित अभ्यास के रूप में अपनाने और अधिक से अधिक जन जागरूकता का सृजन करने की आवश्यकता है। भारत में फेक न्यूज़ पर अंकुश लगाने की राह में कई चुनौतियाँ है जैसे भारत की डिजिटल साक्षरता दर अभी भी कम है, जिससे फेक न्यूज़ का प्रसार आसान हो जाता है, क्योंकि लोगों के पास प्राय: समाचार स्रोतों की प्रामाणिकता को सत्यापित करने का कौशल नहीं होता है। फेक न्यूज़ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ समय पूर्व एक सख्त संदेश जारी किया था । उन्होंने लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि कुछ भी फॉरवर्ड करने से पहले 10 बार सोचें। पीएम ने कहा था कि फेक न्यूज बेहद खतरनाक है और इसके कई गंभीर परिणाम हो सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई एक फर्जी खबर भी बढ़कर राष्ट्रीय चिंता का विषय बनने की क्षमता रखती है, लिहाजा उन पर लगाम कसने के लिए देश को उन्नत

मुफ्त की रेवड़ियों का लोकतंत्र-केजरीवाल की 'फ्रीडम सेल'

प्रो. आर.के. जैन

आज का लोकतंत्र, विशेषकर भारत में, एक नए प्रकार के 'रेवड़ी स्टार्टअप' की अवधारणा पर आधारित हो चुका है। केजरीवाल का मुफ्त सेवा मॉडल अब राजनीति को नीतियों और विचारधाराओं के बजाय एक खतरनाक प्रतिस्पर्धा में बदल चुका है।- 'कौन कितनी ज्यादा मुफ्त रेवड़ियां बांट सकता है।' बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सेवाओं के बाद, अब किसानेयारों के लिए मुफ्त बिजली-पानी की गारंटी ने इस खेल को एक नया मोड़ दे दिया है। अब अगला कदम शायद 'मुफ्त वाई-फाई', 'मुफ्त सस्सुल योजना' या फिर 'नो-वर्क जॉब गारंटी' हो सकता है।

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री व आप पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल की राजनीति अब राजनीति के रंगमंच पर एक अनोखे नाटक की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। उनके 'मुफ्त की रेवड़ियां' मॉडल ने देश की सियासी धड़कनों को कुछ इस तरह तेज कर दिया है, मानो चुनावी मौसम में राजनीतिक गलियारों में कोई नया मसाला परोसा गया हो। ताजा घोषणाओं में किरायेदारों के लिए मुफ्त बिजली और पानी का प्रावधान किया गया है, जो आम आदमी की जेब को राहत देने वाला कदम नजर आता है। इस मुफ्तखोरी के लोकतांत्रिक उत्सव में, जहां जनता को सुविधाओं की मिठास परोसी जा रही है, वहीं यह सवाल अब भी अनुत्तरित है—इस खर्च का असली भार कौन उठाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह 'मुफ्त' की मिठास, अर्थव्यवस्था के भविष्य को खट्टा बना दे? राजनीति का यह नया रंग समाज में एक अस्वाभाविक मानसिकता को जन्म दे रहा है, जहां हर व्यक्ति बस यही सोच रहा है आखिर और कौन सी मुफ्त सुविधा मुझे मिल सकती है? यह दृश्य न केवल लोकतंत्र के असली उद्देश्य से दूर जा रहा है, बल्कि आने वाले समय में इसका असर हमारे सामाजिक ढांचे पर भी दिखाई देगा।

दिल्ली जैसे महानगर में, जहां हर दूसरा व्यक्ति किरायेदार है, इस घोषणा ने एक अनकहे तनाव को जन्म दे दिया है, जो मकान मालिकों और किरायेदारों के बीच बढ़ता जा रहा है। मकान मालिक अब चिंतित होंगे कि किरायेदार मुफ्त सेवाओं का लाभ उठाकर और भी निर्भीत हो जाएंगे, जबकि किरायेदार इसे अपनी 'मुफ्त छत' समझने में बिलकुल भी संकोच नहीं करेंगे। सवाल यह उठता है कि क्या यह राजनीति समाज को और भी ज्यादा खंडित करने का नया हथियार बन चुकी है? किरायेदारों के लिए यह घोषणा किसी सोने की चिड़िया के जैसे तोहफे से कम नहीं, वहीं मकान मालिक इसे एक नए बोझ और जिम्मेदारी के रूप में देख रहे हैं। भारत में अब चुनाव नीतियों और योजनाओं के बजाय मुफ्त सेवाओं के वादों के इर्द-गिर्द घूमने लगे हैं। यह सोचने वाली बात है कि जब सरकारें इन मुफ्त सेवाओं के लिए धन जुटाती हैं, तो इसका स्रोत आखिर है कहां से? अगर इस धन का सही इस्तेमाल शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के लिए किया जाए, तो समाज का व्यापक विकास संभव है। लेकिन 'रेवड़ी बाजार' की इस राजनीति ने दीर्घकालिक विकास और सशक्त भविष्य को पीछे धकेल दिया है। मुफ्त चीजें हमेशा आकर्षित करती हैं, क्योंकि ये हमारी मेहनत और जिम्मेदारी को कम करने का लुभावना रास्ता दिखाती हैं। लेकिन यह सोच दीर्घकालिक विकास की राह में गंभीर अड़चन डाल देती है। जब समाज मुफ्त सेवाओं का आदी हो जाता है, तो उसकी उत्पादकता और आत्मनिर्भरता पर गहरा असर पड़ता है। किरायेदारों को मुफ्त बिजली-पानी देने की केजरीवाल की घोषणा ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगली मुफ्त सेवा क्या होगी—क्या ये मुफ्त शिफ्ट पैकेज कभी खत्म होंगे? केजरीवाल की 'मुफ्तखोरी' वाली राजनीति ने दिल्ली ही नहीं, बल्कि पूरे देश में नेताओं के मन में भी एक नई प्रेरणा जगा दी है।

शख्सियत — बढ़ता राजस्थान

श्री मुकेश कुमार कायथवाल (वरिष्ठ आरएएस)

नमस्कार साथियों हमारी आज की शख्सियत कॉलम के स्टार हैं। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी श्री मुकेश कुमार कायथवाल। इनका जन्म कोटा जिले में 9 जनवरी सन1966 को हुआ। एज्यूकेशन वहीं से हुई और एम फिल व बीए के बाद सरकारी सेवाओं में आए। एक बात रखना चाहूंगा कि एक अच्छा अधिकारी होने से पहले हर शख्स को एक अच्छा इंसान होना जरूरी होता है। ऐसे ही मुकेश कुमार कायथवाल सर हैं। आज अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रथम अलवर पद को सुशोभित कर रहे हैं। इससे पूर्व वे उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक जयपुर वृत्त । उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक अलवर वृत्त । राजस्व अपील अधिकारी,अलवर। शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान जयपुर। निदेशक, सम्पदा क्रम शासन उप सचिव सम्पदा,सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान जयपुर। सहायक आयुक्त देवस्थान, जयपुर। आयुक्त , नगर परिषद झालावाड़। उपखण्ड अधिकारी, बसेड़ी धौलपुर। उपखण्ड अधिकारी, मलारना डूंगर सवाईमाधोपुर। उपायुक्त, नगर निगम जयपुर। आयुक्त, नगर निगम जयपुर। उपखण्ड अधिकारी, मारवाड़ जंक्शन पाली। उपखण्ड अधिकारी,जमवारामगढ़ जयपुर। उपखण्ड अधिकारी, भीनमाल जालौर। उप रजिस्ट्रार, पंजीयन विभाग जयपुर। उप रजिस्ट्रार, पंजीयन विभाग जयपुर। तहसीलदार, ब्यावर अजमेर। तहसीलदार, विराटनगर जयपुर। तहसीलदार, कोटा। तहसीलदार, श्री माधोपुर सीकर। तहसीलदार फुलेरा,जयपुर। तहसीलदार, चुनाव विभाग जयपुर। नायब तहसीलदार, जोहेर जयपुर जैसे पदों पर रहे। बहुत ही बेहतरीन इंसान हैं मुकेश जी सर। अपने वाहन में श्वानों के लिए दवाई साथ लेकर चलते हैं कोई भी बीमार श्वान यदि मिल जाए तो उसका उपचार करते हैं। इंसानियत की शानदार परिभाषा इनके व्यक्तित्व से देखने को मिलती है। दैनिक बढ़ता राजस्थान की टीम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है।

संपादक शर्मा

2025_020 — बढ़ता राजस्थान

Sudoku

6			1	8		3		
4	2	3	7				6	
	1		3	4				2
	9		6	7				
	5		4	1	9	6		3
3			5	2			1	
	8	4	2	5	7			6
		5	8	6		4		
7	6	1			4			

Ans_2025_019

6	2	3	8	5	7	1	9	4
5	8	9	1	4	6	2	7	3
4	1	7	9	2	3	5	6	8
3	7	2	4	1	8	9	5	6
9	5	6	3	7	2	8	4	1
8	4	1	5	6	9	3	2	7
2	3	4	6	8	5	7	1	9
1	9	5	7	3	4	6	8	2
7	6	8	2	9	1	4	3	5

कैसे खेलें

वर्ग को 1 से 9 तक अंकों से ऐसे भरें कि आड़ी व खड़ी पंक्ति के साथ ही 3 गुणा 3 के बॉक्स में 1 से 9 तक अंक आएं। कोई अंक दुबारा नहीं आए।

स्वत्वधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक श्रीमती कमलेश विजयवर्गीय द्वारा बढ़ता राजस्थान प्रिंटिंग प्रेस,हथीपाला रोड खरडवा,निम्बई रोक (राज.) से मुद्रित एवं 180/ 116 "शलिका" सेक्टर-18, प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर से प्रकाशित, संपादक-तनुजा पालीवाल । प्रधान संपादक-राम विलास विजयवर्गीय मो. 9414242258, 9214048888,जयपुर फोन नं.0141-2796794,795 रोक कार्यालय-बाईपास निम्बई, रोक फोन नं.01432-244881 निम्बई 01438-222201,202,203 अलवर कार्यालय-मेहताब सिंह का नोहरा,अलवर मो. 7733000123,कोटा कार्यालय-छावनी मेन रोड,कोटा मो.9414823448 । ई मेल-badhatarajasthan@yahoo.com *पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार